सूर्योदय 6:41 सूर्यास्त 5:29

आज का तापमान

शिमला	12.0 न्यू	22.0 अधि
धर्मशाला	13.0 न्यू	25.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	81,028.02
निफ्टी	25,030.35

सोना 1,41, 000 चांदी 1,87,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | शनिवार, 7 नवंबर 2026 | 22 कार्तिक, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 192, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं टूटेगी : फारूक अब्दुल्ला

एजेंसी, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार गिरने की अटकलों के बीच शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाराज विधायकों ने श्रीनगर में पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर मीटिंग की। इसमें सीएम उमर भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 'नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं टूटेगी। मैंने विधायकों की शिकायतें सुनी हैं, हम उन पर काम करेंगे। कुछ का समाधान तुरंत होगा, तो कुछ का धीरे-धीरे होगा।' नाराज विधायकों के नेता नजीर गुरेजी ने कहा, 'हमने पार्टी लीडरशिप के सामने अपनी शिकायतें रखी हैं, उन पर जल्द ध्यान दिया जाएगा।' 25 विधायकों की प्रमुख मांगों में सीएम के सलाहकार नासिर सोगमी को हटाना, डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी से सड़क निर्माण विभाग वापस लेना या उन्हें पद से हटाना और सरकार के लोगों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराना शामिल है।

बेंगलुरु में पत्नी-सास समेत ससुराल के सात सदस्यों की हत्या

एजेंसी, बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु में घरेलू विवाद के चलते एक कैब ड्राइवर ने अपनी पत्नी समेत उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी। मृतकों में 7 साल का बच्चा भी शामिल है। आरोपी की पहचान शेखर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, शेखर की शादी करीब 20 साल पहले सुनीता से हुई थी। दोनों के बीच सुनीता के मायके जाने को लेकर अक्सर विवाद होता था। सुनीता की मां और भाई भी उसका साथ देते थे। इसी बात से नाराज होकर शेखर ने पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची। आरोप है कि शेखर ने पहले अपनी पत्नी सुनीता की घर में सिलबट्टे से हत्या की और शव को कपड़े में लपेटकर नंदी हिल्स के पास फेंक दिया। इसके बाद उसने सुनीता का मोबाइल बंद कर दिया और पड़ोसियों को बताया कि वह घूमने गई है। अगले दिन उसने अपने दो सालों शिवकुमार और शंकर को पार्टी के बहाने घर बुलाया और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों की पत्नियों दिव्या और नलिनी, अपनी सास रूपवती और शिवकुमार के 7 साल के बेटे पुनीत को भी मार डाला।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.69 अरब डॉलर घटकर 717.06 अरब डॉलर पर पहुंचा

एजेंसी, नई दिल्ली। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अक्टूबर को समाप्त हफ्ते में 2.69 अरब डॉलर घटकर 717.06 अरब डॉलर रह गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया कि 30 अक्टूबर को समाप्त हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.69 अरब डॉलर घटकर 717.06 अरब डॉलर रहा है। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 1.27 अरब डॉलर घटकर 719.75 अरब डॉलर रहा था। आंकड़ों के मुताबिक 30 अक्टूबर को समाप्त हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 2.09 अरब डॉलर घटकर 591.12 अरब डॉलर रही। आरबीआई ने कहा कि इस दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य भी 55.9 करोड़ डॉलर घटकर 102.59 अरब डॉलर रह गया।

दिल्ली प्रदूषण पर कोई पाबंदी नहीं करेगी काम : सुप्रीम कोर्ट

कहा- हम जितने ज्यादा आदेश देंगे, नियमों का उल्लंघन उतना ही बढ़ेगा

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए वह जितने ज्यादा आदेश और पाबंदियां लगाएगा, उनका उल्लंघन उतना ही बढ़ेगा।

कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ सख्त नियम बनाने से प्रदूषण की समस्या हल हो सकती है? बेंच ने प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने और उनके व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत बताई। मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने की। कोर्ट दिवाली की छुट्टियों के बाद 16 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार और अन्य अधिकारियों की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि प्रदूषण रोकने के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों में नियम बनाए गए हैं। इनमें उद्योगों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण, निर्माण और तोड़फोड़ से उड़ने वाली धूल, सड़कों की धूल और पराली जलाना शामिल हैं।



◆ सिर्फ सख्त कानूनों से नहीं रुकेगा प्रदूषण, लोगों को जागरूक करना जरूरी

◆ प्रदूषण रोकने के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों में नियम बनाए गए हैं

उन्होंने कहा कि वीरवार को दिल्ली के कुल प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 14% थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में कुछ आदेश जारी करेगा। वहीं, सीनियर वकील अमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने कोर्ट को बताया कि प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी के आसपास बना हुआ है, यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति रोजाना 30 सिगरेट पी रहा हो।

पेरेंट्स की सैलरी से तय नहीं होगा आरक्षण का लाभ

सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएसी परीक्षाओं में ओबीसी क्रीमी लेयर आरक्षण पर केंद्र सरकार की संशोधन याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के तहत 'क्रीमी लेयर' तय करने का आधार केवल माता-पिता की सैलरी या आय को नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने कहा कि किसी उम्मीदवार को आरक्षण के दायरे से बाहर करने के लिए केवल वेतन को पैमाना मानना सही नहीं है। इसके लिए माता-पिता के सोशल स्टेटस और उनके पद की प्रकृति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

पटना में 3 शूटर ढेर, 20 मिनट चली मुठभेड़, पुलिस पर 24 राउंड फायरिंग



एजेंसी, पटना। पटना में शुक्रवार को पुलिस ने 3 अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया, सुबह करीब 4.30 बजे हुई मुठभेड़ में अपराधियों ने पुलिस पर 24 राउंड फायरिंग की। करीब 20 मिनट तक दोनों ओर से गोलीबारी हुई। जवाब में पुलिस की ओर से 18 राउंड गोलियां चलाई गईं।

◆ एसएचओ भी जख्मी; परिजनों का हंगामा-तोड़फोड़

जवाबी फायरिंग में राजा शर्मा, बबलू कुमार यादव और जेपी यादव घायल हो गए। अस्पताल पहुंचने से पहले तीनों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, तीनों पेशेवर शूटर थे और सुपारी लेकर मर्डर करते थे। मुठभेड़ में मनेर थाना के एसएचओ रजनीश कुमा भी जख्मी हुए हैं। उनके हाथ में गोली लगी है। घटना शेरपुर गंगा घाट के पास की है। मौके से एक देशी पिस्टल, दो देशी कट्टे बरामद हुए हैं। मारे गए आरोपियों के परिजन ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए अस्पताल में करीब 5 घंटे हंगामा किया। लोगों ने पुलिस के साथ हाथापाई की, पथराव किया और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। काफी मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए पटना एम्स भेजा है। राजद सांसद मीसा भारती ने भी कहा, एक जाति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पटना एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा ने बताया, क्राइम प्रिवेंशन के तौर पर पुलिस की यहां पर ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। इसी क्रम में एसटीएफ और जिला बल की टीम की अलग-अलग क्षेत्रों में गश्त चल रही थी। इसी दौरान जानकारी मिली कि यहां पर कुछ अपराधी आए हुए हैं, जिनका आपराधिक इतिहास था और वे शेरपुर में कोई बड़ी घटना करने जा रहे हैं। जब पुलिस की टीम यहां पहुंची, तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान एसएचओ मनेर और उनकी टीम के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई।

पंजाब में यात्रियों से भरी चलती ट्रेन में आग लगी, चार डिब्बे जले

एजेंसी, पटियाला। पंजाब में शुक्रवार दोपहर चलती कर्मभूमि एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। आग इंजन के साथ लगे जनरल डिब्बे में भड़की और देखते ही देखते ट्रेन के 4 जनरल कोच इसकी चपेट में आ गए। आग की चपेट में आए डिब्बों में यात्री सवार थे। इससे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। ट्रेन रुकते ही यात्री जान बचाने के लिए नीचे उतरकर खेतों की ओर भागने लगे। इस दौरान कई यात्रियों ने ट्रेन से छलांग भी लगा दी। घटना फतेहगढ़ साहिब के साधूगढ़ और पटियाला के सराय बंजारा रेलवे स्टेशन के बीच हुई। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन, दमकल विभाग और राहत टीमों को अलर्ट किया गया। रेलवे के अनुसार, ट्रेन नंबर 12508 कर्मभूमि एक्सप्रेस अमृतसर से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जा रही थी। हादसा दोपहर करीब सवा 1 बजे हुआ। सरकारी रेलवे पुलिस ने बताया कि कोच के पंखे में शॉर्ट सर्किट होने के कारण यह घटना हुई। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों को अब लेना होगा वीजा

एजेंसी, नई दिल्ली। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए 6 गैर-मुस्लिम समुदायों के लोगों को यहां रहने के लिए अब वीजा लेना होगा। इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं।

पहले इन लोगों को पासपोर्ट और वीजा, दोनों की अनिवार्यता से छूट मिली हुई थी। यह बदलाव उन लोगों पर लागू होगा, जो 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले भारत आए थे। इनमें बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के आए लोग और जिनके दस्तावेजों की अवधि खत्म हो चुकी है, वे भी शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन नियमों में नए संशोधन की अधिसूचना जारी की। इसमें पाकिस्तानी नागरिकों और भारतीय मूल के कुछ विदेशियों को पासपोर्ट रिन्यू कराने से राहत देने के साथ भारत, नेपाल और भूटान के बीच यात्रा के नियम भी स्पष्ट किए गए हैं।

पाकिस्तानी नागरिकों को पासपोर्ट नवीनीकरण में राहत

भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले भारत आए कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को पासपोर्ट नवीनीकरण से छूट दी है। यह राहत उन लोगों को मिलेगी, जो स्थायी रूप से भारत में रहने आए थे और राष्ट्रीय पहचान पत्र नहीं होने के कारण पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं करवा पा रहे थे। हालांकि, इसके लिए उन्हें लिखित आश्वासन देना होगा कि वे दोबारा पाकिस्तान नहीं लौटेंगे।

◆ पहले हिंदू-सिख समेत 6 समुदायों को छूट थी

दिल्ली में खान-पान के 40 नमूने एकत्र

100 किलोग्राम दूषित खाद्य सामग्री कराई नष्ट, आठ प्रतिष्ठानों को नोटिस

एजेंसी, नई दिल्ली। दीपावली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान तेज कर दिया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने उत्तर-पूर्वी, पूर्वी, शाहदरा, दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में मिठाई की दुकानों, डेयरियों और खाद्य निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य पदार्थों के 40 नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए, जबकि स्वच्छता मानकों में कमियां पाए जाने पर आठ प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए। वहीं, मंडोली एक्सटेंशन स्थित एक डेयरी में करीब 100 किलोग्राम दूषित खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई। विभागीय टीमों ने उत्तर-पूर्वी, पूर्वी और शाहदरा क्षेत्रों में निरीक्षण के दौरान खोया, पनीर, घी, कलाकंद, लड्डू, गुलाब जामुन और ड्राई फ्रूट गिफ्ट पैक सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के 22 नमूने लिए।

इस दौरान मंडोली एक्सटेंशन की एक डेयरी में दुर्गंधयुक्त खोया, रसगुल्ले तथा मच्छरों और मक्खियों से दूषित दूध पाया गया। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए करीब 100 किलोग्राम मानव उपभोग के अयोग्य खाद्य सामग्री नष्ट कराई।

खाद्य पदार्थों में मिलावट बर्दाश्त नहीं : रेखा गुप्ता



मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि त्योहारों की खुशियां तभी सार्थक हैं, जब हर परिवार तक पहुंचने वाली खाद्य सामग्री शुद्ध, सुरक्षित और स्वास्थ्य के अनुकूल हो। खाद्य पदार्थों में मिलावट, दूषित सामग्री की बिक्री और स्वच्छता मानकों की अनदेखी लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है। सरकार इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा विभाग को मिठाई की दुकानों, डेयरियों और खाद्य निर्माण इकाइयों की नियमित जांच करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल अनियमितताओं पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिससे दिल्लीवासियों को पूरे वर्ष और विशेष रूप से त्योहारों के दौरान भरोसेमंद एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

2030 हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए पंजाब तैयार : मुख्यमंत्री मान

एजेंसी, चंडीगढ़। मोहाली के बलबीर सिंह सीनियर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का खिताब अपने पास बरकरार रखा है।



इस ऐतिहासिक जीत और टूर्नामेंट के सफल आयोजन के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम मान ने कहा कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की सफल मेजबानी से पंजाब ने अपने खेल इतिहास में नया अध्याय लिखा है और राज्य अब 2030 हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस सफल आयोजन पर राज्यवासियों को बधाई दी। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पहली बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करना पंजाब की खेल यात्रा में ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह आयोजन दर्शाता है कि पंजाब बड़े वैश्विक खेल आयोजनों के लिए पूरी तरह सक्षम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में खेल ढांचे को मजबूत करने के लिए 1,744 करोड़ रुपए का विशेष बजट रखा गया है। सरकार के कार्यकाल में 6 नए एस्ट्रोटर्फ मैदान तैयार हो चुके हैं, 2 पर काम जारी है और ग्रासरूट स्तर पर 18 सिक्स-ए-साइड एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब ने 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से लेकर पेरिस ओलंपिक 2024 तक देश को 77 हॉकी ओलंपियन और 48 ओलंपिक पदक विजेता दिए हैं।

अगले महीने शुरू होगी 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना', पात्र महिलाओं को मिलेंगे 1,500 रुपए : सीएम सुक्खू

भारतेन्दु संवाददाता, चंबा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भरमौर विधानसभा क्षेत्र की मैहला ग्राम पंचायत में 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों, महिला मंडलों और युवक मंडलों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गांव में रात्रि ठहराव भी किया।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 'मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना' अगले महीने शुरू की जाएगी। मैहला पंचायत के 172 परिवारों को इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है। इसके तहत 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। एक परिवार की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। उन्होंने कहा कि मैहला में आगामी शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई स्कूल शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राकृतिक तरीके से उत्पादित जौ का समर्थन मूल्य 70 से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया है। वहीं, गाय के दूध का खरीद मूल्य 31 से बढ़ाकर 61 रुपए और भैंस के दूध का 46 से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया है। दूध उत्पादकों की प्रोत्साहन राशि भी 3 से बढ़ाकर 6 रुपए प्रति लीटर की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है तथा युवाओं को रोजगार देने के लिए भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाई गई है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है। इस अवसर पर विधायक नीरज नैय्यर, कृषि उपज मंडी समिति चंबा के अध्यक्ष ललित ठाकुर सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।



ईरान ने अमेरिका को 7 शर्तों वाला नया प्रस्ताव भेजा

एजेंसी, तेहरान। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध खत्म कराने की कोशिशों के बीच ईरान ने अमेरिका को नया परमाणु प्रस्ताव भेजा है।

यह प्रस्ताव कतर के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपनी 7 शर्तें पूरी होने के बाद ही परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करेगा और होर्मुज खोलेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिका इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। हालांकि, उन्होंने प्रस्ताव में शामिल शर्तों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी। अधिकारी ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर यह जानकारी दी।

योगी ने पुलिस विभाग में 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को वितरित किए नियुक्ति पत्र

अब कोई भाई-भतीजावाद नहीं, 25 करोड़ जनता ही परिवार



एजेंसी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित 4,543 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

इस अवसर पर उन्होंने दो टूक कहा कि उत्तर प्रदेश में अब भाई-भतीजावाद नहीं चलेगा। प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही हमारा परिवार है और सरकार सभी के साथ समान व्यवहार करेगी। नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। योग्यता और मेरिट के आधार पर प्रदेश के हर युवा को अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में भर्ती की स्थिति ऐसी थी कि आवेदन कोई करता था, परीक्षा कोई दूसरा देता था और नियुक्ति पत्र किसी तीसरे को मिल जाता था। भर्ती के नाम पर सैफई सिंडिकेट का बोलबाला था। हमारी सरकार ने उस व्यवस्था को समाप्त कर पारदर्शी चयन प्रक्रिया स्थापित की है। मुख्यमंत्री ने नवचयनित अभ्यर्थियों से सीधे संवाद करते हुए तीन सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि क्या आपमें से किसी को चयन के लिए किसी की सिफारिश कराने की नौबत आई ? क्या किसी ने आपसे किसी प्रकार का लेन-देन किया या धनराशि का प्रस्ताव रखा ? क्या किसी ने धौंस दिखाकर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसकी आज उत्तर प्रदेश में कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार नहीं आई होती, तो पारदर्शी और ईमानदार भर्ती प्रक्रिया संपन्न होना एक दिवास्वप्न जैसा होता। वर्ष 2003 से 2017 के बीच ऐसी अनेक नियुक्तियां हुईं, जिनमें आवेदन किसी ने किया, परीक्षा किसी और ने दी और नौकरी किसी तीसरे व्यक्ति को मिल गई। ऐसे कई मामले आज भी न्यायालयों में लंबित हैं।

राहुल गांधी हरियाणा आकर करें डिबेट, युवा मोर्चा अध्यक्ष भी पूछेंगे सवाल : नायब सैनी

कांग्रेस के पास आज जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं

एजेंसी, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दी गई बहस की चुनौती पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी हरियाणा आकर डिबेट कर सकते हैं।

इसके लिए प्रदेश में जगह उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी वहां मौजूद रहेंगे और राहुल गांधी से सवाल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ से केवल झूठ बोला जाए और फिर भागकर चले जाएं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर कांग्रेस को चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोई परेशानी है, तो उसे मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और अदालतों के दरवाजे भी खुले हैं। कांग्रेस वहां जाकर अपनी बात क्यों नहीं रखती? केवल घर बैठकर और लोगों को दिखाने के लिए आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास आज जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए वह वोट चोरी के नाम पर देश को गुमराह करने और लोकतंत्र तथा चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास कर रही है।

कांग्रेस शासन में बुजुर्गों को छह-छह महीने नहीं मिलती थी पेंशन



मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में बुजुर्गों को छह-छह महीने तक पेंशन नहीं मिलती थी। बुजुर्गों को अपनी पेंशन के लिए परेशान होकर सरकारी दफ्तरों और नेताओं के दरवाजों के चक्कर काटने पड़ते थे। कांग्रेस के नेता आज वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन उन्हें अपने शासनकाल में गरीबों, बुजुर्गों और जरूरतमंदों के साथ किए गए व्यवहार का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के समय गरीब व्यक्ति को 200 रुपए का लाभ पहुंचाने की बात होती थी, लेकिन उसमें से 150 रुपए कहां चले जाते थे, इसका किसी को पता नहीं चलता था और गरीब के हाथ में केवल 50 रुपए आते थे।

समारोह केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तराखंड पुलिस को प्रदान किया राष्ट्रपति निशान, अधिकारियों को पदकों से किया सम्मानित

असम, हरियाणा के बाद देवभूमि में लगाएंगे हैट्रिक : अमित शाह

एजेंसी, देहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून की पुलिस लाइन में आयोजित उत्तराखंड पुलिस के राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में शामिल हुए।

इस दौरान उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया गया। समारोह में पुलिस बल की उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के लिए दो अधिकारियों को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और तीन अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड पुलिस के राष्ट्रपति निशान की स्मृति में भारतीय डाक विभाग की ओर से विशेष कवर भी जारी किया गया। इससे पहले अमित शाह ने परेड ग्राउंड में भाजपा की जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए '65 पार' का नारा देते हुए कहा कि असम और हरियाणा के बाद अब उत्तराखंड में भी भाजपा हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कांग्रेस की 'वोट बचाओ यात्रा' पर निशाना साधते हुए इसे 'घुसपैठिया बचाओ यात्रा' बताया। शाह ने यूसीसी लागू करने, 35 हजार से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने, पर्यटन में 380% वृद्धि और 1,508 करोड़ रुपए के 63 विकास कार्यों को प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताया। उन्होंने अवैध मजारों और मदरसों को हटाने की कार्रवाई का भी जिक्र किया।



◆ कहा- उत्तराखंड में 1508 करोड़ के 63 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन हुआ

अमित शाह ने देहरादून में कहा कि राज्य में 1508 करोड़ रुपए की लागत से 63 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया गया है। उन्होंने बताया कि समारोह में 15 लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान, 6 लोगों को बाल वीरता पुरस्कार और 2 लोगों को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। शाह ने कहा कि भाजपा सरकार उत्तराखंड के विकास में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने में गौरव महसूस करती है। उन्होंने दावा किया कि 2022 से अब तक राज्य की जीडीपी में 50% की वृद्धि हुई है।

सीएम धामी बोले- उत्तराखंड पुलिस ने 4 साल में 7 हजार से ज्यादा आरोपी किए गिरफ्तार

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस के 26 हजार से अधिक जवान प्रदेश की सेवा कर रहे हैं।

कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा और चारधाम यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की अहम भूमिका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी 14% तक पहुंच गई है। वहीं, ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पिछले 4 साल में 7 हजार से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 307 करोड़ रुपए से ज्यादा के मादक पदार्थ जब्त किए गए। धामी ने ऑपरेशन स्माइल और ऑपरेशन मुक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि इनके जरिए गुमशुदा बच्चों को परिवारों से मिलाने और भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने यूसीसी, धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून लागू किए हैं। साथ ही 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है। वहीं, उन्होंने कहा कि अमित शाह ने साबित किया है कि जब नेतृत्व में निर्णय लेने का साहस और लक्ष्य राष्ट्रहित हो, तो बड़े से बड़े संकल्प पूरे किए जसकते हैं।



बीबीएमबी मामले में हिमाचल की ऐतिहासिक जीत

दो दशक तक सालाना मिलेगी 60 करोड़ यूनिट बिजली, विकास कार्यों को मिलेगी गति

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से संबंधित एरियर और प्रदेश के वित्तीय अधिकारों के मामले में हिमाचल प्रदेश को सर्वोच्च न्यायालय से मिली सफलता को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला प्रदेश की जनता की जीत है और हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। इस व्यवस्था के तहत प्रदेश को अगले 20 वर्षों तक प्रतिवर्ष 60 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त होगी। इससे राज्य को इस अवधि में लगभग 10 हजार करोड़ से 20 हजार करोड़ रुपये तक की आय होने का अनुमान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति, ईमानदार प्रयासों और लगातार की गई कानूनी पैरवी के परिणामस्वरूप हिमाचल को उसका जायज हक दिलाने की दिशा में यह बड़ी सफलता मिली है। इस फैसले से प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त आय प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि बिजली



की दर यदि 13 से 14 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित होती है तो प्रदेश को और अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा। वहीं, दर छह रुपये प्रति यूनिट रहने पर भी राज्य को प्रतिवर्ष कम से कम 500 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।

सुक्खू ने कहा कि अतिरिक्त राजस्व प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और विकासात्मक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे राज्य सरकार को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने इसे प्रदेश के आर्थिक हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के अधिकारों से जुड़े मामलों में यह चौथी बड़ी सफलता है। इससे पहले सरकार ने वाइल्डफ्लावर हॉल, जेएसडब्ल्यू और किशाऊ बांध से संबंधित मामलों में हिमाचल के हितों की मजबूती से पैरवी की है। अब बीबीएमबी एरियर के मामले में मिली उपलब्धि ने प्रदेश के अधिकारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को फिर साबित किया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने इन मामलों में प्रदेश के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार प्रयास किए हैं। राज्य के संसाधनों और उनसे मिलने वाले लाभों पर हिमाचल का उचित अधिकार सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगी। शानन पावर प्रोजेक्ट और वाटर सेस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्य सरकार प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रख रही है। इन मामलों में भी हिमाचल को उसका जायज हक दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश के संसाधनों से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण मामले में सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर खर्च होगी अतिरिक्त आय

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की लगभग 75 लाख जनता और 24 लाख परिवारों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार को मिलने वाले अतिरिक्त राजस्व का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे के विकास और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को समय पर वित्तीय लाभ उपलब्ध करवाने में भी इस राशि का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने उन्हें पांच वर्षों के लिए हिमाचल के संसाधनों और संपदा का संरक्षक बनाया है। वह पूरी निष्ठा, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना और प्रदेश के हितों की रक्षा करना है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और प्रदेश के अधिकारों की लगातार पैरवी करने के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध एवं खुशहाल राज्य बनेगा।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उबादेश को दी दो सड़कों की सौगात, स्वास्थ्य केंद्र की रखी आधारशिला

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के उबादेश क्षेत्र के प्रवास के दौरान दो महत्वपूर्ण सड़कों का लोकार्पण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत नगान में 1 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से निर्मित लगभग साढ़े चार किलोमीटर लंबी मुंडाढांक-मणोंन नाला-ओजड़-कराल (लम्बीधार-कराल) सड़क का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने इसी पंचायत में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन की आधारशिला रखी। इस भवन के निर्माण पर 75 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

◆ कलबोग मार्ग का निर्माण पांच दशक बाद पूरा स्तरोन्नयन के लिए नाबार्ड को भेजा प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री ने कहा कि आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण पूरा होने से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होंगी। स्थानीय लोगों को अपने घर के नजदीक ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि दान करने वाले स्थानीय निवासी नंदलाल हांगटा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि नंदलाल हांगटा ने सामाजिक हित में भूमि दान कर सराहनीय योगदान दिया है और क्षेत्र के लोगों के सामने एक मिसाल पेश की है।

इसके बाद रोहित ठाकुर ने ग्राम पंचायत कलबोग के अंतर्गत 1 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से निर्मित मेलठ-क्यूनल-कलबोग सड़क का लोकार्पण किया। यह सड़क उबादेश क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में शामिल है। इसका निर्माण कार्य 1960 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन भूमि संबंधी अड़चनों के कारण यह लंबे समय तक अधूरा रहा। करीब पांच दशक बाद इस सड़क का काम पूरा हो सका है।

शिक्षा मंत्री ने क्षेत्रवासियों को सड़क की सुविधा मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि यह मार्ग स्थानीय लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। गुम्मा-बाघी सड़क की तरह यह मार्ग भी उबादेश क्षेत्र के लिए आवागमन का एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क के स्तरोन्नयन के लिए 4 करोड़ 76 लाख रुपये का प्राक्कलन तैयार कर नाबार्ड को भेजा गया है। इसके पूरा होने से क्षेत्र में यातायात की सुविधा और बेहतर होगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जुब्बल-नावर-कोटखाई क्षेत्र में 206 नई सड़कों की पासिंग की गई है। इसके अलावा 850 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सड़क और भवन निर्माण परियोजनाओं पर खर्च की जा रही है। इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

जुब्बल-कोटखाई में 206 नई सड़कों को मिली मंजूरी

रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है और यहां के दूरदराज क्षेत्रों में सड़कें विकास की प्रमुख आधारशिला हैं। जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र बागवानी बहुल है, इसलिए सड़क नेटवर्क का विस्तार स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। बागवानों को सेब सहित अन्य उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में बेहतर सड़क सुविधाओं से मदद मिलती है।

कलबोग स्कूल के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की

शिक्षा मंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलबोग का निरीक्षण किया और वहां 4 करोड़ 76 लाख रुपये की लागत से निर्माणाधीन शैक्षणिक ब्लॉक के कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस भवन का निर्माण 31 मार्च, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तैयार होने से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

पेंशन भुगतान के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य

मुख्यमंत्री सहारा योजना के लाभार्थी छह माह के दस्तावेज पोर्टल पर करें अपलोड

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त करने के लिए सभी पात्र लाभार्थियों को अपने बैंक अथवा डाकघर बचत खातों की आधार सीडिंग करवाना अनिवार्य है। जिला कल्याण अधिकारी शिमला कपिल देव शर्मा ने पेंशनधारकों से अपील की है कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपने खातों को आधार से लिंक नहीं करवाया है, वे जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें।

उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पात्र लोगों को पेंशन की राशि ऑनलाइन माध्यम से उनके आधार सीडेड बैंक और डाकघर बचत खातों में भेजी जा रही है। ऐसे में आधार सीडिंग पूरी नहीं होने पर पेंशन भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। सभी लाभार्थी समय रहते अपने संबंधित बैंक या डाकघर में जाकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें।

जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि विभाग



की ओर से संचालित मुख्यमंत्री सहारा योजना के लाभार्थियों को भी योजना का निरंतर लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल और सितंबर माह में आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इसके तहत नवीनतम छह माह का जीवन प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। चिकित्सा प्रमाण पत्र में लाभार्थी के दीर्घकालीन उपचार का उल्लेख होना चाहिए। इन सभी दस्तावेजों को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

शिमला में 20 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े आरोपी की जमानत याचिकाएं हुईं खारिज

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला में 20 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए 36 वर्षीय आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली है। विशेष न्यायाधीश शिमला ने आरोपी लखविंदर सिंह की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। आरोपी के खिलाफ बालूगंज पुलिस थाने में मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने अदालत में आरोपी को जमानत दिए जाने का विरोध किया था।



◆ एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में अदालत ने राहत देने से किया इनकार

पुलिस के अनुसार, आरोपी लखविंदर सिंह पुत्र जसवीर सिंह के कब्जे से 19 अक्टूबर को 20 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। इस बरामदगी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने संबंधित साक्ष्य जुटाए और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की। इसके बाद आरोपी की ओर से अदालत में जमानत याचिकाएं दायर की गईं। जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी को राहत दिए जाने का विरोध करते हुए मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखा। पुलिस का पक्ष सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। इस फैसले के बाद आरोपी को फिलहाल अदालत से जमानत नहीं मिल सकी है।

हिमाचल में दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों को पिछली कक्षा में नहीं मिलेगा दाखिला

एसएलसी में दर्ज कक्षा के आधार पर देना होगा प्रवेश, टेस्ट से नहीं घटेगा ग्रेड

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला



हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों को अब स्कूलों में निचली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। उन्हें स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) में दर्ज कक्षा के अनुसार ही दाखिला देना अनिवार्य होगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर सरकारी और निजी स्कूलों में आदेशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

शिक्षा निदेशालय ने यह फैसला विद्यार्थियों की शैक्षणिक निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है। विभाग के सामने ऐसे मामले आए थे, जिनमें दूसरे राज्यों से हिमाचल आने वाले विद्यार्थियों को एसएलसी में दर्ज कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। कुछ स्कूल दाखिले से पहले विद्यार्थियों की परीक्षा लेते थे और प्रदर्शन कमजोर होने पर उन्हें पिछली कक्षा में बैठा देते थे। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी।

निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली की ओर से जारी पत्र में सभी उपनिदेशकों को आदेशों की जानकारी सरकारी और निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों तथा मुख्याध्यापकों तक पहुंचाने को कहा गया है। अब केवल पढ़ाई में अंतर या पाठ्यक्रम पूरा न होने के आधार पर विद्यार्थी की कक्षा कम नहीं की जा सकेगी।

यदि किसी विद्यार्थी के पास स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा।

चिड़गांव में अवैध पटाखे रखने पर दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। दीपावली के मद्देनजर पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री के खिलाफ शिमला पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी अभियान के तहत पुलिस थाना चिड़गांव की टीम ने बाजार में एक जनरल स्टोर की तलाशी लेकर पटाखों के चार बॉक्स बरामद किए। दुकानदार पटाखों के भंडारण और बिक्री से संबंधित वैध लाइसेंस या परमिट प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने बरामद पटाखों को नियमानुसार कब्जे में लेकर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



पुलिस के अनुसार, पांच नवंबर 2026 को चिड़गांव बाजार में नियमित गश्त के दौरान टीम ने पूजा रोड स्थित लक्ष्मी जनरल स्टोर की तलाशी ली। इस दौरान दुकान से पटाखों के चार बॉक्स मिले। यह दुकान चिड़गांव निवासी शुभम सूद की है। पुलिस ने दुकानदार से पटाखों के भंडारण और बिक्री के लिए आवश्यक वैध दस्तावेज दिखाने को कहा, लेकिन वह कोई लाइसेंस या परमिट प्रस्तुत नहीं कर पाया।

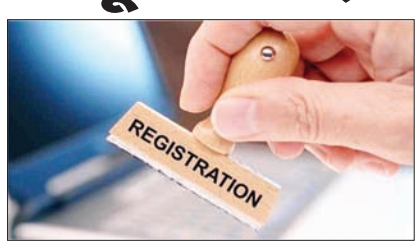
इसके बाद पुलिस थाना चिड़गांव में अभियोग संख्या 117/2026 के तहत पांच नवंबर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 और 288 तथा विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने पटाखों को कब्जे में लेकर आगामी अन्वेषण शुरू कर दिया है। मामले में बरामद सामग्री और उसके भंडारण से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। जिला पुलिस शिमला ने दीपावली के दौरान पटाखों के अवैध भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसके तहत जिले के विभिन्न बाजारों और क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है।

बद्दी की हवा हुई खराब, एक्यूआई 227 तक पहुंचा, पटाखों पर सख्ती

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में त्योहारी सीजन के बीच वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ने लगा है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 227 दर्ज किया गया, जबकि दो नवंबर को यह 200 था। पांवटा साहिब में भी एक्यूआई 123 तक पहुंच गया है। बद्दी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। प्रदेश सरकार ने दिवाली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत निर्धारित समय में ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को पटाखों के इस्तेमाल पर निगरानी रखने तथा निर्धारित नियमों की अनुपालना करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। त्योहारों के दौरान पटाखों से होने वाले धुएं और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। बद्दी और पांवटा साहिब में बढ़ते एक्यूआई के बीच प्रशासन के सामने वायु गुणवत्ता बनाए रखना चुनौती है। लोगों से भी निर्धारित समय और नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

बिना पंजीकरण नहीं चलेंगे शिमला के निजी स्कूलों में ईसीसीई केंद्र

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला शिमला में छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) प्रदान करने वाले सभी निजी विद्यालयों और संबंधित केंद्रों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इनमें प्ले स्कूल, नर्सरी, किंडरगार्टन और इस तरह की अन्य संस्थाएं शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा केंद्र (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2017 और इसके क्रियान्वयन के लिए 17 मार्च, 2026 को अधिसूचित नियमों के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है।



जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिमला ममता पॉल ने सभी निजी विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों से अपने यहां संचालित ईसीसीई केंद्रों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण करवाने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग या किसी अन्य बोर्ड से विद्यालय की मान्यता प्राप्त होना ईसीसीई अधिनियम के तहत अलग पंजीकरण का विकल्प नहीं है। अधिनियम के निर्धारित अपवादों को छोड़कर निजी क्षेत्र में संचालित संबंधित संस्थानों को पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण व्यवस्था का उद्देश्य संस्थानों को नियमन के दायरे में लाने के साथ छोटे बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाना है। इसके तहत प्रशिक्षित स्टाफ, आयु के अनुरूप पाठ्यक्रम, खेल एवं शिक्षण सामग्री, स्वच्छ पेयजल, बच्चों के अनुकूल शौचालय, प्राथमिक उपचार और निर्धारित वयस्क-बाल अनुपात जैसे मानकों का पालन जरूरी होगा। पात्र निजी विद्यालय और ईसीसीई केंद्र महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हिमसेवा पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

एक महीने के भीतर निरीक्षण करने के निर्देश

जिला के प्रत्येक विकासखंड में पंजीकरण व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए खंड स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। उपायुक्त शिमला की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन मिलने के एक महीने के भीतर संबंधित समिति संस्थान का निरीक्षण और भौतिक सत्यापन पूरा करे। निरीक्षण में सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और निर्धारित मानकों की जांच की जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाएगी। जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी पात्र संस्थानों से नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। संचालकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय रहते आवेदन करना होगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

कांगड़ा-चंबा में भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा जिलों में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। भूकंप सुबह 6 बजकर 59 मिनट पर आया और इसका केंद्र जमीन के भीतर करीब 15 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया। फिलहाल किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। कांगड़ा और चंबा जिले हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने के कारण भूकंपीय गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं। यहां समय-समय पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण भूकंप आते रहते हैं। कांगड़ा का इतिहास 4 अप्रैल 1905 को आए विनाशकारी भूकंप से जुड़ा है। उस समय करीब 7.8 तीव्रता के भूकंप ने कांगड़ा, धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई थी। हजारों इमारतें ढह गई थीं और 18 हजार से अधिक लोगों की जान चली गई थी। यह देश के सबसे विनाशकारी भूकंपों में गिना जाता है। सुबह आए 3.2 तीव्रता के भूकंप को किसी बड़े भूकंप का संकेत नहीं माना जा सकता। हालांकि, यह घटना पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंपरोधी भवन निर्माण और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की अहमियत याद दिलाती है। भूकंप के झटके महसूस होने पर लोगों को घबराने के बजाय सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए।

रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के दौरों को बताया राजनीतिक ड्रामा, आपदा राहत पर मांगा श्वेत पत्र

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्रों के दौरे और करोड़ों रुपये की घोषणाएं केवल राजनीतिक ड्रामा हैं। तीन साल तक सरकार को जनता की याद नहीं आई और अब चुनाव नजदीक आते ही घोषणाओं की झड़ी लगाई जा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को याद रखना चाहिए कि अंतिम समय का दान भी काम नहीं आता।



घोषणाओं के लिए बजट कहां से लाएगी सरकार : रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के पास सड़कों की मरम्मत, एचआरटीसी बसों के टायर बदलने, खराब मशीनरी ठीक करवाने और विधायक निधि जारी करने तक के लिए पर्याप्त धन नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि करोड़ों रुपये की नई घोषणाओं के लिए बजट कहां से आएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का स्थानीय वेशभूषा पहनना, लोगों के साथ भोजन करना और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना अच्छी बात है, लेकिन सरकार को अपनी नाकामियों का जवाब भी देना चाहिए।

आपदा राहत राशि के इस्तेमाल पर उठाए सवाल : भाजपा विधायक ने कांग्रेस सरकार पर आपदा राहत के नाम पर मिले हजारों करोड़ रुपये के दुरुपयोग और बंदरबांट के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ, एसडीएमएफ, एनडीआरएफ और पीडीएनए सहित विभिन्न मदों में सहायता उपलब्ध करवाई है। उनके अनुसार, पीडीएनए के तहत 2,006.40 करोड़ रुपये की पुनर्निर्माण योजना स्वीकृत हुई, जिसमें केंद्र का हिस्सा 1,504.80 करोड़ रुपये है। उन्होंने दावा किया कि जुलाई और दिसंबर 2025 में 1,053.36 करोड़ रुपये जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है।

शर्मा ने आरोप लगाया कि आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए स्वीकृत धन का इस्तेमाल निर्धारित कार्यों से हटकर किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा विधायकों के क्षेत्रों की अनदेखी और कांग्रेस नेताओं के क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग में ऑफलाइन टेंडर की सीमा एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने तथा बड़े कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटने की प्रक्रिया की जांच की मांग की। बिना काम किए भुगतान होने के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच करवाने की बात कही।

आपदा राहत पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग : रणधीर शर्मा ने मांग की कि सरकार आपदा राहत राशि पर तत्काल श्वेत पत्र जारी करे। इसमें केंद्र से प्राप्त प्रत्येक किस्त, विभागवार आवंटन, विधानसभा क्षेत्रवार खर्च, ठेकेदारों के नाम और भुगतान का पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने महिलाओं को 1,500 रुपये, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और रोजगार देने के वादों पर भी सरकार से जवाब मांगा। भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के 2,200 से अधिक संस्थान बंद कर जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित किया है।

बीबीएमबी फैसले पर श्रेय लेने का आरोप : बीबीएमबी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए शर्मा ने कहा कि हिमाचल को बिजली में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी और अन्य आर्थिक लाभ मिलने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय है। हालांकि, फैसले की विस्तृत प्रति आने के बाद ही इसके सभी पहलू स्पष्ट होंगे।

दीपावली पर एचआरटीसी के 12 हजार कर्मचारियों को पांच प्रतिशत डीए की सौगात

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। दीपावली के पावन अवसर पर हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) की सौगात दी है। निगम के कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने के आदेश दिए गए हैं। इस फैसले से एचआरटीसी के लगभग 12 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। प्रदेश सरकार की ओर से राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा के बाद निगम के कर्मचारियों को भी इसका लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इससे त्योहार के मौके पर कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।



उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एचआरटीसी के कर्मचारी प्रदेश के परिवहन तंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे राज्य के दुर्गम और दूरदराज क्षेत्रों सहित प्रदेश के प्रत्येक हिस्से में लोगों को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी सेवाओं के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को आवागमन की सुविधा मिलती है।

उन्होंने कहा कि निगम के कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। प्रदेश के दूरस्थ इलाकों तक बस सेवाएं पहुंचाने में उनका योगदान सराहनीय है। सरकार कर्मचारियों की सेवाओं और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार कल्याणकारी फैसले ले रही है।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी के पेंशनरों को भी राहत देते हुए दो दिन पहले 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने के आदेश दिए थे। इस फैसले से निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार कार्यरत कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों के हितों का भी ध्यान रख रही है। उनका कल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी के सभी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिवारों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सभी के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि त्योहार का यह अवसर सभी के जीवन में नई खुशियां और सकारात्मकता लेकर आएगा।

पुराने ट्रक सोसायटी सदस्यों के मतदान अधिकार बहाल करेगा हाईकोर्ट आदेश

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिलासपुर की एक ट्रक परिवहन सहकारी सोसायटी के चार पुराने सदस्यों को मतदान, बैठकों और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार देने वाले सरकारी आदेश को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने सोसायटी की याचिका खारिज करते हुए आदेश को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि पहले से पंजीकृत सदस्यों को बिना नोटिस और उचित कारण के नाममात्र का सदस्य घोषित कर उनके अधिकार नहीं छीने जा सकते। सोसायटी ने चारों सदस्यों को पंजाब के कीरतपुर में कारोबार करने के आधार पर नाममात्र का सदस्य बना दिया था। साथ ही उनके ट्रकों को गट्ठा नंबर-1 से हटाकर गट्ठा नंबर-2 में डाल दिया था। हाईकोर्ट ने पाया कि चारों सदस्य पहले से सोसायटी में दर्ज थे और बिलासपुर के स्थायी निवासी हैं। उनके सदस्यता पहचान पत्र, नामांकन रजिस्टर और कृषि प्रमाणपत्र भी इसकी पुष्टि करते हैं।

यशपाल आर्य ने अग्निवीर योजना रद्द करने की मांग उठाई

भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून/बाजपुर। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अग्निवीर योजना को देश की सुरक्षा, सेना के गौरव और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए केंद्र सरकार से इसे तत्काल रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सेना में पहले की तरह नियमित सैनिक भर्ती व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए, ताकि युवाओं को स्थायी रोजगार और सैनिकों को सेवा संबंधी सभी अधिकार मिल सकें। शुक्रवार को जारी बयान में यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस अग्निपथ योजना लागू होने के समय से ही इसका विरोध कर रही है। अब पहले बैच के अग्निवीरों का चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 75 प्रतिशत जवानों की सेवा समाप्त होने का सवाल खड़ा हो गया है। ऐसे में दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने की चर्चा युवाओं की चिंताओं का समाधान नहीं है, बल्कि इससे योजना की खामियां सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों के भविष्य और सम्मान की जिम्मेदारी भी सरकार की है। यशपाल आर्य ने केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना समाप्त कर नियमित सैन्य भर्ती प्रक्रिया तत्काल बहाल करने की अपील की। उन्होंने अग्निवीरों को स्थायी सेवा और समान अधिकार देने, प्रभावित युवाओं के साथ न्याय करने तथा सेना में रिक्त पदों को भरने की मांग की।

उत्तराखंड को 62 विकास योजनाओं की सौगात

अमित शाह और धामी ने 1475 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण–शिलान्यास

राज्य ब्यूरो

देहरादून। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को उत्तराखंड राज्योत्सव के तहत परेड ग्राउंड में 1475.31 करोड़ रुपये की 62 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 1073.11 करोड़ रुपये की 44 योजनाओं का शिलान्यास और 402.20 करोड़ रुपये की 18 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इन परियोजनाओं से प्रदेश में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, पर्यटन और शहरी विकास से जुड़ी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।

ऊर्जा विभाग के तहत यूपीसीएल की 472.33 करोड़ रुपये की 20 योजनाओं का शिलान्यास और 77.93 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। पेयजल निगम की 191.17 करोड़ रुपये की आठ योजनाओं का शिलान्यास तथा 82.03 करोड़ रुपये की पांच योजनाओं का लोकार्पण हुआ। जल संस्थान की 62.30 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया।

लोक निर्माण विभाग की 18.78 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास और 99.68 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। शहरी विकास विभाग की 92.25 करोड़ रुपये की चार योजनाओं का शिलान्यास तथा 10.95 करोड़ रुपये की एक योजना का लोकार्पण हुआ। इनमें हरिद्वार में कुम्भ मेला-2027 के मद्देनजर सड़क, पुल और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास के कार्य शामिल हैं।

पर्यटन और स्वास्थ्य योजनाओं को गति



तकनीकी शिक्षा विभाग की 35.06 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास और 61.98 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इनमें नई टिहरी के राजकीय पॉलिटेक्निक में भवन निर्माण शामिल है। पर्यटन विभाग की 43.70 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का शिलान्यास हुआ। इनमें टिहरी की डोबरा-चांठी पार्क परियोजना और हेमकुण्ड साहिब रोपवे के लिए विद्युत आपूर्ति संबंधी कार्य शामिल हैं। गृह विभाग की 68.27 करोड़ रुपये की दो योजनाओं के तहत देहरादून में साइबर उत्कृष्टता केंद्र और हल्द्वानी में फायर स्टेशन के आवासीय भवन बनाए जाएंगे। सितारगंज में 48.21 करोड़ रुपये की लागत से मिल्क पाउडर, आइसक्रीम और बेकरी यूनिट स्थापित करने की योजना का भी शिलान्यास किया गया। इसके अलावा अगस्त्यमुनि महाविद्यालय में 19.01 करोड़ रुपये से पीजी ब्लॉक बनेगा। आवास, गन्ना विकास और चिकित्सा शिक्षा विभाग की परियोजनाओं का भी लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।

◆ **1073 करोड़ की 44 योजनाओं का शिलान्यास, 402 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण**

अमित शाह और धामी ने नेगी व हेमंत पांडे को नवाजा



परेड ग्राउंड में आयोजित राज्योत्सव समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी और अभिनेता हेमंत पांडे को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्तराखंड फिल्म नीति-2024 के तहत वर्ष 2024 के लिए नेगी और 2025 के लिए हेमंत पांडे का चयन किया गया। दोनों कलाकारों को दो-दो लाख रुपये की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। नेगी ने लोकगीतों से उत्तराखंड की संस्कृति को पहचान दिलाई, जबकि हेमंत पांडे ने अभिनय के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है।

छह बच्चों को मिला मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार



परेड ग्राउंड में छह बच्चों को प्रथम मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। सभी विजेताओं को पदक, प्रशस्ति पत्र और 51-51 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की गई। इनमें चमोली की दिव्या, दीपिका और आरव सिंह शामिल हैं, जिन्होंने भालू के हमले के दौरान साहस दिखाया। चम्पावत की माया ने नदी के तेज बहाव में फंसी बालिका को बचाया, जबकि देहरादून की आराध्या ने आपदा के दौरान 17 लोगों को सतर्क कर सुरक्षित पहुंचाया। टिहरी की श्वेता ने सड़क पर एक बुजुर्ग को वाहन की चपेट में आने से बचाया।

स्काउट्स-गाइड्स के 75 वर्ष पूरे

स्काउट्स एवं गाइड्स बच्चों में नेतृत्व और अनुशासन विकसित करें: राज्यपाल



राज्य ब्यूरो

देहरादून। राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन से शुक्रवार को लोक भवन में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को संगठन का राजकीय स्कार्फ पहनाया और फ्लैग स्टीकर लगाया। साथ ही संगठन की विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं की जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स सात नवंबर को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाएगा। राज्यपाल ने इस अवसर पर संगठन के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों और स्वयंसेवकों को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि स्काउट्स एवं गाइड्स बच्चों में अनुशासन, सेवा, नेतृत्व क्षमता और देशभक्ति की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अधिक से अधिक बच्चों को संगठन से जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए। राज्यपाल ने विद्यालयों में बच्चों को आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार और बचाव कार्यों का प्रशिक्षण देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि आपदाओं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रशिक्षित स्वयंसेवक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने सेवा एवं सहयोग कार्यों में स्काउट्स एवं गाइड्स के योगदान की सराहना की। इस अवसर पर स्टेट अपर मुख्य आयुक्त वंदना गर्ब्याल, स्टेट सेक्रेटरी रविंद्र मोहन काला सहित संगठन के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

◆ **स्काउट्स एवं गाइड्स के 75वें स्थापना दिवस पर राज्यपाल ने दी बधाई**

न्यूज ब्रीफ

आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों ने मानदेय बढ़ाने की उठाई मांग

भारतेन्दु संवाददाता, पौड़ी। आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं ने मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की मांग उठाई है। उनके अधिकारों और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकत्री/सहायिका कर्मचारी एकता संगठन उत्तराखंड की प्रदेश एवं ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी गठित की गई है। इसी क्रम में संगठन के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से मुलाकात कर मानदेय बढ़ाने की मांग रखी। मंत्री ने इस पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए जल्द उचित वृद्धि करने की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी रावत, महामंत्री विमला गैरोला और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि कार्यकत्रियां लंबे समय से सेवाएं दे रही हैं। उनके योगदान को देखते हुए मानदेय बढ़ाना जरूरी है। संगठन ने सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की उम्मीद जताई।

पीएनबी ने गंगा सभा और शांतिकुंज को भेंट किए वाहन

भारतेन्दु संवाददाता, हरिद्वार। धनतेरस के अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक ने सामाजिक दायित्व निभाते हुए स्वच्छ हरिद्वार अभियान को सहयोग दिया। बैंक की ओर से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत गंगा सभा और शांतिकुंज गायत्री परिवार को एक-एक वाहन भेंट किया गया। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में बैंक के अंचल प्रमुख अनुपम ने दोनों वाहन संबंधित संस्थाओं को सौंपे। उन्होंने कहा कि बैंक बैंकिंग सेवाओं के साथ सामाजिक सरोकारों, पर्यावरण संरक्षण और जनकल्याण के कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इन वाहनों से शहर में स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को गति मिलेगी और हरिद्वार को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के प्रयास मजबूत होंगे। कार्यक्रम में बैंक के उप अंचल प्रमुख अभिजित सिन्हा, मंडल प्रमुख रंजन प्रकाश सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गंगा सभा और शांतिकुंज के प्रतिनिधियों ने बैंक की पहल की सराहना करते हुए इसे स्वच्छता अभियान के लिए उपयोगी सहयोग बताया।

डीएम गौरव कुमार ने दी दीपावली की शुभकामनाएं



भारतेन्दु संवाददाता, चमोली/गोपेश्वर। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने प्रकाश पर्व दीपावली पर प्रदेश एवं जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि प्रकाश, उमंग और उल्लास का प्रतीक यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। उन्होंने कहा कि दीपावली आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करने का अवसर है। इस पर्व को सभी को मिल-जुलकर हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। जिलाधिकारी ने लोगों से स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल दीपावली मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि त्योहार की खुशियों के साथ पर्यावरण और सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने सभी से स्वच्छता बनाए रखने और आपसी सद्भाव के साथ प्रकाश पर्व मनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

चमोली के दशोली में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की पहल

भारतेन्दु संवाददाता, चमोली। चमोली जिले के विकासखंड दशोली में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य और संरक्षित खेती की जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालदम के वैज्ञानिक डॉ. अभिषेक बहुगुणा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में ग्वाड़, देवलधार, बैरागना, सिरोली, मंडल, खल्ला, कोटेश्वर, बणद्वारा, रौलीग्वाड़, कुंजों मैकोट, बैमरू और मैठाणा सहित विभिन्न गांवों के किसानों ने भाग लिया। डॉ. बहुगुणा ने जीवामृत, बीजामृत, दशपर्णी और घनजीवामृत बनाने के तरीके बताए।

अल्मोड़ा पुलिस ने 9 .45 लाख के 63 खोए मोबाइल बरामद किए



◆ **दिल्ली से बिहार तक तलाशे गए 63 खोए मोबाइल फोन**

भारतेन्दु संवाददाता, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा पुलिस की साइबर सेल और विशेष अभियान समूह (एसओजी) की टीम ने मोबाइल फोन गुम होने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने विभिन्न राज्यों और उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों से 63 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन सभी मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 9.45 लाख रुपये बताई गई है। शुक्रवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोडके ने पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बरामद मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे।

पुलिस के अनुसार, मोबाइल फोन बरामद करने के लिए साइबर सेल और एसओजी की टीम ने लगातार प्रयास किए।

मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिले

मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने खुशी जाहिर की और अल्मोड़ा पुलिस की साइबर सेल तथा एसओजी टीम का आभार जताया। उन्होंने बताया कि लंबे समय से मोबाइल फोन नहीं मिलने के कारण उन्होंने उन्हें वापस पाने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। मोबाइल मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। एसएसपी चंद्रशेखर घोडके ने बरामद मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे। पुलिस की इस कार्रवाई से न केवल 63 लोगों को उनके खोए हुए फोन वापस मिले, बल्कि साइबर सेल और एसओजी की संयुक्त कार्यवाही से लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ।

विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटा निर्वाचन विभाग

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विभागों से जल्द मांगी आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारियों की सूची

राज्य ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 की तैयारियों को लेकर निर्वाचन विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों, कार्यालयों और उपक्रमों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मतदान दिवस पर आवश्यक सेवाओं में तैनात रहने वाले कार्मिकों के मताधिकार को सुनिश्चित करने और उन्हें डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों की सूची जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि चुनाव से पहले मतदान की व्यवस्था को व्यवस्थित किया जा सके।

डॉ. जोगदंडे ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन, परिवहन, ऊर्जा, पेयजल और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान दिवस पर भी लगी रहती है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों के कारण कोई भी कार्मिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रहे। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यालय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया जाए। संबंधित अधिकारी अपने विभाग के कार्मिकों की सूची तैयार करने, आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान और डाक मतपत्र से मतदान की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए जिम्मेदार होंगे।



निर्वाचन विभाग ने विभागों से मांगा सहयोग

बैठक में उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी सहित पुलिस, अग्निशमन, राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ), स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, परिवहन, पशुपालन, सूचना एवं लोकसंपर्क, दूरदर्शन केंद्र, ऊर्जा निगम और पेयजल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सभी विभागों को निर्वाचन विभाग के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा गया।

ड्यूटी का विवरण समय पर देने के निर्देश

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस पूरी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मतदान में प्रत्येक कार्मिक की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने विभागों में ऐसे सभी कर्मचारियों की पहचान करें, जिन्हें मतदान के दिन आवश्यक सेवाओं में तैनात रहना पड़ सकता है। उनकी ड्यूटी और तैनाती से संबंधित विवरण समय रहते निर्वाचन विभाग को उपलब्ध कराया जाए, जिससे डाक मतपत्र जारी करने सहित अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा सकें।

आदि कैलास के शिव-पार्वती मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद

भारतेन्दु संवाददाता, धारचूला। उच्च हिमालयी क्षेत्र में समुद्र तल से करीब 15 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र आदि कैलास के शिव-पार्वती मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए पांच नवंबर को विधि-विधान के साथ बंद कर दिए गए। अब श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन के लिए अगले साल मई माह तक इंतजार करना होगा। ग्रीष्मकाल शुरू होने और मौसम अनुकूल होने के बाद ही मंदिर के कपाट दोबारा खोले जाएंगे। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, पांच नवंबर की दोपहर ठीक चार बजे स्थानीय परंपराओं और धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार मंदिर के कपाट बंद किए गए। इस दौरान मंदिर के पुजारी वीरेंद्र कुटियाल, पाल सिंह और गिरीश सिंह सहित कई स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। कपाट बंद होने के साथ ही इस वर्ष आदि कैलास में नियमित दर्शन की प्रक्रिया पर विराम लग गया है।

अमित शाह का देवभूमि दौरा प्रेरणादायी प्रदेश में नई ऊर्जा का संचार: महाराज

बोले, केंद्र के सहयोग से विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा उत्तराखंड

राज्य ब्यूरो

देहरादून। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का देवभूमि दौरा अत्यंत प्रेरणादायी रहा। उनके आगमन से प्रदेश में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। यह दौरा राज्य आंदोलन के अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी है। इससे स्पष्ट होता है कि केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने प्रदेशवासियों को राज्य के 26वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन केवल सरकारी उत्सव नहीं, बल्कि संघर्ष, बलिदान और स्वाभिमान का प्रतीक है। नौ नवंबर, 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड राज्य का गठन किया था। खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराहा के बलिदानों को याद करते हुए उन्होंने राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों को नमन किया।



महाराज ने कहा कि स्थापना दिवस पर अमित शाह का मुख्य अतिथि के रूप में सानिध्य मिलना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐतिहासिक निर्णय और सहकारिता के माध्यम से गांवों को सशक्त बनाने की पहल प्रेरणादायी है। सीमांत राज्य उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र का सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और मुख्यमंत्री के विकसित उत्तराखंड के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए चारधाम यात्रा को सुगम बनाया गया है।

वाइब्रेंट विलेज और होम-स्टे से जुड़ेगा पर्यटन

उन्होंने कहा कि पर्यटन को चारधाम तक सीमित रखने के बजाय वाइब्रेंट विलेज, होम-स्टे और लोक संस्कृति से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और देहरादून के परेड ग्राउंड का सौंदर्यीकरण भी विकास की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। महाराज ने कहा कि युवा उत्तराखंड का लक्ष्य पलायन रोकना, युवाओं को रोजगार देना और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखना है।

टिहरी मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल



मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग तेज

भारतेन्दु संवाददाता, टिहरी। *नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज निर्माण का शासनादेश जारी न होने से नाराज मेडिकल कॉलेज निर्माण संयुक्त संघर्ष समिति ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। समिति 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेगी। शुक्रवार को बौराड़ी के गणेश चौक स्थित धरना स्थल पर पत्रकार वार्ता में समिति के मीडिया प्रभारी महिपाल सिंह नेगी ने बताया कि आंदोलन को करीब तीन महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। 11 नवंबर को भूख हड़ताल के स्थान की जानकारी दी जाएगी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जीतराम भट्ट भूख हड़ताल पर बैठेंगे। नेगी ने कहा कि गैरसैंण विधानसभा सत्र में भी टिहरी मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर सरकार ने कोई पहल नहीं की।*

देहरादून में अमित शाह के आगमन पर कांग्रेस-उक्रांद का विरोध प्रदर्शन

काली पट्टी बांधकर कांग्रेस ने उठाए प्रदेश जनहित के मुद्दे

भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शुक्रवार को देहरादून पहुंचने पर कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) ने अलग-अलग मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बांह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया, जबकि उक्रांद कार्यकर्ताओं ने मूल निवास, सशक्त भू-कानून और गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग उठाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश की कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता इस मामले में न्याय चाहती है।



राज्य के बुनियादी मुद्दों पर उक्रांद ने सरकार से मांगा जवाब

वहीं, उक्रांद कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन पर प्रदर्शन कर प्रदेश के बुनियादी मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा। दल के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी प्रदेश बेरोजगारी, पलायन तथा शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने मूल निवास और भू-कानून लागू करने के साथ गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर सवाल उठाए।

समारोह | नशे के कारोबारियों पर होगी कठोर कार्रवाई, 2029 तक नशामुक्ति का लक्ष्य

उत्तराखंड पुलिस को मिला राष्ट्रपति निशान, शाह ने सौंपा सम्मान

भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति निशान (प्रेसिडेंट्स कलर) प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस बल को बधाई देते हुए कहा कि वर्ष 2027 के बाद दर्ज होने वाली एफआईआर में आरोपितों को तीन साल के भीतर सजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सरकार ने 31 मार्च, 2029 तक देश को पूरी तरह नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने राज्य गठन के बाद से अब तक कर्तव्य निभाते हुए बलिदान देने वाले 206 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में पुलिस परेड का आयोजन किया गया और उत्तराखंड पुलिस पत्रिका का विमोचन भी हुआ।

राज्योत्सव समारोह के बाद पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति निशान सौंपा। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 25 वर्षों के भीतर यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करना प्रदेश पुलिस के लिए गौरव की बात है। उत्तराखंड देश का 16वां पुलिस बल है, जिसे राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस ने अपने आदर्श वाक्य 'कर्मण्यता, सत्यनिष्ठा और शौर्यम' को जीवन का आधार बनाकर सेवा, अनुशासन और समर्पण की मिसाल पेश की है। राज्य गठन के समय पुलिस बल में लगभग 13 हजार जवान थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 26 हजार हो गई है।

गृह मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं, भूस्खलन, जंगल की आग और दुर्गम क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों के दौरान पुलिस ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। केदारनाथ आपदा, सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के अभियान तथा धराली, स्यानाचट्टी और मालदेवता में आपदा के दौरान जवानों ने साहस और समर्पण का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में भी उत्तराखंड पुलिस सक्रिय भूमिका निभा रही है।

नक्सलवाद से मुक्त हुआ देश, अब नशे के खिलाफ लड़ाई

अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में उत्तराखंड पुलिस के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक विज्ञान, कंप्यूटरीकरण, सीसीटीएनएस और आईसीजेएस के माध्यम से पुलिस, जेल, अदालत, अभियोजन, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं तथा अस्पतालों को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से जोड़ने का काम किया गया है। ई-रिकॉर्ड तैयार करने में भी प्रदेश ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो चुका है।

नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में उत्तराखंड पुलिस की सराहना



नशामुक्त भारत के लिए 2029 तक चलेगा अभियान: अमित शाह

31 मार्च, 2026 को संसद में देश को नक्सलवाद से मुक्त घोषित किए जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब नशे के खिलाफ लड़ाई बड़ी चुनौती है। सरकार 31 मार्च, 2029 तक देश को नशामुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण करने वाली देश की पहली पुलिस बनने का गौरव उत्तराखंड पुलिस को मिला है।

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की सफल मेजबानी से पंजाब ने 2030 हॉकी विश्व कप की दावेदारी की मजबूत

भारत की खिताबी जीत से पंजाब का बढ़ा मान, 2030 हॉकी विश्व कप की मेजबानी पर नजर

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी-2026 की सफल मेजबानी कर अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के आयोजन में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस उपलब्धि के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वर्ष 2030 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए भी दावा पेश किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य की मजबूत खेल विरासत, बेहतर होते खेल ढांचे और हॉकी के प्रति लोगों के जुनून को देखते हुए पंजाब इस आयोजन के लिए उपयुक्त स्थान है।



एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की विजेता भारतीय टीम के साथ मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान।

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सफल आयोजन के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी। मोहाली के बलबीर सिंह सीनियर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने जापान को 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने ट्रॉफी पर अपना कब्जा बरकरार रखा। वहीं, मलेशिया ने दक्षिण कोरिया को हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब का हॉकी के साथ ऐतिहासिक और अटूट रिश्ता रहा है। राज्य ने भारतीय हॉकी को कई महान खिलाड़ी दिए हैं। बलबीर सिंह सीनियर, ऊधम सिंह, पृथीपाल सिंह, अजीत पाल सिंह और सुरजीत सिंह जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से लेकर वर्तमान समय के हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह तक पंजाब के खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया है।

पंजाब के 77 खिलाड़ी ओलंपिक में कर चुके हैं प्रतिनिधित्व : मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से लेकर 2024 के पेरिस ओलंपिक तक पंजाब ने भारतीय हॉकी को 77 ओलंपियन दिए हैं। इनमें से 48 खिलाड़ियों ने ओलंपिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। पंजाबी खिलाड़ियों ने 10 बार ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी भी की है। टोक्यो ओलंपिक-2020 में पंजाब के आठ खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि पेरिस ओलंपिक-2024 में राज्य के नौ खिलाड़ी भारतीय दल का हिस्सा बने थे। इन दोनों प्रतियोगिताओं में क्रमश: मनप्रीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने भारतीय टीम की कप्तानी की थी।

खेल ढांचे को मजबूत करने पर 1744 करोड़ खर्च : मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में छह नए हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान तैयार किए जा चुके हैं, जबकि दो अन्य मैदानों का निर्माण कार्य चल रहा है। खेल सुविधाओं के विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में 1744 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार पंजाब की खेल विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

हार्दिक सिंह को 200वें अंतरराष्ट्रीय मैच पर सम्मान : फाइनल मुकाबले के दौरान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भारतीय हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह को उनके 200वें अंतरराष्ट्रीय मैच के अवसर पर विशेष जर्सी भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने भारतीय और जापानी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। इसके बाद विजेता भारतीय टीम को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए।

समापन समारोह में पंजाब की सांस्कृतिक विरासत की शानदार झलक देखने को मिली। खचाखच भरे स्टेडियम में गतका और भांगड़े की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाया। हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ ने भी प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री और पंजाब सरकार की सराहना की। इस अवसर पर प्रमुख सचिव खेल वरुण रूजम, हॉकी पंजाब के अध्यक्ष नितिन कोहली सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

राजपुरा में कर्मभूमि एक्सप्रेस के चार डिब्बों में आग लगने से यात्रियों में मची अफरा-तफरी

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के अमृतसर से पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस के चार जनरल कोच में शुक्रवार को आग लगने से रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना के बाद ट्रेन को पटियाला जिले के राजपुरा रेलवे स्टेशन पर आपात स्थिति में रोक दिया गया। आग लगने की सूचना मिलते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। रेलवे प्रशासन, दमकल विभाग और राहत दल ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। अधिकारियों के अनुसार, घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं, रेल यातायात प्रभावित होने से आठ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव करना पड़ा। रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 12508 कर्मभूमि एक्सप्रेस के चार जनरल कोच में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। ट्रेन शुक्रवार दोपहर 12:58 बजे फतेहगढ़ साहिब के साधूगढ़ रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी। इसके कुछ समय बाद ट्रेन के इंजन से पांचवें कोच तक आग लगने की जानकारी सामने आई। संबंधित कोच का नंबर 265287 जीएस बताया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ट्रेन को राजपुरा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। इसके बाद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने और आग पर काबू पाने के लिए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।



घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन ने संबंधित विभागों को सतर्क किया। दमकल विभाग की टीमों के साथ राहतकर्मी भी मौके पर पहुंचे। यात्रियों को कोच से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। रेलवे की मेडिकल टीम को भी घटनास्थल पर भेजा गया, ताकि जरूरत पड़ने पर यात्रियों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जानकारी में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, रेलवे की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। घटना के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

कर्मभूमि एक्सप्रेस में आग लगने की घटना के कारण रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अंबाला रेलवे मंडल ने आठ ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से चलाने का निर्णय लिया। मंडल की ओर से जारी डायवर्जन योजना के अनुसार, डाउन दिशा की पांच और अप दिशा की तीन ट्रेनों के मार्ग बदले गए। इससे संबंधित रेलखंड पर परिचालन व्यवस्था में बदलाव करना पड़ा।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की। अंबाला रेलवे मंडल के पीआरओ नीरज ने बताया कि अमृतसर से पश्चिम बंगाल जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस में आग लगने की सूचना मिलने के बाद मंडल की मेडिकल टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। डीआरएम विनोद कुमार भाटिया भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अभी तक घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रेलवे की ओर से आग लगने की घटना की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच के बाद ही आग लगने के कारणों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की स्पष्ट जानकारी सामने आएगी।

लहरागागा की डेयरी फैक्टरी पर छापा, दो क्विंटल संदिग्ध पनीर सहित घी-दही बरामद

भारतेंदु संवाददाता, लहरागागा । त्योहारों के सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए प्रशासन और फूड सेफ्टी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में लहरागागा के स्टेडियम रोड स्थित एक मिल्क प्रोडक्ट फैक्टरी में प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने अचानक छापेमारी की। इस दौरान करीब दो क्विंटल संदिग्ध पनीर के अलावा भारी मात्रा में देसी घी, दही और क्रीम बरामद की गई। टीम ने मौके पर मौजूद खाद्य सामग्री को कब्जे में लेकर जांच की और विभिन्न दुग्ध उत्पादों के सैंपल भरकर सील किए।



यह कार्रवाई उपमंडल मैजिस्ट्रेट (एसडीएम) राकेश प्रकाश और फूड सेफ्टी ऑफिसर सीमा रानी की अगुवाई में की गई। अधिकारियों की टीम ने स्टेडियम रोड के सामने स्थित डेयरी फैक्टरी परिसर में दबिश देकर वहां तैयार किए जा रहे उत्पादों और उपलब्ध स्टॉक का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान पनीर, देसी घी, दही, क्रीम और पनीर बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के नमूने भी लिए गए।

एसडीएम राकेश प्रकाश ने बताया कि उक्त फैक्टरी के खिलाफ स्थानीय निवासियों और उपभोक्ताओं की ओर से लंबे समय से मिलावटखोरी और घटिया गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ तैयार करने की शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा विभाग संगरूर की विशेष टीम के साथ मिलकर अचानक छापेमारी की। इसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करना और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। उन्होंने बताया कि मौके से लिए गए सभी नमूनों को सील कर सरकारी प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जा रहा है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद ही उत्पादों की गुणवत्ता और उनमें किसी तरह की मिलावट होने की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि यदि जांच रिपोर्ट में पनीर, घी, दही, क्रीम या अन्य उत्पादों में मिलावट अथवा गुणवत्ता संबंधी खामी पाई जाती है तो फैक्टरी संचालक के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अमृतसर में विदेशी मॉडल का डेढ़ लाख का आईफोन झपटकर फरार हुआ लुटेरा

भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में वाघा बॉर्डर घूमकर लौट रही लंदन निवासी विदेशी मॉडल लाली से बाइक सवार झपटमार ने डेढ़ लाख रुपये कीमत का आईफोन 17 प्रो मैक्स छीन लिया। वारदात के दौरान आरोपित बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर सवार था। लाली पंजाबी गाने 'सोहनी नहीं' में मॉडलिंग कर चुकी हैं। फोन छिनने के बावजूद उन्होंने भारत, पंजाब और अमृतसर के प्रति अपना प्यार बरकरार रहने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यहां के लोग मुश्किल समय में परिवार की तरह मदद के लिए आगे आते हैं। लाली ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 31 अक्टूबर को शाम करीब सात बजे वह अन्य पर्यटकों के साथ वाघा बॉर्डर घूमकर ऑटो में वापस लौट रही थीं। वह ऑटो की अगली सीट पर बैठी थीं और उनका आईफोन गोद में रखा हुआ था। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार एक अज्ञात व्यक्ति उनके पास आया और झपट्टा मारकर फोन छीनकर फरार हो गया। फोन के कवर में एक मोर पंख भी लगा हुआ था, जो उन्हें भारत में किसी अनजान व्यक्ति ने उपहार के रूप में दिया था। मॉडल ने बताया कि यह भारत की उनकी नौवीं यात्रा थी। फोन चोरी होने की घटना से उन्हें परेशानी जरूर हुई, लेकिन इससे भारत और यहां के लोगों के प्रति उनका लगाव कम नहीं हुआ।

सेक्टर-17 में गो-कार्टिंग से बढ़ेगा पर्यटन रोमांच

पीपीपी मॉडल पर निजी एजेंसी करेगी संचालन, तिरंगा पार्क के पास बनेगा रेसिंग ट्रैक

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को पर्यटन के लिहाज से और आकर्षक बनाने के लिए प्रशासन नई गतिविधियां शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है। इसी कड़ी में शहर के प्रमुख व्यावसायिक और सार्वजनिक स्थल सेक्टर-17 प्लाजा में गो-कार्टिंग शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इसके शुरू होने से शहरवासियों और पर्यटकों को खरीदारी, खानपान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा रेसिंग कार का रोमांच भी अनुभव करने का अवसर मिलेगा। प्रशासन ने इस परियोजना को लेकर प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं।



गो-कार्टिंग के लिए सेक्टर-17 स्थित तिरंगा पार्क के पास जगह तलाश की गई है। इस संबंध में पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है। प्रस्तावित परियोजना के लिए संपदा विभाग को संबंधित जमीन पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने के लिए कहा गया है। योजना के अनुसार इसका संचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर किया जा सकता है। इसके तहत प्रशासन स्थान और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा, जबकि निजी एजेंसी गो-कार्टिंग के लिए कार्ट, उपकरण और संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। हालांकि परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही संचालन की शर्तें, शुल्क और अन्य व्यवस्थाएं निर्धारित की जाएंगी।

गो-कार्टिंग एक ऐसी एडवेंचर गतिविधि है, जिसमें छोटी चार पहियों वाली रेसिंग कारों को विशेष रूप से तैयार ट्रैक पर चलाया जाता है। इसमें निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुसार बच्चे और बड़े दोनों हिस्सा ले सकते हैं। देश के कई शहरों में निजी कंपनियां इस तरह की सुविधा संचालित कर रही हैं। वहां एक राइड के लिए सामान्य तौर पर 500 से 1000 रुपये तक शुल्क लिया जाता है। चंडीगढ़ में भी इसे व्यावसायिक और पर्यटन गतिविधि के रूप में विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अधिकारियों की ओर से दूसरे राज्यों में सफल रहे पर्यटन प्रोजेक्टों का भी अध्ययन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि हर साल करीब 12 लाख पर्यटक चंडीगढ़ पहुंचते हैं।

सेक्टर-17 प्लाजा चंडीगढ़ की पहचान और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों में शामिल है। इसे फिर से आकर्षक बनाने के लिए प्रशासन पहले ही कई कदम उठा चुका है। यहां म्यूजिकल फाउंटेन, एम्फीथिएटर, आकर्षक लाइटिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। प्रोजेक्टर मैपिंग और विभिन्न आयोजनों के माध्यम से भी प्लाजा को जीवंत बनाने का प्रयास हो रहा है। दीपावली के अवसर पर यहां करीब 20 हजार डिजिटल लाइट्स से चेरी ब्लॉसम थीम पर सजावट की गई थी। अब गो-कार्टिंग जैसी एडवेंचर गतिविधि जोड़ने से इस स्थान पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। इससे युवाओं के साथ परिवारों को भी आकर्षित किया जा सकेगा।

चंडीगढ़ में बड़े आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए सारंगपुर में करीब 25 एकड़ जमीन पर कॉन्सर्ट-कम-एग्जीबिशन सेंटर विकसित करने की योजना है। यहां बड़े संगीत कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और सार्वजनिक आयोजन किए जा सकेंगे। इससे मोहाली और पंचकूला में होने वाले बड़े आयोजनों को चंडीगढ़ की ओर आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

गैंगस्टर बनने की चाह में तीन घरों पर फायरिंग आकाशदीप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

भारतेंदु संवाददाता, मोहाली। मोहाली में पांच-पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के लिए तीन घरों पर फायरिंग करने के मामलों में पुलिस ने आकाशदीप सिंह को मुख्य आरोपित बनाया है। पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच के अनुसार, तीनों वारदातों में आकाशदीप की अहम भूमिका थी। वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कार्यशैली से प्रभावित होकर अपराध की दुनिया में अपनी पहचान और दबदबा बनाना चाहता था। फिलहाल वह जेल में बंद है।

आकाशदीप की मां अमरीन राय भी हत्या के एक मामले में गिरफ्तार हो चुकी है। चंडीगढ़ पुलिस ने 18 मार्च 2026 को सेक्टर-9 में हुए चिन्नी कुबाहेड़ी हत्याकांड में उसे गिरफ्तार किया था। जांच में आरोप लगा था कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते अमरीन ने गैंगस्टर लक्की पटियाल को सुपारी देकर हत्या करवाई थी। मां के संबंध लक्की पटियाल से बताए गए, जबकि बेटा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से प्रभावित था।

पुलिस के अनुसार, मोहाली में पहली फायरिंग चार-पांच सितंबर की रात फेज-10 में सैय्यम डुडेजा के घर पर हुई। सात सितंबर को उनके पार्टनर बलजीत सिंह के घर और 14 सितंबर को सेक्टर-104 में जगदीप सिंह मान के घर को निशाना बनाया गया। तीनों से पांच-पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी। तीसरी वारदात में घर पर काम कर रहा सचिन गोली लगने से घायल हो गया था। जांच में आकाशदीप और उसके साथियों के बुड़ैल जेल में बंद गैंगस्टर रविंदर सिंह उर्फ काली तथा विदेश में बैठे कुलवीर सिंह सिद्धू से संपर्क होने की बात सामने आई। पुलिस ने करीब आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से पांच पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल फार्च्यूनर कार बरामद की गई थी।

फिरोजपुर और संगरूर में भी पराली जलाने के मामले बढ़े, प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती

पंजाब में पराली जलाने की 2787 घटनाएं 46 लाख जुर्माना; तरनतारन सबसे आगे

भारतेंदु संवाददाता, पटियाला। पंजाब में धान की कटाई का सीजन अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो पाया है। पांच नवंबर तक राज्य में पराली जलाने की 2787 घटनाएं सैटेलाइट के माध्यम से दर्ज की गई हैं। इन मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 46.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से अब तक 24.85 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है।



कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) की रिपोर्ट के अनुसार, तरनतारन जिला पराली जलाने के मामलों में सबसे आगे है। यहां अब तक 586 घटनाएं दर्ज की गई हैं। प्रशासन ने जिले में 14.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें से 13.30 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। इसके अलावा 13 नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है।

अमृतसर में पराली जलाने के 221 मामले सामने आए हैं। यहां 5.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 4.75 लाख रुपये वसूल किए गए हैं। वहीं, फिरोजपुर में 361 घटनाएं दर्ज हुई हैं, जो तरनतारन के बाद राज्य में सबसे अधिक हैं। जिले में 7.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और 1.60 लाख रुपये की वसूली हुई है। फिरोजपुर में पांच अधिकारियों के खिलाफ भी अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है।

9 नवंबर को गोवर्धन पूजा पर चंडीगढ़ में रहेगी छुट्टी

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ प्रशासन ने नौ नवंबर (सोमवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में प्रशासन के गृह सचिव मनदीप सिंह बराड़ की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रशासन के इस फैसले से चंडीगढ़ के सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों में नौ नवंबर को छुट्टी रहेगी। पहले इस दिन को प्रतिबंधित अवकाश की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन अब इसे सार्वजनिक अवकाश में शामिल कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह फैसला वर्ष 2026 के अवकाश कैलेंडर में संशोधन करते हुए लिया गया है। गौरतलब है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने 30 दिसंबर 2025 को वर्ष 2026 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया था। इसमें नौ नवंबर को गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा दिवस के लिए प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया गया था।

धनतेरस पर पीतल-कांसे के बर्तनों की चमक लौटी, बाजारों में बढ़ी मांग

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। कहते हैं कि जमाना लौटकर आता है। इसकी झलक इस बार धनतेरस पर बर्तन बाजारों में देखने को मिली। करीब तीन दशक बाद पारंपरिक धातुओं से बने बर्तनों की मांग एक बार फिर बढ़ती नजर आई। आधुनिक किचनवेयर और क्रॉकरी के बढ़ते चलन के बीच लोगों ने स्टील के साथ पीतल और कांसे के बर्तनों को भी खूब पसंद किया। इससे बाजारों में पारंपरिक बर्तनों की रौनक देखने को मिली। धनतेरस के अवसर पर ग्राहकों ने अपनी जरूरत और बजट के अनुसार अलग-अलग धातुओं के बर्तनों की खरीदारी की। बाजार में पीतल के बर्तनों की कई तरह की वैरायटी उपलब्ध रही। इनमें 200 रुपये की कटोरी और गिलास से लेकर 30 हजार रुपये तक के डिनर सेट शामिल रहे। वहीं, कांसे के बर्तन भी ग्राहकों के आकर्षण का केंद्र बने। पारंपरिक धातुओं के बर्तनों में लोगों ने अलग-अलग डिजाइन, आकार और



उपयोगिता को ध्यान में रखकर खरीदारी की। पिछले कुछ वर्षों में लोग आधुनिक डिजाइन वाली क्रॉकरी और किचन के नए सामान की ओर अधिक आकर्षित हुए थे, लेकिन अब पारंपरिक बर्तनों के प्रति रुचि दोबारा बढ़ रही है। इसके पीछे परंपरा के साथ स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती जागरूकता को भी एक वजह माना जा रहा है। कई ग्राहक त्योहारों पर पुराने समय से चली आ रही खरीदारी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पीतल और कांसे के बर्तन घर ले जा रहे हैं। बर्तन बाजारों में केवल पीतल और कांसे की ही मांग नहीं रही, बल्कि स्टील के बर्तनों की भी अच्छी बिक्री हुई।

बेटे को न्याय दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे झोटा के पिता, एसएसपी पर कार्रवाई की मांग

भारतेंदु संवाददाता, मानसा। पंजाब के मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की मौत के मामले में नया घटनाक्रम सामने आया है। झोटा के पिता भीम सिंह ने अपने बेटे को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक मानसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) का तबादला नहीं किया जाता और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं होती, तब तक वह अपना विरोध जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि वह शुक्रवार से खाना-पीना छोड़ रहे हैं और मांगें पूरी होने तक अपने फैसले पर कायम रहेंगे।

चंडीगढ़ में परविंदर सिंह झोटा के पोस्टमार्टम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए भीम सिंह ने पंजाब सरकार की ओर से घोषित आर्थिक सहायता और परिवार को सरकारी नौकरी देने के फैसले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार



की ओर से दिए जाने वाले दो करोड़ रुपये के मुआवजे की जरूरत नहीं है और न ही वह अपनी बहू मनप्रीत कौर के लिए सरकारी नौकरी चाहते हैं। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बेटे को न्याय मिलना है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो परिवार को दी गई सुरक्षा भी वापस ले सकती है, लेकिन जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वह पीछे नहीं हटेंगे।

गौरतलब है कि नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा का 24 दिन बाद शुक्रवार, छह नवंबर को चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। उनका शव गुरुवार देर रात करीब 12 बजे मानसा सिविल अस्पताल की मोर्चरी से एंबुलेंस के माध्यम से चंडीगढ़ भेजा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। लोगों ने वाहेगुरु का जाप करते हुए झोटा के शव को मोर्चरी से बाहर निकाला और एंबुलेंस में रखा। शव को ले जाने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस एंबुलेंस की व्यवस्था की गई थी, जिसमें आईसीयू, वेंटिलेटर और फ्रीजर की सुविधा उपलब्ध थी। बताया गया है कि पोस्टमार्टम करवाने के फैसले से पहले झोटा के पिता भीम सिंह और इंसाफ कमेटी ने पंजाब सरकार के साथ बातचीत कर समझौता किया था। इस दौरान सरकार ने परिवार को दो करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने और झोटा की पत्नी मनप्रीत कौर को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने का भरोसा दिया था।

नशामुक्ति भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल ने नशे के मुद्दे पर आप सरकार की घेराबंदी की तेज

2027 चुनाव में नशे का मुद्दा बनेगा सत्ता की सियासत का बड़ा आधार

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब चुनाव में नशे का मुद्दा फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। सभी प्रमुख दल नशे की समस्या को लेकर सरकार की नीतियों और दावों पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक दलों के लगातार हमलावर रुख से स्पष्ट है कि आगामी विधानसभा चुनाव में नशे का मुद्दा सबसे अहम चुनावी मुद्दों में शामिल रहने वाला है। खास बात यह है कि करीब एक दशक पहले जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राजनीतिक विरोधियों की आलोचना झेलनी पड़ी थी, आज उसी मुद्दे पर कांग्रेस सहित अन्य दल आप सरकार को घेर रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अक्टूबर को पंजाब दौरे के दौरान नशे के खिलाफ लड़ाई को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने वर्ष 2029 तक पंजाब सहित पूरे देश से नशे को समाप्त करने का संकल्प जताया। शाह ने प्रदेश में नशे के कारोबार को लेकर सीधे तौर पर आप सरकार पर निशाना साधते हुए उसे जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। इसके जवाब में आप नेताओं ने भाजपा पर पलटवार किया और गुजरात में नशे के कारोबार पर रोक लगाने की चुनौती दी। इस बयानबाजी के बाद भाजपा और आप के बीच नशे के मुद्दे पर राजनीतिक टकराव और तेज हो गया।


दशहरे पर लुधियाना में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह और दो दिन पहले संगरूर में रैली के दौरान राहुल गांधी।

वहीं, बुधवार को संगरूर में आयोजित रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नशे की समस्या को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने पंजाब में नशे के बढ़ते प्रभाव के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने प्रदेश की स्थिति को लेकर सरकारों की भूमिका पर सवाल उठाए। कांग्रेस इस मुद्दे को आप सरकार की विफलता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। पार्टी का आरोप है कि नशे की समस्या पर सरकार के दावों और जमीनी स्थिति में काफी अंतर है। दूसरी ओर भाजपा भी नशे की तस्करी और कानून-व्यवस्था के सवाल पर राज्य सरकार को घेर रही है।

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी लगातार नशे के मुद्दे पर आप सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अकाली दल का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब को नशामुक्त बनाने के बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी प्रदेश में नशे का कारोबार पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाया। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार की ओर से कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन समस्या की गंभीरता को देखते हुए और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अकाली दल इस मुद्दे को लेकर सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है।

भाजपा भी पंजाब में नशे की समस्या को सीमा पार से होने वाली तस्करी और प्रदेश की कानून-व्यवस्था से जोड़कर उठा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि नशे के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई के बिना इस समस्या पर काबू पाना मुश्किल है। इस तरह भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ आप सरकार को निशाना बना रहे हैं।

नेकां में बगावत के सुर तेज, उमर फारूक के सामने बढ़ी चुनौती

नेकां विधायकों ने खोला मोर्चा, मंत्रिमंडल में फेरबदल और संगठन में लोकतंत्र की उठाई मांग

भारतेन्दु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर की सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) में अंदरूनी असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है। हालिया मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज पार्टी विधायकों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला के साथ बैठक कर अपनी मांगें रखीं। विधायकों ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत करने, मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल करने और सरकार के कामकाज में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने अपनी शिकायतों और मांगों से जुड़ा विस्तृत मांगपत्र भी नेतृत्व को सौंपा।

मुख्यमंत्री आवास पर सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुई इस बैठक को पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष को दूर करने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। हालिया मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं मिलने और कुछ नेताओं को दोबारा जिम्मेदारियां सौंपे जाने से कई विधायक नाराज हैं। उनका मानना है कि मंत्रिमंडल में पदों और विभागों का बंटवारा करते समय वरिष्ठता, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और विधायकों के राजनीतिक योगदान को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया।

सूत्रों के अनुसार, विधायकों ने स्पष्ट किया कि उनकी नाराजगी केवल मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि पार्टी और सरकार के कामकाज में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही है। संगठनात्मक फैसलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामूहिक विचार-विमर्श की व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है। विधायकों ने मांग की कि महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक फैसले कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित न रहें, बल्कि उनमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए।



सलाहकारों को हटाने और नए सलाहकार नियुक्त करने का प्रस्ताव

नाराज विधायकों की प्रमुख मांगों में मुख्यमंत्री के मौजूदा सलाहकार को हटाने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने दो नए अवैतनिक सलाहकार नियुक्त करने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक, विधायकों का सुझाव है कि जम्मू और कश्मीर संभाग से एक-एक सलाहकार नियुक्त किया जाए, ताकि दोनों क्षेत्रों की राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याओं को मुख्यमंत्री तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके। उपमुख्यमंत्री के पद और विभागों को लेकर भी विधायकों ने अपनी आपत्ति जताई है। उनकी मांग है कि यदि उपमुख्यमंत्री को पद से नहीं हटाया जाता है तो उनके विभागों में व्यापक फेरबदल किया जाए। इसके अलावा मंत्रिमंडल में शामिल कुछ मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करने और लंबे समय से पद संभाल रहे मंत्रियों की जगह वरिष्ठ तथा उपेक्षित विधायकों को अवसर देने की मांग भी उठाई गई है।

आगा रुहुल्लाह के इस्तीफे से बढ़ी नेतृत्व की चुनौती

नेकां में असंतोष का यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने तीन नवंबर को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफे का एलान किया था। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे और अनुच्छेद 370 की बहाली से जुड़े चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया था। रुहुल्लाह और पार्टी नेतृत्व के बीच पिछले काफी समय से मतभेद चल रहे थे। आरक्षण नीति, अनुच्छेद 370 और पार्टी की राजनीतिक कार्यशैली को लेकर उनकी असहमति पहले भी सार्वजनिक हो चुकी थी। उनके इस्तीफे के बाद विधायकों की सामूहिक नाराजगी ने पार्टी नेतृत्व के सामने संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखने की चुनौती और बढ़ा दी है।

अपराध नियंत्रण, नशा विरोधी मुहिम और सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर

त्योहारी सीजन से पहले जम्मू पुलिस सतर्क, सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत

भारतेन्दु संवाददाता, जम्मू

जम्मू जिले में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर शहर और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाएगी। इसके तहत भीड़भाड़ वाले इलाकों में डायनामिक नाके स्थापित करने के साथ महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। यह निर्देश एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह ने जिला पुलिस लाइन (डीपीएल) जम्मू में आयोजित अपराध एवं पुलिस कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक के दौरान दिए।

बैठक में जिले की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस की कार्यप्रणाली से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। एसएसपी ने अधिकारियों से जिले में दर्ज आपराधिक मामलों के निपटारे की स्थिति की जानकारी ली। इसके अलावा नए आपराधिक कानूनों (एनसीएल) के प्रभावी क्रियान्वयन, ई-साक्ष्य प्रणाली के इस्तेमाल और लंबित शिकायतों के समाधान की भी समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को जांच प्रक्रिया में तेजी लाने और मामलों के निपटारे में निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

आगामी त्योहारों के दौरान बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही बढ़ने की संभावना को देखते हुए एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने शहर के प्रमुख बाजारों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही डायनामिक नाकों के माध्यम से नियमित जांच और निगरानी सुनिश्चित करने को कहा, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते नजर रखी जा सके। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सतर्कता बनाए रखने और विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का लगातार आकलन करने के निर्देश भी दिए। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि त्योहारी सीजन के दौरान आम लोगों की सुरक्षा और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए।

बैठक में सामुदायिक पुलिसिंग और बीट व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई। एसएसपी ने कहा कि पुलिसकर्मियों को स्थानीय लोगों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक बीट में पुलिस की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याएं सुनने, शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने और पुलिस तथा जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।



◆ डीपीएल में समीक्षा बैठक संवेदनशील इलाकों में बढ़ेगी पुलिस की निगरानी और गश्त

कारीगरों को देश-विदेश से मिल रहे ऑर्डर, डेढ़ महीने में तैयार होता है एक रबाब

कश्मीर के रबाब की दुनिया में गूंज शहतूत की लकड़ी की बढ़ी किल्लत

भारतेन्दु संवाददाता, श्रीनगर

कश्मीरी संगीत की पहचान माने जाने वाले पारंपरिक वाद्ययंत्र रबाब की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। अपनी अनूठी बनावट, मधुर ध्वनि और सांस्कृतिक महत्व के कारण इसकी मांग कश्मीर के साथ देश के दूसरे हिस्सों और विदेशों में भी बनी हुई है। हालांकि, इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली शहतूत की लकड़ी की कमी कारीगरों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। लकड़ी की उपलब्धता घटने से इस पारंपरिक हस्तकला के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ रही है।

◆ तीन पीढ़ियों से परिवार संजो रहा हुनर, यूनेस्को से मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान

मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के नरबल निवासी कारीगर मुश्ताक अहमद डार रबाब बनाने की कला से जुड़े हैं। वह बताते हैं कि उन्हें लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। कश्मीर के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों से भी लोग उनसे रबाब बनवाने के लिए संपर्क करते हैं। उनके अनुसार, रबाब की पहचान अब केवल संगीत के क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी आकर्षक बनावट के कारण लोग इसे घरों में सजाने और उपहार देने के लिए भी खरीदते हैं।

डार ने बताया कि एक स्थानीय वकील ने 35 हजार रुपये का रबाब अमेरिका में रहने वाले अपने रिश्तेदार को उपहार देने के लिए बनवाया था। जब वह इसे लेने उनकी कार्यशाला पहुंचे तो इसकी सुंदरता देखकर उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। उन्होंने रबाब अपने पास रखने का निर्णय लिया और बाद में तीन रबाब तथा एक सारंगी भी खरीदी। यह उदाहरण बताता है कि रबाब अब संगीत वाद्ययंत्र के साथ सजावटी वस्तु के रूप में भी पसंद किया जा रहा है।

डार अपने घर में बनी दो कमरों की कार्यशाला में सुबह नौ बजे से रात दस बजे तक काम करते हैं। वह रबाब के अलावा संतूर और सारंगी सहित अन्य वाद्ययंत्र भी बनाते हैं। हालांकि, सबसे अधिक ऑर्डर रबाब के ही मिलते हैं। उनका कहना है कि रबाब को कश्मीरी वाद्ययंत्रों का राजा माना जाता है। इसकी मांग और कीमत भी दूसरे वाद्ययंत्रों की तुलना में अधिक है। ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार इसकी बनावट और डिजाइन तय करवाते हैं।

रबाब बनाने की कला डार के परिवार में तीन पीढ़ियों से चली आ रही है। उन्होंने यह हुनर अपने पिता से सीखा, जो सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद शौक के तौर पर रबाब बनाया करते थे। अब उनके पिता और भाई भी इस काम में सहयोग करते हैं। परिवार के बच्चे भी इस पारंपरिक कला को आगे बढ़ाने में रुचि दिखा रहे हैं। डार के मुताबिक, शुरुआत में उन्होंने इसे शौक के रूप में अपनाया था, लेकिन धीरे-धीरे यही उनका पूर्णकालिक व्यवसाय बन गया।

तीन अभियानों में नशे के पांच संदिग्ध तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे

भारतेन्दु संवाददाता, हंदवाड़ा। जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पुलिस ने तीन अलग-अलग अभियानों के दौरान पांच संदिग्धों को पकड़कर उनके कब्जे से चरस और अन्य प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए हैं। ये कार्रवाई क्रालगुंड पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकी चोगुल के अधिकार क्षेत्र में की गई। पुलिस ने सभी मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, पहली कार्रवाई क्रालगुंड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत खानू बाबागुंड इलाके में नाका जांच के दौरान की गई। यहां पुलिस ने दो व्यक्तियों को संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर रोककर तलाशी ली। उनकी पहचान ताराथपोरा निवासी आबिद हुसैन मीर और खानू निवासी रऊफ मुश्ताक भट के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चरस जैसा पदार्थ और चरस पाउडर जैसा पदार्थ बरामद किया गया। इस संबंध में क्रालगुंड पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20-29 के तहत प्राथमिकी संख्या 78/2026 दर्ज की गई है।

दूसरी कार्रवाई वनिगाम क्रॉसिंग पर की गई। यहां पुलिस ने बुद्रा बाला निवासी दानिश परवेज पर्रा को पकड़ा। उसके कब्जे से भांग (खसखस) जैसा पदार्थ बरामद हुआ। इस मामले में क्रालगुंड पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत प्राथमिकी संख्या 79/2026 दर्ज की गई है।

तीसरी कार्रवाई पुलिस चौकी चोगुल के अधिकार क्षेत्र में वटयेन इलाके में नाका जांच के दौरान हुई। इस दौरान सोपोर से कुपवाड़ा की ओर जा रही एक मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली गई। मोटरसाइकिल पर सवार बिहार निवासी मोहम्मद जहांगीर सिद्दीकी और मोहम्मद हसीमुद्दीन को पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक, उनके कब्जे से चरस जैसा पदार्थ बरामद हुआ। इस मामले में हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20-29 के तहत प्राथमिकी संख्या 275/2026 दर्ज की गई है।

त्योहारों की रौनक से गुलजार हुए जम्मू के बाजार, खरीदारी ने पकड़ी रफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, जम्मू

त्योहारों के मौसम ने जम्मू के बाजारों में रौनक बढ़ा दी है। करवाचौथ के बाद अब धनतेरस और दीपावली की खरीदारी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, आभूषण और बर्तनों की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। त्योहारों के चलते कारोबार में तेजी आने से व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि नवंबर के अंत तक बाजारों में खरीदारी का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जम्मू के पुराने शहर के बाजारों से लेकर गांधी नगर, शास्त्री नगर, नानक नगर, छन्नी हिम्मत, न्यू प्लाट, रिहाड़ी और सरवाल जैसे इलाकों में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई है। लोग त्योहारों के लिए घरों की सजावट, पूजा सामग्री, नए कपड़े और अन्य जरूरी सामान खरीद रहे हैं। शुक्रवार को धनतेरस के साथ दीपोत्सव का शुभारंभ हो गया है। इसके बाद दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाईदूज और छठ पूजा सहित कई प्रमुख पर्व मनाए जाएंगे। इसके साथ ही शादी-विवाह का सीजन शुरू होने से बाजारों में कारोबार बढ़ने की उम्मीद है।

लगातार त्योहारों के चलते बाजारों में बढ़ी ग्राहकों की आवाजाही


एआई इमेज

दस नवंबर को गोवर्धन पूजा और 11 नवंबर को भाईदूज मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा पर भगवान को अन्नकूट और मौसमी सब्जियों का भोग लगाया जाएगा, जबकि भाईदूज पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी सुख-समृद्धि और लंबी आयु की कामना करेंगी। 13 से 16 नवंबर तक छठ पूजा का आयोजन होगा। जम्मू में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों में इस पर्व को लेकर विशेष उत्साह रहता है। श्रद्धालु सूर्यदेव की आराधना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करेंगे। इसके बाद 17 नवंबर को गोपाष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन गोमाता की पूजा और सेवा का विशेष महत्व है। वहीं, 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ महीने के प्रमुख त्योहारों का समापन होगा। इस अवसर पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान, दीपदान और दान-पुण्य करेंगे। लगातार त्योहारों और शादी-विवाह के आयोजनों के चलते जम्मू के व्यापारियों को नवंबर में अच्छे कारोबार की उम्मीद है।

आठ वर्षों से साइकिल पर देश में एकता का संदेश फैला रहे नागराज

भारतेन्दु संवाददाता, आरएसपुरा। देश की सड़कों पर पिछले आठ वर्षों से साइकिल के पैडल मार रहे कर्नाटक निवासी नागराज गौड़ा का सफर केवल देश भ्रमण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए वह राष्ट्रीय एकता, आपसी भाईचारे और सनातन धर्म का संदेश भी फैला रहे हैं। वर्ष 2018 में शुरू हुई उनकी साइकिल यात्रा के तहत अब तक वह 22 राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं। गुरुवार को आरएसपुरा पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

नागराज गौड़ा ने बताया कि उन्होंने देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर लोगों को प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देने के उद्देश्य से यह यात्रा शुरू की थी। आठ वर्षों के इस सफर में उन्हें विभिन्न राज्यों में लोगों का भरपूर सहयोग और स्नेह मिला है, जिससे उनका उत्साह लगातार बढ़ा है।



उन्होंने बताया कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद वह जम्मू पहुंचे और यहां से आरएसपुरा आए हैं। उन्होंने कहा कि देश के सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के बीच आपसी भाईचारा कायम रहना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी शांति और सद्भाव का वातावरण बना रहना जरूरी है। नागराज गौड़ा ने आरएसपुरा प्रवास के दौरान गीता भवन में स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज से भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान वह अरविंद केजरीवाल, जीतन राम मांझी, मनोज तिवारी और दिग्विजय सिंह सहित कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों से मिल चुके हैं।

हथियार लाइसेंस घोटाले में दो आईएएस अधिकारियों को झटका

भारतेन्दु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने हथियार लाइसेंस घोटाले से जुड़ी जनहित याचिका में हस्तक्षेप की मांग करने वाले दो आईएएस अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी है। अधिकारियों ने केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की थी कि सीबीआई की ओर से उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने के प्रस्ताव पर फैसला लेने से पहले उनके अभ्यावेदनों पर विचार किया जाए। मुख्य न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह का निर्देश देने का कोई औचित्य नहीं है। पीठ ने टिप्पणी की कि अधिकारियों की दलील का अर्थ यह है कि न्यायालय के निर्देश के बिना संबंधित विभाग उचित विचार नहीं करेंगे, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जम्मू-कश्मीर के दूरदराज इलाकों में खुलेंगी नई राशन दुकानें, वितरण व्यवस्था होगी आधुनिक

भारतेन्दु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राशन लेने के लिए अब कई किलोमीटर की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दायरे से बाहर रह गई बस्तियों तक राशन पहुंचाने के लिए नई उचित मूल्य की दुकानें (फेयर प्राइस शॉप्स) खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए मौजूदा दुकानों का युक्तिकरण भी किया जाएगा, ताकि प्रत्येक क्षेत्र की जरूरत के अनुसार राशन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। जनता की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। विभाग नई दुकानें खोलने और पहले से संचालित दुकानों की व्यवस्था में सुधार के लिए दो स्तरों पर काम कर रहा है। इसके तहत दुकानों की आर्थिक व्यवहार्यता, उनसे जुड़े राशन कार्डों की संख्या और भौगोलिक पहुंच को प्रमुख आधार बनाया जाएगा। विशेष रूप से दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों की बस्तियों को पर्याप्त कवरेज देने पर ध्यान रहेगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कमिश्नर सचिव सौरभ भगत ने बताया कि नई राशन दुकानों का आवंटन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए 19 जनवरी 2023 के एसओ-41 को आधार बनाया गया है। नियमों के मुताबिक दुकान आवंटन के लिए आवेदक का कम से कम बारहवीं पास होना जरूरी है। उसकी आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह संबंधित क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए। दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों और महिला समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में एक हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। दुकान खोलने से पहले संबंधित क्षेत्र के राशन कार्डों की संख्या, दुकान की आर्थिक व्यवहार्यता और लोगों की भौगोलिक पहुंच का आकलन किया जाएगा।

केंचुआ खाद से खेती कर पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बने किसान

भारतेन्दु संवाददाता, बिश्नाह। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल के बीच जम्मू के बिश्नाह क्षेत्र के वार्ड नंबर आठ निवासी किसान सतीश भारती जैविक खेती को अपनाकर दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। वह पिछले 25 वर्षों से केंचुआ खाद के माध्यम से खेती कर रहे हैं। अपनी तीन एकड़ भूमि पर विभिन्न प्रकार की सब्जियां और अन्य फसलें उगाकर उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल खेती की मिसाल पेश की है। साथ ही आसपास के किसानों को भी जैविक खेती के फायदे बताकर इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

सतीश भारती अपने खेतों में आलू, पालक, मटर, शलगम और विभिन्न प्रकार के साग सहित कई सब्जियों की पैदावार कर रहे हैं। इन फसलों के लिए वह रासायनिक खादों के बजाय केंचुआ खाद और स्वयं तैयार की गई जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं। उनकी खेती को देखने और उनके प्रयासों की जानकारी लेने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी भी कई बार खेतों का दौरा कर चुके हैं।

सतीश भारती ने बताया कि वह करीब 25 वर्षों से केंचुआ खाद तैयार कर उसी के माध्यम से खेती कर रहे हैं। उन्होंने रासायनिक खाद, यूरिया और कीटनाशकों के इस्तेमाल से दूरी बनाई हुई है। उनका मानना है कि रासायनिक पदार्थों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती अपनाने से मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद मिलती है और गुणवत्तापूर्ण फसल तैयार की जा सकती है। किसानों को केवल रासायनिक खादों पर निर्भर रहने के बजाय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ाना चाहिए।

मीरवाइज लगातार दूसरे जुमे पर नजरबंद

लगातार पाबंदियों पर मीरवाइज ने कश्मीर में सामान्य स्थिति के दावों को घेरा

भारतेन्दु संवाददाता, श्रीनगर

कश्मीर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में लगातार दूसरे शुक्रवार भी मीरवाइज-ए-कश्मीर डॉ. मौलवी मोहम्मद उमर फारूक जुमे की नमाज के अवसर पर नमाजियों को संबोधित नहीं कर सकेंगे। वह पिछले करीब एक सप्ताह से श्रीनगर के निगीन स्थित अपने आवास में नजरबंद हैं। उनके घर के बाहर पुलिस की तैनाती और बैरिकेडिंग किए जाने के कारण उन्हें बाहर निकलने तथा जामा मस्जिद जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। लगातार जारी पाबंदियों के चलते वह धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं।

मीरवाइज ने शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह से उन्हें उनके आवास में नजरबंद रखा गया है। घर के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ बैरिकेडिंग भी की गई है। इसके कारण वह लगातार दूसरे शुक्रवार को जामा मस्जिद में नमाजियों को संबोधित करने से वंचित रहेंगे। उन्होंने इस स्थिति पर अफसोस जताते हुए अपनी आवाजाही पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर सवाल उठाए।

मीरवाइज ने अपनी पोस्ट में कश्मीर में सामान्य स्थिति होने के सरकारी दावों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि आवाजाही और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाले मनमाने तथा सत्तावादी कदम वास्तविक स्थिति को सामने लाते हैं। उनके अनुसार, जब किसी धार्मिक नेता को अपने धार्मिक दायित्वों का निर्वहन करने और लोगों के बीच अपनी बात रखने की अनुमति नहीं मिलती, तो ऐसे में सामान्य स्थिति के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने अपनी नजरबंदी को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की पाबंदियां लोगों की स्वतंत्रता और सार्वजनिक गतिविधियों में भागीदारी को प्रभावित करती हैं।



छापेमारी पाकिस्तान से संचालित नेटवर्क पर संदेह, प्रतिबंधित संगठनों से युवाओं को जोड़ने की कोशिशों की पड़ताल

कश्मीर में आतंकी भर्ती नेटवर्क पर सीआईके की छापेमारी

भारतेन्दु संवाददाता, श्रीनगर

कश्मीर में युवाओं को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कथित तौर पर आतंकी संगठनों में शामिल करने की कोशिशों के मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) विंग ने जांच तेज कर दी है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को घाटी के विभिन्न जिलों में छह स्थानों पर एक साथ छापामारी कर संदिग्धों के आवासों की तलाशी ली गई। जांच एजेंसी का उद्देश्य कथित आतंकी भर्ती नेटवर्क से जुड़े लोगों, उनकी गतिविधियों और उनके संपर्कों के बारे में महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाना है।

अधिकारियों के अनुसार, सीआईके की अलग-अलग टीमों ने बडगाम, श्रीनगर, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहाड़ा और मट्टन तथा पुलवामा जिले के एक गांव में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों के आवासों की बारीकी से जांच की गई। पूरी कार्रवाई स्थानीय पुलिस और राजस्व अधिकारियों के समन्वय से की गई। तलाशी के दौरान कार्यकारी मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे, ताकि कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

◆ डिजिटल माध्यमों से आतंकी संगठनों में भर्ती की साजिश की जांच तेज

अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन सीआईके श्रीनगर में वर्ष 2023 में दर्ज एक प्राथमिकी के तहत चल रही जांच का हिस्सा है। संबंधित मामला कथित तौर पर ऐसे आतंकी भर्ती मॉड्यूल से जुड़ा है, जो इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित करने और प्रतिबंधित आतंकी संगठनों में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। जांच एजेंसी इस नेटवर्क की कार्यप्रणाली, इसके स्थानीय संपर्कों और युवाओं तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे माध्यमों की पड़ताल कर रही है।



जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, एजेंसियों को ऐसी सूचनाएं मिली थीं कि पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग लश्कर-ए-तैयबा और अन्य प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के हैंडलरों के कथित सहयोग से कश्मीरी युवाओं को निशाना बना रहे थे। आरोप है कि इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं से संपर्क स्थापित किया जा रहा था। इसके बाद उन्हें अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करने, बहलाने-फुसलाने और कट्टरपंथी विचारधारा की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ भड़काने के प्रयास भी किए जा रहे थे।

सीआईके इस पूरे मामले में इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग और कथित आतंकी भर्ती नेटवर्क की भूमिका को प्रमुखता से जांच रही है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस गतिविधि में कौन-कौन लोग शामिल हैं और संदिग्धों के बीच किस तरह का संपर्क बना हुआ था। इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि कथित नेटवर्क को संचालित करने वाले लोगों के स्थानीय स्तर पर कौन-कौन से संपर्क थे और युवाओं को अपने प्रभाव में लेने के लिए किन माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा था।

लोकतंत्र की घर

वापसी कब हुई थी, और अब फिर उसे बचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है?



देश वर्ष 1947 में आजाद हुआ था। इसके बाद देश में संविधान लागू हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई और जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला। लोकतंत्र की इस व्यवस्था में जनता सर्वोच्च मानी गई और संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान किए। सत्ता के गठन से लेकर सरकार की जवाबदेही तय करने तक, हर महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए संवैधानिक प्रावधान बनाए गए। इसका उद्देश्य ऐसी व्यवस्था स्थापित करना था, जिसमें जनता की इच्छा सर्वोपरि हो और सत्ता किसी एक व्यक्ति या राजनीतिक दल की निजी संपत्ति बनकर न रह जाए। लेकिन आज देश की राजनीतिक तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी पदयात्रा निकालकर लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है और कांग्रेस भी पदयात्रा निकालकर लोकतंत्र बचाने का संदेश दे रही है। ऐसे में आम जनता के मन में एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर लोकतंत्र को बचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है?

आजादी के बाद से देश ने अनेक राजनीतिक उतार-चढ़ाव देखे हैं। अलग-अलग दलों की सरकारें बनीं, सत्ता परिवर्तन हुआ, चुनाव हुए और लोकतांत्रिक संस्थाओं ने अपनी भूमिका निभाई। इसके बावजूद आज राजनीतिक दलों को लोकतंत्र बचाने के लिए उसे सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आजादी के बाद से लोकतंत्र कहीं चला गया था? क्या अब राजनीतिक दल उसकी घर वापसी कराने के लिए पदयात्राएं निकाल रहे हैं? या फिर लोकतंत्र अपनी जगह मौजूद है, लेकिन सत्ता और विपक्ष के बीच उसकी परिभाषा बदलती रहती है? यदि लोकतंत्र सुरक्षित है तो उसे बचाने की इतनी चिंता क्यों दिखाई दे रही है और यदि खतरा है तो उस खतरे का वास्तविक कारण क्या है?



विकास बलूनी

भाजपा कहती है कि लोकतंत्र बचाना है। कांग्रेस भी कहती है कि लोकतंत्र बचाना है। दोनों ही दल लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को अपना महत्वपूर्ण राजनीतिक उद्देश्य बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि खतरा किससे है? क्या खतरा सत्ता पक्ष से है? क्या विपक्ष की भूमिका से लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है? क्या चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठने के कारण लोकतंत्र खतरे में है? या फिर लोकतंत्र के नाम पर जनता के वास्तविक मुद्दों को पीछे छोड़ दिया जा रहा है? इन सवालों का जवाब केवल राजनीतिक नारों और पदयात्राओं से नहीं मिल सकता। इसके लिए राजनीतिक दलों को अपने कामकाज, विचारों और व्यवहार का भी आकलन करना होगा। लोकतंत्र केवल चुनाव कराने या सरकार बनाने तक सीमित व्यवस्था नहीं है। इसमें जनता की आवाज सुनना, असहमति का सम्मान करना, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता बनाए रखना और सत्ता को जवाबदेह बनाना भी उतना ही आवश्यक है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वह संविधान की मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करे। वहीं विपक्ष का दायित्व है कि वह जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाए और सरकार की नीतियों की रचनात्मक समीक्षा करे। दोनों की भूमिका अलग-अलग हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी दोनों पर समान रूप से है।

एआई निर्मित चित्र।

लोकतंत्र किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं है। यह जनता का अधिकार, संविधान की व्यवस्था और संस्थाओं की जवाबदेही का नाम है। इसकी मजबूती राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि व्यवहार, पारदर्शिता, स्वतंत्र संस्थाओं और जनता के प्रति उत्तरदायित्व से तय होती है। जनता को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और विकास जैसे मुद्दों पर भी स्पष्ट जवाब चाहिए। इसलिए लोकतंत्र बचाने की बात करने वाले राजनीतिक दलों को यह भी बताना होगा कि वे इन सवालों पर क्या कर रहे हैं। अंतत: जनता का सवाल यही है कि लोकतंत्र बचाने की पदयात्रा निकालने वालों, जरा यह भी बताइए कि लोकतंत्र को आखिर खतरा किससे है? क्या केवल एक-दूसरे पर सवाल उठाने से लोकतंत्र मजबूत होगा या इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी?

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

अकादमिक शिक्षा और वास्तविक शिक्षा बच्चों के विकास में दोनों महत्वपूर्ण

हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 99 प्रतिशत आंकी गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित माप के अनुसार 95 प्रतिशत से अधिक है। शानदार उपलब्धि है। शिक्षा के स्तर को सुधारने और विस्तार के उद्देश्य में प्रदेश हमेशा प्रत्यनशील रहा है। अकादमिक शिक्षा के अलावा क्या वास्तविक शिक्षा प्रदान करने में सफल हुए हैं या नहीं? विचारणीय है।

आखिर वास्तविक शिक्षा है क्या? केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक ज्ञान बच्चों को दिया जाना वास्तविक शिक्षा है। चरित्र निर्माण, नैतिकता, बुद्धिमत्ता, समाज के प्रति जिम्मेवारी, व्यवहारिक संस्कार आदि गुण किशोरावस्था में विकसित होना जरूरी है।

युवावस्था में बेहतर इंसान बनने का है, जो जीवन में चुनौतियों का धैर्य से हल निकालने में सफल रहे। अनुशासित जीवन बिताएं और कुसंगतियों से दूर रहे। वैसे नियमित पढ़ाई के साथ स्कूलों में खेल, संगीत, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती हैं, जो बच्चों के विकास में सहयोग देती है, लेकिन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए वास्तविक शिक्षा महत्वपूर्ण है।

शिक्षा समाज का स्तंभ है। क्या सोचना है, शिक्षा सिखाती है। परंतु कैसे सोचना है, शिक्षा नहीं सिखाती। किताबों में लिखी प्रत्यक्ष जानकारी के साथ अप्रत्यक्ष जानकारी उदाहरण सहित यदि बच्चों को दी जाती है, तो सोने पर सुहागा जैसी कहावत चरितार्थ होती रहेगी। बाहरी जानकारी उदाहरणों के साथ पाठ्यक्रम में संवाद विधि अपनाना बच्चों के हित में है। अकादमिक ज्ञान सफल करियर के लिए जरूरी है, परंतु उतना ही जरूरी है, जिम्मेदारी संभालने, व्यवहारिक ज्ञान, जो सिखाता है कि समाज में कैसे जीना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे सामने आ रही बाधाओ से पार पाना है। माता-पिता और शिक्षक मार्गदर्शक बनकर बच्चों को प्यार के साथ सही और गलत का फर्क बताते रहे। अनुचित दबाव के बिना पढ़ाई ज्ञान के लिए प्रेरित करें। जो उपदेश दे, समझानी दे, उस तरह का आचरण पहले स्वयं अपनाएं। हमारे आचरण से बच्चे जल्दी सिखते है। कठोरता जरूरी है परंतु क्रोध के साथ नहीं।



एआई निर्मित चित्र।



योगिन्द्र पाल वालिया

अत्यधिक क्रोध और अत्यधिक प्यार दोनों उचित नहीं होते। बच्चों की आंतरिक शक्तियों को स्वयं बाहर निकलने में मदद करें। हमेशा पढ़ाई ज्ञान में बैठाए रखना उचित नहीं होता है। समय प्रबंधन तय करें, जिससे बच्चा अनुशासन और समय के महत्व को समझे। बच्चा अपना कार्य स्वयं करें, इसके लिए जिम्मेदारी तय करें। बच्चों को एकाकी जीवन व्यतीत करने से बचाए।

अन्य बच्चों के साथ समय व्यतीत करने दें, जहां उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आपसी सहयोग करना सीखता है। रास्ता चुनने में मदद करते रहे। प्रत्येक कार्य करने का एक समय निर्धारित होता है। इसलिए कम उम्र में ही बच्चों से ज्यादा की उम्मीद न करें। ध्यान रखना होगा की अनुचित दबाव से बच्चो का बचपन प्रभावित ना हो। यही वास्तविक शिक्षा है। बच्चे दो नावों पर सवार होकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक नाव विद्यालय है, जहां उनका अधिकांश किशोरावस्था का समय व्यतीत होता है और उन्हें अकादमिक ज्ञान प्राप्त होता है।

दूसरी नाव घर-परिवार है, जहां वे सामाजिक व्यवहार, संस्कार और जीवन मूल्यों को सीखते हैं। यद्यपि कहा जाता है कि दो नावों पर सवार होकर सफलता नहीं मिलती, परंतु किशोरावस्था में ये दोनों ही बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। स्कूल और घर-दोनों के वातावरण का बच्चों के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था में सीखी गई बातें आगे युवावस्था में व्यवहार का रूप ले लेती हैं। बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, जिन्हें जैसा आकार दिया जाए, वे वैसे ही ढल जाते हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

अतीत की दास्तान बन चुका कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार और पलायन

कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार और पलायन



एआई निर्मित चित्र।

कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार और उनका सामूहिक पलायन भारत के इतिहास की सबसे पीड़ादायक और शर्मनाक त्रासदियों में से एक है। यह केवल एक समुदाय का विस्थापन नहीं था, बल्कि सभ्यता, संस्कृति और मानवता पर किया गया संगठित हमला था। सन् 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के सैन्य हुक्मरान और सियासी नेतृत्व अपनी आंतरिक विफलताओं, गरीबी और अस्थिरता से जूझती आवाम का ध्यान भटकाने के लिए जम्मू-कश्मीर पर कब्जे का सपना दिखाते रहे हैं। इसी उद्देश्य से पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध लगातार शत्रुतापूर्ण नीतियां अपनाईं।

पाकिस्तान ने 1947, 1965, 1971 और 1999 में जम्मू-कश्मीर पर सैन्य आक्रमण किए, लेकिन हर बार भारतीय सेना के सशक्त प्रतिकार के सामने उसे शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। प्रत्यक्ष युद्ध में विफल होने के बाद पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई के माध्यम से भारत के खिलाफ 'प्रॉक्सी वॉर' की नीति अपनाई और आतंकवाद को अपनी राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बना लिया। नियंत्रण रेखा के पास पीओके में आतंकी प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए गए, जहां युवाओं को धार्मिक उन्माद के नाम पर भर्ती किया गया।

1980 के दशक में पाकिस्तान के सैन्य शासक जनरल जिया-उल-हक और आईएसआई प्रमुख अख्तर अब्दुर रहमान ने 'ऑपरेशन टोपैक' नामक योजना तैयार की, जिसका उद्देश्य कश्मीर घाटी में आतंक फैलाकर भारत को अस्थिर करना था। इस योजना के अंतर्गत आतंकियों को हथियार, प्रशिक्षण और वैचारिक समर्थन दिया गया। धार्मिक नेताओं ने युवाओं को जिहाद और जन्नत के भ्रमजाल में फंसाकर एके-47 थमा दीं। परिणामस्वरूप, शांत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कश्मीर घाटी आतंक की प्रयोगशाला में बदल दी गई। 1989-90 के दौरान कश्मीर में लक्षित हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। टीका लाल टपलू, नीलकंठ गंजू, प्रेम नाथ भट, शीला टिक्कू और गिरिजा टिक्कू जैसी अनेक नृशंस हत्याएं इस आतंक का प्रतीक बनीं।



प्रताप सिंह पटियाल

25 जनवरी 1990 को श्रीनगर में वायुसेना के निहत्थे जवानों की हत्या ने स्थिति की भयावहता को उजागर कर दिया। आतंकियों द्वारा फैलाए गए भय, धमकियों और हत्याओं के कारण 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी हिंदुओं को अपनी पुश्तैनी भूमि, घर और सभ्यता छोड़कर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। विडंबना है कि कश्मीर में आतंक के उस भयावह के दौर में जम्मू-कश्मीर की प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस, न्यायपालिका और राजनीतिक नेतृत्व आतंकवाद के सामने पूरी तरह असफल सिद्ध हुए। कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याओं, महिलाओं के साथ हुए अमानवीय अत्याचारों और सामूहिक पलायन जैसी भीषण त्रासदी पर न तो समय रहते प्रभावी कदम उठाए गए और न ही पीड़ितों को न्याय मिल सका।

इससे भी अधिक पीड़ादायक तथ्य यह रहा कि इस मानवीय संकट पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र और तथाकथित मानवाधिकार संगठनों ने लगभग पूर्ण चुप्पी साधे रखी। देश के भीतर भी अनेक राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक संगठनों ने इस विषय पर मौन रहकर अपनी नैतिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। आज भी यह प्रश्न उतना ही प्रासंगिक है कि पिछले 36 वर्षों से अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जी रहे कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी वापसी कब संभव होगी। क्या राज्य और केंद्र सरकार मिलकर उनके पुनर्वास के लिए कोई ठोस, दीर्घकालीन और प्रभावी नीति बनाएंगी? कश्मीरी पंडितों को केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि न्याय, सुरक्षा और पुनर्स्थापन का अधिकार चाहिए।

इस समूची त्रासदी के बीच राष्ट्र को उन हजारों भारतीय सैनिकों के बलिदान को भी स्मरण रखना चाहिए, जिन्होंने आतंकवाद से लड़ते हुए कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखा। यह त्रासदी केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान के लिए एक गंभीर चेतावनी है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

पति पत्नी का रिश्ता : समझदारी, सम्मान और साथ का रिश्ता



एआई निर्मित चित्र।

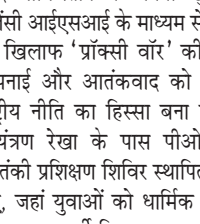
पति और पत्नी का रिश्ता बहुत खास होता है। पति-पत्नी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। यह रिश्ता केवल दो दिलों का नहीं, बल्कि दो परिवारों, दो सपनों और दो सोच का मिलन होता है। जब दो लोग शादी के बंधन में बंधते हैं, तो वे सिर्फ एक-दूसरे के जीवनसाथी नहीं बनते, बल्कि जीवनभर के दोस्त भी बन जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि शादी का मतलब साथ रहना है, लेकिन असल में शादी का मतलब एक-दूसरे का साथ निभाना है। यह सफर हमेशा आसान नहीं होता, पर समझदारी, प्यार और विश्वास के साथ इसे खूबसूरत बनाया जा सकता है।

शादी के बाद अक्सर पति-पत्नी बनने की जल्दी में हम दोस्त बनना भूल जाते हैं, जबकि दोस्ती ही वह नींव है, जिस पर पूरा रिश्ता टिका होता है। दोस्त वह होता है, जिससे हम बिना किसी डर के अपनी हर बात कह सकते हैं। यदि पति-पत्नी एक-दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन जाएं, तो उनके जीवन में अकेलेपन की जगह अपनापन आ जाता है। वे अपने दुख, खुशी, परेशानियां और सपने बेझिझक साझा कर सकते हैं। दोस्ती में कोई छोटा-बड़ा नहीं होता, न कोई मालिक होता है और न कोई नौकर, बल्कि दोनों के बीच बराबरी होती है।

जब रिश्ते में दोस्ती होगी, तो सम्मान अपने आप बढ़ेगा।

हम अक्सर बाहर के लोगों को धन्यवाद कहते हैं, लेकिन अपने जीवनसाथी के योगदान को नजरअंदाज कर देते हैं। पत्नी पूरे दिन घर संभालती है, बच्चों की देखभाल करती है और परिवार के लिए खाना बनाती है, तो उसे यह कहना जरूरी है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। इसी तरह पति दिनभर मेहनत करता है और परिवार की जिम्मेदारियां निभाता है, तो पत्नी को भी उसकी मेहनत की कद्र करनी चाहिए। ये छोटे-छोटे शब्द रिश्ते में मिठास लाते हैं। अगर कभी गलती हो जाए, तो सॉरी कहने में भी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि रिश्ते के प्रति अपने प्यार और सम्मान को दिखाने का तरीका है। शुक्रिया और सॉरी जैसे दो छोटे शब्द रिश्ते को हमेशा नया और ताजा बनाए रखते हैं।

आज के समय में हर कोई व्यस्त है। पति अपने काम में व्यस्त है, पत्नी घर और काम दोनों की जिम्मेदारियां निभाती है और बच्चे पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में अगर हम अपने रिश्ते को समय नहीं देंगे, तो धीरे-धीरे दूरियां बढ़ने लगेंगी। इसके लिए रोज घंटों निकालने की जरूरत नहीं है। दिन में केवल बीस मिनट एक-दूसरे के लिए निकालिए। मोबाइल और टीवी को थोड़ी देर के लिए अलग रखकर साथ बैठिए, चाय पीजिए और दिनभर की बातें साझा कीजिए। बच्चों, परिवार और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कीजिए। साथ में टहलना, खाना बनाना या कोई छोटा काम करना भी रिश्ते को मजबूत बनाता है।



वीरेन ठाकुर

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

आत्ममंथन

हीरा सिंह कौशल,
गांव व डाकखाना महादेव, सुंदरनगर

हे मन हर रोज अपने कर्मों
का आत्मंथन किया कर।
कर्मों को ज्ञान की रोशनी
से सुर्ख रूह किया कर।।
बसा हो रोग मन में सत्संग में
आकर दूर किया कर।
संतजनों के वचनों को हू-ब-हू
मान जीवन में अपनाया कर।।
कमियां न देख किसी की दिल में
बसी द्वेष ईर्ष्या दूर किया कर।
दूसरे की खूबियां ही नजरों में रहे
दातार से दुआ किया कर।।
काम, क्रोध, मोह, ममता
ज्ञान की रोशनी से काबू किया कर।
सत्संग में हरपल का शुक्रिया
दातार की रहमत से किया कर।।
आत्ममंथन से निंदा छोड़ दातार
की दातों का गुणगान किया कर।
जाति, धर्म को छोड़
इंसानियत को अपना लिया कर।।
भ्रमों की उलझनों से सतगुरु के
दर पे आके पार किया कर।
कौशल स्वयं के आत्मंथन से
आत्म सुधार कर लिया कर।।

संपादकीय

राजनीति में भाषा की मर्यादा जरूरी

संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच वैचारिक मतभेद तथा एक-दूसरे की नीतियों की आलोचना होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का सरकार से सवाल करना और सत्ता पक्ष का अपनी नीतियों का बचाव करना जरूरी है। हालांकि राजनीतिक विरोध के दौरान भाषा की मर्यादा और सार्वजनिक जीवन की गरिमा बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की राजनीति की आलोचना करते हुए कहा कि नकारात्मक राजनीति के चलते पार्टी अगले 30 वर्षों तक केंद्र की सत्ता में वापस नहीं आ सकती। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन उनकी भाषा में व्यक्तिगत अपमान या अमर्यादित टिप्पणी नहीं थी। इसके विपरीत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पटना के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। कार्यकर्ता के टोकने पर उनका गुस्से में दिया गया बयान राजनीतिक मर्यादा के सवाल खड़े करता है। चिंता की बात यह भी रही कि कांग्रेस के नेताओं ने इस टिप्पणी पर खेद जताने के बजाय उसका बचाव करने का प्रयास किया।

राजनीति में चुनाव जीतने के लिए किसी भी दल को मजबूत संगठन, स्पष्ट विचारधारा और जनता के विश्वास की आवश्यकता होती है। इसके लिए जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाना, सकारात्मक नीतियां प्रस्तुत करना और ऐसा नेतृत्व देना जरूरी है, जिस पर मतदाता भरोसा कर सकें। राजनीतिक विरोधियों की आलोचना नीतियों और कार्यों के आधार पर होनी चाहिए, न कि उनके परिवार या व्यक्तिगत जीवन को निशाना बनाकर। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शब्दों और व्यवहार से समाज के सामने जिम्मेदार उदाहरण प्रस्तुत करें।

चुनाव में हार-जीत लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी स्थापना के बाद राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता तक पहुंचने के लिए लंबा राजनीतिक संघर्ष करना पड़ा। जनसंघ से भाजपा तक के सफर में पार्टी ने कई चुनावी पराजय देखीं, लेकिन समय के साथ अपनी संगठनात्मक क्षमता, विचारधारा और चुनावी रणनीति को मजबूत किया। इसके विपरीत कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को लेकर सवाल उठते रहे हैं। वर्ष 2014 के बाद पार्टी लगातार कई चुनावों में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाई है। ऐसी स्थिति में उसे अपनी नीतियों, संगठन, नेतृत्व और चुनावी रणनीति की गंभीर समीक्षा करनी चाहिए थी। चुनावी हार का कारण केवल विरोधियों की ताकत या संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका को बताने से राजनीतिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता।

कांग्रेस के भीतर अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं की भूमिका को लेकर भी समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। पार्टी में संगठनात्मक अनुभव रखने वाले नेताओं और नए राजनीतिक सलाहकारों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। किसी भी राजनीतिक दल को अपनी रणनीति बनाते समय देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को समझना चाहिए। केवल विरोध की राजनीति के सहारे लंबे समय तक जनता का विश्वास हासिल करना मुश्किल है। राहुल गांधी और उनके सहयोगियों की ओर से ईवीएम, एसआईआर और कथित वोट चोरी जैसे मुद्दे लगातार उठाए जाते रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन ऐसे आरोपों के समर्थन में ठोस तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत करना भी उतना ही जरूरी है। बिना पर्याप्त प्रमाण के संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठाने से जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर आयोजित मॉक पार्लियामेंट और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की मांग से जुड़े राजनीतिक प्रयासों को लेकर भी बहस हुई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध और असहमति के अनेक तरीके हैं, लेकिन किसी भी अभियान का आधार तथ्य, संवैधानिक प्रक्रिया और शांतिपूर्ण संवाद होना चाहिए। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि संस्थाओं की आलोचना और उनकी विश्वसनीयता को कमजोर करने के बीच अंतर होता है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में कमियां हों तो उन्हें उचित मंच पर उठाया जाना चाहिए।

राहुल गांधी के कई पुराने राजनीतिक बयानों को लेकर भी विवाद होता रहा है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री को लेकर की गई व्यक्तिगत टिप्पणियां हों या बाद में उन्हें चोर कहने का राजनीतिक नारा, इनसे राजनीतिक संवाद की गुणवत्ता पर सवाल उठे। इसी तरह कांग्रेस के अन्य नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री के लिए की गई विवादित टिप्पणियां भी पार्टी की छवि को प्रभावित करती रही हैं। खरगे द्वारा प्रधानमंत्री की तुलना रावण और जहरीले नाग से करने जैसे बयानों पर भी राजनीतिक विवाद हुआ। नेताओं को यह समझना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों का प्रभाव केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम नागरिकों के बीच भी संवाद की संस्कृति को प्रभावित करता है।

-शिवांश धाकड़

आज की प्रमुख हस्ती

दुनिया में दमदार पहचान

भारतीय अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी दक्षिण भारतीय सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हैं। उनका असली नाम स्वीटी शेट्टी है। उनका जन्म 7 नवंबर 1981 को कर्नाटक के मंगलुरु में हुआ था। दो दशक से अधिक लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने तमिल और तेलुगु फिल्मों में अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। मीडिया में उन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा की क्वीन के रूप में भी पहचाना जाता है। अभिनय के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें तीन फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण, दो नंदी पुरस्कार, दो साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवॉर्ड और एक तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। वर्ष 2010 में तमिलनाडु सरकार ने उन्हें कलैमामणि सम्मान से नवाजा था।



अनुष्का शेट्टी
जन्म : 7 नवंबर 1981

अनुष्का ने वर्ष 2005 में तेलुगु फिल्म 'सुपर' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। इस फिल्म में उनके अभिनय को सराहना मिली और उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकन भी मिला। वर्ष 2006 में उन्होंने एसएस राजामौली की फिल्म 'विक्रमारकुडु' में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद 'लक्ष्यम', 'सौर्यम' और 'चिंताकायला रवि' जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता बढ़ाई।

वर्ष 2009 में आई फिल्म 'अरुंधति' उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई और अपने प्रभावशाली अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार और नंदी पुरस्कार मिला। वर्ष 2010 में फिल्म 'वेदम' में निभाए गए चुनौतीपूर्ण किरदार के लिए उन्हें लगातार दूसरी बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ। तमिल सिनेमा में भी उन्होंने 'वेट्टैक्कारण', 'सिंघम', 'सिंघम-2' और 'येन्नई अरिंदाल' जैसी सफल फिल्मों में अभिनय किया। 'वानम', 'दैव तिरुमगल' और 'साइज जीरो' में उनके काम को समीक्षकों ने सराहा। वर्ष 2015 में ऐतिहासिक फिल्म 'रुद्रमादेवी' में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें तीसरा फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला।

'भारतेन्दु शिखर'

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

घट्टा टोल प्लाजा पर जनता का महा आंदोलन, करीब दो घंटे तक चक्का जाम

वाहनों की लंबी कतारों में फंसी एंबुलेंस, लोगों को हुई भारी परेशानी

आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। घट्टा टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। रानीताल के समीप स्थित टोल प्लाजा पर क्षेत्रवासियों ने करीब दो घंटे तक चक्का जाम रखा। टोल टैक्स में बढ़ोतरी और स्थानीय लोगों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ के विरोध में किए गए प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गईं।



जाम में एंबुलेंस भी फंस गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। प्रदर्शन में महिलाएं, युवा, पंचायत प्रतिनिधि और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। लोगों ने मांग उठाई कि घट्टा टोल प्लाजा को यहां से हटाया जाए, ताकि चंगर क्षेत्र और आसपास के निवासियों को रोजाना टोल टैक्स के बोझ से राहत मिल सके। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अस्पताल और अन्य जरूरी कामों के लिए उन्हें बार-बार इस मार्ग से गुजरना पड़ता है। ऐसे में हर बार टोल देना आर्थिक परेशानी बढ़ाता है।

जनता के समर्थन में एक मंच पर दिखे नेता: प्रदर्शन में विधायक पवन काजल, हिमाचल पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष अजय वर्मा और भाजपा नेता मनीष शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं, बल्कि जनता की आवाज है। जनता की मांग के साथ खड़े होना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। इस मंच पर राजनीति नहीं होगी और लोगों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।

संघर्ष समिति ने किया था आंदोलन का ऐलान: घट्टा टोल प्लाजा संघर्ष समिति ने पहले ही छह नवंबर को बड़े आंदोलन की घोषणा की थी। समिति का कहना है कि यह पूरे चंगर क्षेत्र और आसपास के लोगों की सामूहिक लड़ाई है। देहरा सहित अन्य क्षेत्रों में आने-जाने वाले लोगों को भी टोल के कारण आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निजी गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों को वैध फास्टैग के आधार पर मासिक और सालाना पास की सुविधा मिल सकती है।

हालांकि, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पास से मूल समस्या हल नहीं होगी। उनकी मांग टोल प्लाजा हटाने की है। लोगों ने चेतावनी दी कि ठोस निर्णय नहीं होने तक आंदोलन जारी रह सकता है। प्रदर्शन में जिला परिषद सदस्य विनोद बराड़, वीरेंद्र चौधरी, रमेश बराड़, कुलभाष चौधरी, रिंकू चौधरी, निशांत चौधरी और राजेश परयाल सहित कई पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे।

जिला हमीरपुर के मुख्य बाजारों में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिह्नित

सुरेंद्र कटोच, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। त्योहारी सीजन के दौरान आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने हमीरपुर के मुख्य बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री एवं भंडारण के लिए अलग-अलग स्थान चिह्नित किए हैं। जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इन निर्धारित स्थानों पर ही लाइसेंस प्राप्त दुकानदार पटाखों की बिक्री कर सकेंगे।



आदेश के अनुसार, हमीरपुर शहर में ट्राला यूनियन, बीएसएनएल कार्यालय के पास, गलोडा अस्पताल के निकट, हथली पुल, नालटी चौक से पक्का भरो सड़क पर बावड़ी के पास और नए बस अड्डे के समीप पटाखों की दुकानें लगाई जा सकेंगी। इसके अलावा खसग्रां-चौकी सड़क, मुठान भलियाणा, ताल कुश्ती अखाड़ा, टौणी देवी, उहल, जंदड़ू, अवाह देवी, कक्कड़, लंबलू और सुजानपुर सहित अन्य क्षेत्रों में भी स्थान निर्धारित किए गए हैं। मैहरे, बड़सर, बिझड़ी, भोटा, सलौणी, चकमोह, भरेड़ी, जाहू, भोरंज, सुलगवान, तरक्वाड़ी, पट्टा, लदरौर, नादौन, गलोड़ और कांगू में भी पटाखों की बिक्री के लिए मैदान और खुले स्थान चिह्नित किए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एक क्लस्टर में 50 से अधिक दुकानें नहीं लगाई जा सकेंगी। जिलाधीश ने सभी एसडीएम, पुलिस, अग्निशमन और संबंधित विभागों को सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दुकानदारों से भी निर्धारित स्थानों पर लाइसेंस लेने के बाद ही पटाखे बेचने और भंडारण करने की अपील की गई है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाकों में पटाखे न जलाने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की।

न्यूज ब्रीफ

हिमाचल की अंडर-16 टीम विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए तैयार, विजयवाड़ा में दिखाएगी दम

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर-16 के लिए 18 सदस्यीय टीम घोषित की है। शिमला जिले के सांभव शर्मा को कप्तान और मंडी जिले के आदिश मिन्हास को उप-कप्तान बनाया गया है। टीम में शिमला से अथर्व आर्य, नीरव और सान्यम भातुनी, कांगड़ा से भावेश ठाकुर, रियांश ठाकुर और यश चौधरी, मंडी से अर्णव ठाकुर और येश वर्मा शामिल हैं। सोलन से अभिनव शर्मा, समीर लबाना और उदयवीर अटलस, बिलासपुर से अंश गौतम और सुवंश द्विवेदी, कुल्लू से शौर्य और वेदांत शर्मा तथा ऊना से नमिश कालिया चुने गए हैं। टीम विजयवाड़ा में पांच लीग मैच खेलेगी। पहला मुकाबला 14 नवंबर को असम से होगा।

डॉ. रमेश चंद्र मस्ताना के निधन से पहाड़ी भाषा और साहित्य जगत में शोक

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश आर्थर्स गिल्ड के कांगड़ा चैप्टर के अध्यक्ष डॉ. रमेश चंद्र मस्ताना का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन पर आर्थर्स गिल्ड ऑफ हिमाचल के मुख्य संरक्षक एवं पूर्व बागवानी मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। सत्य प्रकाश ठाकुर ने कहा कि डॉ. मस्ताना हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी भाषा के प्रखर विद्वान एवं साहित्यकार थे। पहाड़ी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए उनकी आवाज महत्वपूर्ण थी। वर्ष 2011-12 में उन्हें पहाड़ी भाषा, कला और संस्कृति के योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कांगड़ा बैंक की पूर्व निदेशक प्रेमलता ठाकुर, भुट्टिको के पदाधिकारियों और बुनकर सदस्यों ने भी उनके निधन पर शोक जताया।

झंडूता बाजार में चोरी की वारदात सुलझी उत्तर प्रदेश से आरोपी गिरफ्तार

अमर सिंह, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। झंडूता बाजार में दुकान से करीब पांच लाख रुपये के चांदी के आभूषण चोरी करने के मामले को बिलासपुर पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से मुख्य आरोपी मनोज कुमार उर्फ मोनू (19) को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई चांदी भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार, झंडूता निवासी विपन कुमार ने 18 अक्टूबर को दुकान से आभूषण चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। आरोपियों ने चेहरे ढकने के साथ मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट से भी छेड़छाड़ की थी। जांच में आरोपी मुरादाबाद के निवासी पाए गए। पुलिस ने वहां दबिश देकर मनोज कुमार को गिरफ्तार किया। मामले में शामिल अन्य दो आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस शेष चोरीशुदा चांदी बरामद करने का प्रयास कर रही है।

बिलासपुर में खुलेगा फिश पार्लर, पर्यटकों को मिलेगा हिमाचली व्यंजनों का स्वाद

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिले में मत्स्य विपणन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईटीआई चौक के समीप स्थित जागृति भवन में फिश पार्लर स्थापित किया जाएगा। इसे पर्यटन विभाग के लेक व्यू कैफे के साथ संचालित किया जाएगा। यहां स्थानीय लोगों और पर्यटकों को जीवित व ताजी मछली खरीदने के साथ पारंपरिक हिमाचली मछली व्यंजनों का स्वाद मिलेगा। निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य ओम कांत ठाकुर ने अधिकारियों के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। इस पहल से स्थानीय मछुआरों और मत्स्य सहकारी सभाओं को उत्पादों की बिक्री के लिए नया मंच मिलेगा। साथ ही मत्स्य पालन से जुड़े लोगों के लिए रोजगार और आय के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

जिला स्तरीय युवा उत्सव 17 नवम्बर को

भारतेन्दु संवाददाता, सोलन। जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी भूपेन्द्र वर्मा ने बताया कि 17 नवंबर को चिल्ड्रन पार्क स्थित खेल सभागार में जिला स्तरीय युवा उत्सव आयोजित होगा। इसमें समूह लोकगीत, लोकनृत्य, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला और कविता लेखन प्रतियोगिताएं होंगी। उत्सव की थीम 'विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा' रखी गई है। सोलन जिले के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा भाग ले सकते हैं। इच्छुक प्रतिभागियों को आयु प्रमाणपत्र और आधार कार्ड की छायाप्रति लेकर सुबह 9:30 बजे पहुंचना होगा। प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा।

जनसेवा और जनकल्याण ही राजनीति का ध्येय संतों से मिलती है प्रेरणा : मुकेश अग्निहोत्री

भारतेन्दु संवाददाता, ऊना। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जनसेवा और जनकल्याण ही उनकी राजनीति का मुख्य उद्देश्य है। संतों का आशीर्वाद समाजसेवा की दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है। शुक्रवार को बीटन स्थित श्री लालपुरी विष्णु धाम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने धाम के जीर्णोद्धार के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। यह कार्यक्रम श्री सतगुरु लाल दास जी रकबे वालों के शुभ आगमन दिवस पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने वर्तमान गुरु गद्दीनशीन वेदांताचार्य श्री सतगुरु चेतनानंद जी भूरीवाले से आशीर्वाद प्राप्त किया। अग्निहोत्री ने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि बीटन में 3.69 करोड़ रुपये से दस बिस्तरों वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। खेल मैदान के विकास के लिए दो करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं, तालाब के जीर्णोद्धार पर भी दो करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। पंचायत घर के निर्माण के लिए 1.14 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने अमराली, पोलियां और ढुलैहड़ में बने पेयजल भंडारण टैंकों का भी उल्लेख किया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिमाचल के अधिकारों को मिली मजबूती, 75 लाख जनता को बधाई : मुकेश शर्मा

भारतेन्दु संवाददाता, सोलन। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं अधिवक्ता मुकेश शर्मा ने बीबीएमबी एरियर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए प्रदेश की 75 लाख जनता को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उनके अनुसार, करीब चार वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश हितों से जुड़ी यह चौथी बड़ी उपलब्धि है।



मुकेश शर्मा ने कहा कि बीते 15 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित बीबीएमबी एरियर मामले में आया फैसला हिमाचल प्रदेश के हक और अधिकारों की जीत है। इसका श्रेय प्रदेश की जनता, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, अधिकारियों और सरकार की ओर से पैरवी करने वाली कानूनी टीम को जाता है।

उन्होंने बताया कि फैसले के तहत हिमाचल प्रदेश को बीबीएमबी से एरियर के रूप में करीब 55 से 56 करोड़ यूनिट बिजली मिलने की संभावना है। इसका लाभ आगामी 20 वर्षों तक जारी रह सकता है। उनके अनुसार, इससे प्रदेश को लगभग 15 हजार करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है।

मुकेश शर्मा ने कहा कि यदि बिजली का मूल्यांकन छह रुपये प्रति यूनिट की दर से किया जाए तो प्रदेश को हर वर्ष करीब 500 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ होगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश राजस्थान को 15.50 रुपये, केरल को 14.50 रुपये और तमिलनाडु को 13.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बेच चुका है। भविष्य में इसी तरह की दरों पर बिजली समझौते होने पर प्रदेश की सालाना आय करीब एक हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि यह फैसला प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार होगा। सरकार प्रदेश के संसाधनों और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री जल्द करेंगे शाहपुर अस्पताल के नए भवन का लोकार्पण : केवल सिंह पठानिया

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। शाहपुर के विधायक एवं उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि नागरिक अस्पताल शाहपुर के नए भवन का जल्द ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोकार्पण कर जनता को समर्पित करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के पौने चार वर्ष के कार्यकाल में अस्पताल में करीब 16 करोड़ रुपये खर्च कर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है।



पठानिया शुक्रवार को धनतेरस के अवसर पर अस्पताल में नई एंबुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में यह एंबुलेंस क्षेत्र के लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने अस्पताल के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का आभार जताया। उन्होंने बताया कि नागरिक अस्पताल शाहपुर में शाहपुर के अलावा ज्वाली और भटियात विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को भी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। वर्तमान में यहां 17 चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं और जल्द ही चिकित्सकों के दो रिक्त पद भी भरे जाएंगे। पठानिया ने कहा कि मरीजों को उपचार और ऑपरेशन के लिए टांडा अस्पताल न जाना पड़े, इसके लिए 1.50 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर स्थापित किया गया है, जहां ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा 7.50 लाख रुपये से हाई मास्ट लाइट, 25 लाख रुपये से अल्ट्रासाउंड मशीन और 50 लाख रुपये की लागत से ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित की गई है।

चमत्कारी बाबा बनकर आए ठग, महिला की सोने की बालियां उड़ाई

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट के निकटवर्ती गांव भगवानसर में चमत्कारी बाबा बनकर आए ठग ने एक दंपति को बातों में उलझाकर महिला की सोने की बालियां ठग लीं। आरोप है कि इस वारदात में पांच से छह लोग शामिल थे। ठगों ने बाबा की चमत्कारी शक्तियों का दावा कर दंपति को अपने जाल में फंसाया। पीड़ित रमेश कुमार और उनकी पत्नी दर्शना ने बताया कि गुरुवार शाम वे गांव भोआ से किराना सामान लेकर लौट रहे थे। भगवानसर के बाहर सफेद कपड़ों और पगड़ी में एक व्यक्ति ने उन्हें रोककर शिव मंदिर का रास्ता पूछा। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर एक महिला और युवक पहुंचे। उन्होंने उस व्यक्ति को चमत्कारी बाबा बताते हुए उसकी शक्तियों के किस्से सुनाए। बातों में उलझाकर बाबा ने महिला से सोने की बालियां उतरवा लीं और उन्हें कागज व रुमाल में बांधकर घर जाकर खोलने को कहा। घर पहुंचने पर रुमाल खोलने पर बालियों की जगह भांग के पत्ते मिले।

13 नवंबर को मंडी में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकथॉन प्रस्तावित

रूप लाल कौंडल, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश को चिट्टे जैसे घातक नशे से मुक्त बनाने के उद्देश्य से 13 नवंबर को मंडी में एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकाथॉन आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने शुक्रवार को स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के आईजी बिमल गुप्ता मंडी पहुंचे। उन्होंने उपायुक्त अपूर्व देवगन और पुलिस अधिकारियों के साथ पडुल मैदान का निरीक्षण किया।

आईजी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आयोजन को सफल बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिट्टे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है। इस बुराई को समाप्त करने के लिए हर नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने



◆ चिट्टामुक्त हिमाचल के संकल्प के साथ मंडी में निकलेगी वॉकाथॉन

आम जनता से सरकार की मुहिम में सहयोग देने की अपील की।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि मंडी शहर में जागरूकता रैली और वॉकाथॉन के माध्यम से लोगों, विशेषकर युवाओं को चिट्टे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्रतिभागियों को चिट्टा मुक्त हिमाचल बनाने की शपथ भी दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए विभिन्न स्तरों पर कमेटियां गठित की गई हैं। सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

परिवहन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, साफ-सफाई और नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त प्रियंशु खाती, एडीएम डॉ. मदन कुमार, एसडीएम चंद्र प्रकाश और एएसपी अभिमन्यु वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने वॉकाथॉन में अधिक से अधिक युवाओं और स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक ने विशेष बच्चों के साथ मनाया दीपावली त्यौहार

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पहचान स्पेशल स्कूल, हमीरपुर के परिसर में शुक्रवार को दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह अपनी धर्मपत्नी के साथ विशेष रूप से स्कूल पहुंचे और बच्चों के साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं।

◆ एसपी बलबीर सिंह ने विशेष बच्चों के साथ मनाई दीपावली



एसपी बलबीर सिंह और उनकी धर्मपत्नी ने बच्चों को अपने हाथों से मिठाइयां खिलाईं तथा विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने बच्चों के साथ नृत्य भी किया और उनके उत्साह में शामिल होकर दीपावली के आयोजन को यादगार बनाया। पुलिस अधीक्षक और उनकी धर्मपत्नी को अपने बीच पाकर बच्चे बेहद खुश और उत्साहित नजर आए। इस दौरान स्कूल परिसर में खुशियों, मुस्कान और अपनत्व का माहौल देखने को मिला। एसपी और उनकी धर्मपत्नी ने बच्चों के साथ आत्मीयता से समय बिताया और उनके चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास किया। उनके इस स्नेहपूर्ण व्यवहार से बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दिया।

स्कूल की प्रधानाचार्य चेतना शर्मा ने पुलिस अधीक्षक और उनकी धर्मपत्नी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विशेष बच्चों के साथ त्योहार मनाने से उनमें अपनत्व, आत्मविश्वास और समाज से जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। ऐसे आयोजन बच्चों के जीवन में खुशियों के यादगार पल जोड़ते हैं और उन्हें यह एहसास कराते हैं कि समाज उनके साथ खड़ा है।

पांच किलोमीटर दायरे के वाहनों को टोल छूट देने की उठी मांग : पवन काजल

14 नवंबर को होगी अधिकारियों संग बैठक

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। कच्छयारी-शिमला फोरलेन के तहत घट्टा टोल प्लाजा को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग को लेकर शुक्रवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने टोल प्लाजा हटाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में स्थानीय विधायक एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष पवन काजल सहित कई पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। करीब दो घंटे तक चले जाम के कारण टोल प्लाजा के दोनों ओर हजारों वाहन फंसे रहे। इस दौरान कई एंबुलेंस भी जाम में फंसी रहीं।



पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के आग्रह के बावजूद प्रदर्शनकारी रास्ता खोलने को तैयार नहीं हुए। एसडीएम डॉ. अंजलि गर्ग ने यातायात सुचारू करवाने के लिए करीब आधे घंटे तक टोल प्लाजा के सेंसर भी बंद करवाए। प्रदर्शन के दौरान अलग-अलग समूहों में नारेबाजी भी हुई। विधायक पवन काजल और एसडीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने रास्ता खोल दिया। तय हुआ कि 14 नवंबर को कांगड़ा में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, क्षेत्रीय अधिकारी (आरओ), सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज और संघर्ष समिति के बीच बैठक होगी।

इसमें टोल प्लाजा से जुड़ी समस्या का समाधान निकालने पर चर्चा की जाएगी। विधायक पवन काजल ने कहा कि यदि घट्टा में टोल प्लाजा का निर्माण नियमों के विरुद्ध हुआ है तो इसे हटाया जाएगा। ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है। एसडीएम ने शिमला में एनएचएआई अधिकारियों से बात कर बैठक की तारीख तय करवाई।

सुरक्षा अलर्ट पठानकोट सिटी और कैंट रेलवे स्टेशनों पर संयुक्त टीमों ने चलाया तलाशी अभियान

त्योहारी सीजन में पठानकोट की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, चप्पे-चप्पे पर निगरानी

अशोक ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। त्योहारी सीजन के दौरान पठानकोट में शांति, सुरक्षा और भाईचारा बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सीमावर्ती और संवेदनशील जिला होने के कारण यहां सरहद से लेकर शहर के प्रमुख बाजारों और रेलवे स्टेशनों तक विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और पंजाब पुलिस के जवान संयुक्त रूप से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं। वहीं, जिले में प्रवेश करने वाले मुख्य मार्गों और अंतरराज्यीय सीमाओं पर नाकेबंदी कर वाहनों की सघन जांच की जा रही है।

सीमावर्ती नाकों पर दिन-रात वाहनों की जांच: पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित मीलवां, चक्की पुल और कंडवाल पुलिस नाकों पर सुरक्षा जांच का दायरा बढ़ाया गया है। सब-इंस्पेक्टर दलजीत सिंह की अगुवाई में पुलिस



जवान आने-जाने वाले छोटे-बड़े वाहनों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। दिन और रात दोनों समय वाहनों की तलाशी ली जा रही है। पूरी जांच के बाद ही किसी वाहन को आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। पुलिस का उद्देश्य त्योहारी भीड़ के दौरान किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोकना है। एसपी जगदीश राज अत्री ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। किसी वीआईपी, रसूखदार या राजनीतिक सिफारिश वाले व्यक्ति को भी जांच से छूट नहीं मिलेगी। सुरक्षा और कानून के नियम सभी नागरिकों के लिए समान हैं। उन्होंने कहा कि जिले में शांति बनाए रखने के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है।

रेलवे स्टेशनों पर संयुक्त टीमों का सर्च अभियान: त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए पठानकोट सिटी और पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशनों पर विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। जीआरपी, आरपीएफ, स्थानीय पुलिस और एंटी-सबोटाज स्क्वॉड की संयुक्त टीमों ने रेलवे स्टेशन के विभिन्न हिस्सों की जांच की।

यात्रियों के बैठने वाले हॉल, पार्सल क्षेत्र, साइकिल स्टैंड और प्लेटफार्मों पर मेटल डिटेक्टरों सहित अन्य उपकरणों की मदद से तलाशी ली गई। इसके अलावा संदिग्ध लोगों और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में खुफिया जवानों को भी तैनात किया गया है। जीआरपी थाना प्रमुख सुखविंदर सिंह सरां के अनुसार पठानकोट पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर तीन राज्यों का महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे में दिवाली के पूरे उत्सव तक रेलवे स्टेशनों पर जांच अभियान जारी रहेगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

लावारिस वस्तुओं से दूर रहने की अपील: एसपी जगदीश राज अत्री ने आम लोगों से भी सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बाजारों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कोई लावारिस बैग या संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो उसे छूने से बचें। ऐसी किसी भी वस्तु की जानकारी तुरंत पास मौजूद पुलिसकर्मी या नजदीकी थाने को दें। इसके साथ ही किसी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि के बारे में भी पुलिस को सूचित करें। पुलिस के अनुसार नागरिकों की सतर्कता और सहयोग से ही त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा सकते हैं। त्योहारों के दौरान बाजारों में बढ़ती भीड़ और जाम की समस्या को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। गांधी चौक से डाकखाना चौक तक के व्यस्त क्षेत्र में चौपहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है।

चार्जिंग स्टेशन तैयार जोगिंद्रनगर डिपो को नहीं मिली इलेक्ट्रिक बसें

भारतेन्दु संवाददाता, जोगिंद्रनगर। जोगिंद्रनगर बस अड्डे पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन तैयार हो चुका है, लेकिन क्षेत्र में अभी तक एक भी इलेक्ट्रिक बस का संचालन शुरू नहीं हुआ है। स्टेशन का सिविल कार्य और बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद बसें उपलब्ध न होने से लाखों रुपये की लागत से तैयार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार पड़ा है। जोगिंद्रनगर डिपो प्रबंधन ने उच्च अधिकारियों और सरकार से इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाने की मांग की है। वहीं, डिपो इन दिनों खटारा बसों और कर्मचारियों की कमी से भी जूझ रहा है। यहां चालकों के 16 और मिस्त्री व मैकेनिकों के 10 पद लंबे समय से रिक्त हैं। अन्य श्रेणियों में भी कई पद खाली हैं। स्टाफ की कमी के कारण ग्रामीण और दूरदराज के रूटों पर बस सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कई बसें रखरखाव के अभाव में वर्कशॉप में खड़ी हैं। इससे विद्यार्थियों, कर्मचारियों और ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

न्यूज ब्रीफ

100 रुपए की चाट उधार नहीं देने पर गंडासे और चाकू से हमला

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर-58 में 100 रुपये की चाट उधार नहीं देने पर विवाद हो गया। आरोप है कि चाट उधार मांगने आए युवक ने पहले रेहड़ी संचालक को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद परिवार के सदस्य बीच-बचाव करने पहुंचे तो युवक ने अपने भाई और पिता के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। परिजनों के मुताबिक, आरोपितों ने गंडासे और चाकू से वार किए। इस हमले में रेहड़ी संचालक समेत चार लोग घायल हो गए। हमले के दौरान एक युवक का कान भी कट गया। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दो घायलों का इलाज जारी है। घटना की शिकायत थाना सेक्टर-58 पुलिस को दी गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हमले के कारणों और आरोपितों की भूमिका की जांच की जा रही है।

कैथल में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, महिला से छेड़छाड़

भारतेन्दु संवाददाता, कैथल। हरियाणा के कैथल जिले के सीवन थाना क्षेत्र के एक गांव में कृषि भूमि के विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। एक महिला ने गांव के ही कुछ लोगों पर घर में घुसकर उसके और परिजनों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार, विवाद के दौरान आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए। उसने आरोप लगाया कि आरोपितों ने गलत नीयत से उसे छुआ और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। घटना के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। महिला ने संबंधित लोगों के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच हुए झगड़े और महिला की ओर से लगाए गए आरोपों की पड़ताल की जा रही है।

फतेहाबाद के दैय्यड़ गांव में भाजपा नेताओं की एंट्री पर रोक, प्रवेश द्वारों पर लगाए बैनर

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भट्टू खंड के दैय्यड़ गांव में ग्रामीणों और धरना कमेटी ने भाजपा नेताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। गांव के प्रवेश द्वारों पर इस संबंध में बैनर लगाए गए हैं। ग्रामीण मुआवजा नहीं मिलने और नहरीबंदी के विरोध में नाराजगी जता रहे हैं। जानकारी के अनुसार, गांव में नहरीबंदी के विरोध में किसानों का धरना चल रहा है। इसी के चलते ग्रामीणों और धरना कमेटी ने भाजपा नेताओं को गांव में प्रवेश नहीं देने का फैसला लिया है। गांव के मुख्य प्रवेश द्वारों पर बैनर लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया गया है। इन बैनरों के माध्यम से भाजपा नेताओं को गांव में नहीं आने की चेतावनी दी गई है। ग्रामीणों की नाराजगी का प्रमुख कारण मुआवजा नहीं मिलना और नहरीबंदी बताया जा रहा है। किसानों का धरना जारी है और इस फैसले के जरिए उन्होंने अपनी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। फिलहाल गांव में भाजपा नेताओं के प्रवेश पर रोक का मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

जींद नागरिक अस्पताल में पेन किलर मांगने पर कपल से मारपीट, स्टाफ पर गंभीर आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, जींद। हरियाणा के जींद स्थित नागरिक अस्पताल की इमरजेंसी में इलाज कराने पहुंचे एक कपल के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि दर्द से परेशान युवक ने डॉक्टर से पेन किलर मांगी तो डॉक्टर और स्टाफ ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। कपल ने जब इसका विरोध किया तो अस्पताल के स्टाफ ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार, अस्पताल में हुई घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें स्टाफ के कुछ सदस्य युवक को धक्का देते और थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि युवक का गला पकड़कर उसे घसीटा भी गया। कपल का कहना है कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया और करीब दो घंटे तक उनका इलाज नहीं किया गया। घटना के बाद अस्पताल की इमरजेंसी में मरीजों के साथ व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी सामने आना बाकी है।

शाह के हरियाणा दौरे पर कांग्रेस का तंज बुवानीवाला बोले- रैली से व्यापारियों को नुकसान

भारतेन्दु संवाददाता, भिवानी। कांग्रेस के वरिष्ठ व्यापारी नेता अशोक बुवानीवाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 5 नवंबर को करनाल और अंबाला दौरे को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह कांग्रेस की 1 नवंबर को हुई रैली को व्यापारियों के लिए नुकसानदायक बता रहे थे, जबकि उनके अपने दौरे और कार्यक्रमों से भी कारोबार प्रभावित हुआ है। बुवानीवाला के अनुसार, दिवाली जैसे बड़े त्योहार के दौरान बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही कम रही और व्यापारी बिक्री को लेकर परेशान रहे। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कांग्रेस की रैली से व्यापारियों को नुकसान होने की बात कही जा रही थी तो भाजपा के कार्यक्रमों के असर पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि व्यापारियों के हितों की बात करने वाली सरकार को उनके वास्तविक नुकसान की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय बाजारों में ग्राहकों की कमी से कारोबारियों को परेशानी उठानी पड़ी।

गुरुग्राम के निजी अस्पताल में युवक की मौत परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाए लापरवाही के आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-102 के धनकोट स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है। उसकी मौत की सूचना मिलते ही परिजनों और रिश्तेदारों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। उन्होंने डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिजनों के अनुसार, मुकेश को सामान्य बुखार होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका कहना है कि वह सुबह तक ठीक था और बातचीत भी कर रहा था। इसके बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मुकेश की जान गई। घटना के बाद अस्पताल के बाहर काफी संख्या में लोग जमा हो गए और प्रबंधन के खिलाफ रोष जताया। फिलहाल परिजनों के आरोप सामने आए हैं।

हरियाणा के 52 लाख लोगों को दिवाली से पहले 1650 करोड़ की सौगात

त्योहार को देखते हुए 10 नवंबर के बजाय छह नवंबर को जारी होगी विभिन्न योजनाओं की सहायता राशि

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



हरियाणा में दीवाली से पहले करीब 52 लाख गरीबों, महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों के लिए सरकार ने बड़ी राहत देने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में करीब 1650 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी करेंगे। इस राशि से प्रदेश के लाखों परिवारों को त्योहार से पहले आर्थिक मदद मिलेगी। इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, लाडो लक्ष्मी योजना और गैस सिलेंडर सब्सिडी सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं।

सरकार सामान्य तौर पर हर महीने की दस तारीख को इन योजनाओं की राशि लाभार्थियों के खातों में भेजती है। हालांकि, इस बार दीवाली के त्योहार को देखते हुए चार दिन पहले ही भुगतान करने का फैसला लिया गया है। इससे लाभार्थियों को त्योहार की तैयारियों के लिए समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

सरकार का उद्देश्य है कि त्योहार के दौरान जरूरतमंद परिवारों को पैसों की कमी का सामना न करना पड़े। विभिन्न योजनाओं के तहत जारी होने वाली कुल राशि में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बड़ा हिस्सा शामिल है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता सहित 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 35 लाख 13 हजार लाभार्थियों के बैंक खातों में करीब 1131 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे।

इन योजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों, दिव्यांगों और अन्य पात्र वर्गों को नियमित आर्थिक सहायता दी जाती है। पेंशन की यह राशि उनके दैनिक खर्चों और जरूरी जरूरतों को पूरा करने में मददगार होती है। इसके अलावा लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को भी सहायता राशि जारी की जाएगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वहीं, गैस सिलेंडर सब्सिडी के लाभार्थियों के खातों में भी राशि भेजी जाएगी। सरकार की ओर से जारी होने वाली कुल 1650 करोड़ रुपये की सहायता में इन योजनाओं का भी योगदान रहेगा। इससे महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों को घरेलू खर्चों में राहत मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से राशि जारी किए जाने के बाद लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भुगतान किया जाएगा। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद वर्गों तक सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रही है। त्योहार से पहले भुगतान की तारीख आगे करने का निर्णय इसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। करीब 52 लाख लाभार्थियों तक पहुंचने वाली इस आर्थिक सहायता से प्रदेश में बड़ी संख्या में परिवारों को फायदा मिलेगा। दीवाली से पहले पेंशन और अन्य योजनाओं की राशि मिलने से लाभार्थी त्योहार की आवश्यक खरीदारी और घरेलू जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।

हालांकि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 35.13 लाख लोगों के लिए 1131 करोड़ रुपये का विवरण सामने आया है, जबकि शेष राशि और अन्य योजनाओं के अलग-अलग लाभार्थियों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध जानकारी में नहीं दिया गया है। लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खातों की जानकारी और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपडेट रखें, ताकि भुगतान में किसी तरह की परेशानी न हो। राशि सीधे खातों में पहुंचने से पारदर्शिता बनी रहेगी और पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा।

50 लाख के डीजल घोटाले को फरीदाबाद सीएमओ ने बताया झूठा

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद। बीके अस्पताल में सामने आए 50 लाख रुपये के कथित डीजल घोटाले को लेकर सीएमओ डॉ. जयंत आहूजा ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपये के गबन की बात पूरी तरह गलत है। मामले की जांच रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले ही विपक्षी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। सीएमओ के अनुसार, मीडिया में घोटाले को लेकर काल्पनिक आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता में मामला इतनी बड़ी रकम का नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर इस मामले को राजनीतिक रंग देने और स्वास्थ्य विभाग के साथ भाजपा सरकार की छवि खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। डॉ. आहूजा ने कहा कि जांच पूरी होने और तथ्यों की जानकारी सामने आने से पहले 50 लाख रुपये के गबन का दावा करना उचित नहीं है। उन्होंने विपक्षी दलों की बयानबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले को बेवजह राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है।

आशा वर्कर के पद पर रहकर चुनाव लड़ी सरपंच को मंडल आयुक्त से भी नहीं मिली राहत

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर



यमुनानगर के गांव दौलतपुर की सरपंच पिंकी रानी को आशा वर्कर के पद पर रहते हुए सरपंच का चुनाव लड़ने और दोनों पदों से मानदेय लेने के मामले में मंडल आयुक्त न्यायालय से भी राहत नहीं मिली है। अंबाला मंडल आयुक्त ने उनकी अपील खारिज कर दी है। इससे पहले उपायुक्त कार्यालय ने 21 जनवरी 2026 को उन्हें सरपंच पद से हटाने के आदेश जारी किए थे। अब मंडल आयुक्त के फैसले से प्रशासन की इस कार्रवाई को चुनौती देने की उनकी कोशिश को झटका लगा है।

मामले की शुरुआत गांव दौलतपुर निवासी ममतेश पत्नी विनोद कुमार की शिकायत से हुई थी। उन्होंने 27 अक्टूबर 2025 को प्रशासन को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि पिंकी रानी सरपंच होने के साथ आशा वर्कर के पद पर भी कार्यरत हैं और दोनों पदों से मानदेय प्राप्त कर रही हैं। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच करवाई।

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त कार्यालय ने 23 दिसंबर 2025 को पिंकी रानी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। प्रशासन के अनुसार, पिंकी रानी की ओर से दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद 21 जनवरी 2026 को उन्हें सरपंच पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए गए। इस फैसले को चुनौती देते हुए पिंकी रानी ने अंबाला मंडल आयुक्त के समक्ष अपील दायर की थी। उन्होंने प्रशासनिक आदेशों के खिलाफ राहत की मांग की थी।

अपील पर सुनवाई के दौरान मंडल आयुक्त ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। इसके बाद अपील को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया। डीसीपीओ नरेंद्र सिंह के अनुसार, आदेश में उल्लेख किया गया है कि पिंकी रानी ने सरपंच का चुनाव लड़ने से पहले 12 अक्टूबर 2022 को आशा वर्कर के पद से त्यागपत्र देने की बात कही थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। ऐसे में दोनों पदों से मानदेय लेने का मामला सामने आया। मंडल आयुक्त के फैसले के बाद पिंकी रानी को सरपंच पद से हटाने के प्रशासनिक आदेशों पर कोई राहत नहीं मिली है।

शराब घोटाला उजागर करने वाले इंस्पेक्टर दिनेश मेहरा बने एईटीओ

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार। आबकारी एवं कराधान विभाग में करोड़ों रुपये के कथित शराब घोटाले और नियमों को ताक पर रखकर डिफॉल्टर फर्म को ठेके देने का मामला उजागर करने वाले टैक्स इंस्पेक्टर दिनेश मेहरा को पदोन्नति मिल गई है। झज्जर में कार्यरत दिनेश मेहरा को सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी (एईटीओ) बनाया गया है। हरियाणा सरकार की आबकारी एवं कराधान आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़ की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, उन्हें 25 मई 2026 से नॉशनल बेसिस पर एईटीओ पद पर पदोन्नत किया गया है। साथ ही उन्हें तुरंत प्रभाव से नया पदभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। टैक्स इंस्पेक्टर दिनेश मेहरा ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को शिकायत भेजकर आबकारी एवं कराधान विभाग के तत्कालीन अधिकारियों और शराब ठेकेदारों के बीच कथित सांठगांठ का मामला उठाया था। उन्होंने करीब 85 करोड़ रुपये के शराब घोटाले और डिफॉल्टर फर्मों को ठेके देने में नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए थे।

अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश दो सगे भाई पंजाब से गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, सिरसा। सिरसा पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो सगे भाइयों को पंजाब के बठिंडा से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर सहित कई क्षेत्रों में कारों के शीशे तोड़कर चोरी की करीब एक दर्जन वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। उनकी पहचान तमिलनाडु के गुंटूर शहर निवासी कबीर और सुमित कुमार के रूप में हुई है।



अंतरराज्यीय चोर गिरोह के दो भाई गिरफ्तार।

डीएसपी सुखबीर सिंह ने बताया कि सिरसा निवासी विकास कुमार की कार से सात लाख 75 हजार रुपये, मोबाइल फोन और जरूरी कागजात चोरी हुए थे। विकास कपास मंडी में अपने दोस्त की दुकान पर आए थे। दोपहर को लौटने पर उन्हें कार का शीशा टूटा मिला और सामान गायब था।

◆ बठिंडा से गिरफ्तार दोनों भाई कई राज्यों में कर चुके हैं चोरी की वारदातें

शिकायत के आधार पर थाना शहर सिरसा में मामला दर्ज कर एबीटी स्टाफ और शहर थाना पुलिस की विशेष टीमें गठित की गईं। सूचना के आधार पर पुलिस ने बठिंडा में दबिश देकर दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अलग-अलग राज्यों में कारों के शीशे तोड़कर चोरी करना स्वीकार किया है।

रिटायर्ड आईएएस अरुण कुमार गुप्ता बने हरियाणा बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण नियुक्ति करते हुए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता को हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (एचईआरसी) का चेयरमैन नियुक्त किया है। सरकार की ओर से 6 नवंबर को यह नियुक्ति की गई। अरुण कुमार गुप्ता इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव रखने वाले गुप्ता की इस नियुक्ति को राज्य के बिजली क्षेत्र के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



अरुण कुमार गुप्ता हरियाणा कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने सरकार के प्रशासनिक कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुख्यमंत्री के साथ काम करने के कारण उन्हें राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी कामकाज का अनुभव है। अरुण कुमार गुप्ता उस प्रतिनिधिमंडल का भी हिस्सा रह चुके हैं, जो सिंगापुर दौरे पर गया था। इस दौरे का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में विकास और निवेश से जुड़े अनुभवों को समझना था। उनके प्रशासनिक अनुभव और सरकार के साथ पूर्व में निभाई गई जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्हें एचईआरसी चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन राज्य में बिजली क्षेत्र से जुड़े नियामकीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आयोग बिजली दरों के निर्धारण, बिजली कंपनियों से जुड़े नियामकीय विषयों और उपभोक्ताओं के हितों से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने का काम करता है। ऐसे में चेयरमैन का पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अरुण कुमार गुप्ता की नियुक्ति के बाद अब उनके सामने आयोग के कामकाज को आगे बढ़ाने और बिजली क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर नियामकीय जिम्मेदारियां निभाने की चुनौती होगी। हालांकि, उनके कार्यकाल की अवधि और पदभार संभालने की तारीख को लेकर उपलब्ध जानकारी में विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।

करनाल में पुलिस ने चार आरोपितों को बाजार में घुमाकर हाथ जोड़कर माफी मंगवाई

पूर्व पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाला साहिल गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, करनाल

हरियाणा के करनाल में पूर्व पत्नी पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपित साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि साहिल ने दो दिन पहले अपनी पूर्व पत्नी के गले में सुआं घोंपकर उस पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। वहीं, एक अन्य लड़ाई-झगड़े के मामले में भी पुलिस ने तीन आरोपितों को काबू किया है।

पुलिस ने चारों आरोपितों को गंजा कर बाजार में घुमाया। इसके बाद उन्हें संबंधित वारदात स्थलों पर ले जाया गया, जहां पुलिस ने उनसे निशानदेही कराई। इस दौरान आरोपितों को बाजार में हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए भी देखा गया। पुलिस की इस कार्रवाई की चर्चा क्षेत्र में हो रही है। पुलिस के अनुसार, साहिल ने तलाक होने के बावजूद अपनी पूर्व पत्नी पर हमला किया। बताया गया है कि वह अपनी पूर्व पत्नी के किसी अन्य युवक के साथ घूमने से नाराज था। इसी बात को लेकर उसने कथित तौर पर वारदात को अंजाम दिया। महिला के गले में सुआं घोंपने की घटना के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच शुरू की गई। दो दिन पहले हुई इस वारदात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपित की तलाश शुरू की थी।



जांच के बाद साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, पुलिस ने एक अन्य लड़ाई-झगड़े के मामले में शामिल तीन आरोपितों को भी पकड़ लिया। इस तरह दोनों मामलों में कुल चार आरोपित पुलिस की गिरफ्त में आए। पुलिस ने चारों आरोपितों को संबंधित घटनास्थलों पर ले जाकर वारदातों से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई और निशानदेही कराई। हालांकि, पूर्व पत्नी पर हमले के मामले में महिला की मौजूदा स्थिति और पुलिस की आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर खबर तैयार की गई है। चारों आरोपितों को गंजा कर बाजार में घुमाने की कार्रवाई का उल्लेख मूल खबर के अनुसार किया गया है।

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। मामले में पुलिस की ओर से आगे की जांच जारी है। आरोपितों से पूछताछ के आधार पर वारदातों से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामलों में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।

संत रामपाल आश्रम पर फायरिंग मामले में दो आरोपितों का तीन दिन का रिमांड पूरा

भारतेन्दु संवाददाता, कुरुक्षेत्र

हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिपली स्थित संत रामपाल आश्रम पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा-1 ने कार्रवाई करते हुए जिला करनाल और पंचकूला के रहने वाले दोनों आरोपितों को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की। तीन दिन का रिमांड पूरा होने के बाद वीरवार को अदालत के आदेश पर दोनों को कारागार भेज दिया गया। वहीं, मामले में मुख्य हमलावर की तलाश अभी जारी है।



पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों की पहचान जिला करनाल के गांव अरजेहड़ी निवासी अनिल कुमार और जिला पंचकूला के मौली निवासी रेशव उर्फ सुदामा के रूप में हुई है। दोनों को अदालत के आदेश पर प्रोडक्शन वारंट के जरिए लाया गया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें तीन दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की। रिमांड के दौरान पुलिस ने फायरिंग की घटना से जुड़े पहलुओं की जानकारी जुटाने का प्रयास किया।

पूछताछ पूरी होने के बाद वीरवार को दोनों आरोपितों को अदालत में पेश किया गया। अदालत के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में कारागार भेज दिया गया। पिपली स्थित संत रामपाल आश्रम पर हुई फायरिंग की घटना के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अपराध अन्वेषण शाखा-1 की टीम इस मामले से जुड़े आरोपितों की भूमिका की जांच कर रही है। अब तक की कार्रवाई में दो और आरोपितों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि, फायरिंग करने वाले मुख्य हमलावर की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है।

पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। मामले में अन्य आरोपितों की भूमिका और घटना के पीछे के कारणों को लेकर भी जांच की जा रही है। पुलिस की ओर से मुख्य हमलावर की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं। फिलहाल, तीन दिन के रिमांड के बाद अनिल कुमार और रेशव उर्फ सुदामा को जेल भेज दिया गया है। पुलिस की आगामी जांच और मुख्य हमलावर की गिरफ्तारी के बाद ही फायरिंग की घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।

गौरव चंडीगढ़ के सेक्टर-19सी निवासी ईश की सफलता से सेना में जाने वाले युवाओं को मिली प्रेरणा

हरियाणा के बेटे ईश ने एनडीए में चौथी रैंक पाकर बढ़ाया मान

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में उड़ान और उन्हें पूरा करने का जुनून होता है। चंडीगढ़ के ईश फोगाट ने अपनी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति से इस कहावत को सच कर दिखाया है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए)-1, 2026 परीक्षा में ईश ने ऑल इंडिया रैंक (एआईआर)-4 हासिल कर अपने परिवार और शहर का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से सेना में अधिकारी बनने का सपना देखने वाले हजारों युवाओं को भी प्रेरणा मिली है।

सेक्टर-19सी निवासी ईश की यह सफलता अचानक नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे वर्षों की मेहनत और लगातार बेहतर प्रदर्शन की कहानी है। उन्होंने एनडीए की लिखित परीक्षा के साथ सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) का कठिन इंटरव्यू भी सफलतापूर्वक



पास किया। देश के शीर्ष पांच सफल अभ्यर्थियों में जगह बनाना उनकी प्रतिभा, तैयारी और आत्मविश्वास को दर्शाता है।

इस उपलब्धि के साथ उन्होंने साबित किया है कि लक्ष्य के प्रति समर्पण और नियमित प्रयास से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। ईश की प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2021 में उन्होंने देहरादून स्थित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (आरआईएमसी) की प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक-2 हासिल की थी। इसके बाद उनका चयन आरआईएमसी में हुआ।

यहां उन्हें पढ़ाई के साथ सैन्य जीवन के अनुरूप अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और शारीरिक दक्षता विकसित करने का अवसर मिला। संस्थान में प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने कठिन परिस्थितियों में खुद को बेहतर साबित करने की दिशा में लगातार प्रयास किए। अब एनडीए परीक्षा में चौथा स्थान हासिल कर उन्होंने अपनी सफलता की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ दी है। ईश की शुरुआती पढ़ाई चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित सेंट जॉन्स हाई स्कूल से हुई। इसी विद्यालय में उनकी शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास की नींव मजबूत हुई।

पढ़ाई के साथ बेहतर व्यक्तित्व विकसित करने और समाज व देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने की भावना ने उनके लक्ष्य को दिशा दी। स्कूल के दिनों से ही उन्होंने अपने भविष्य को लेकर गंभीरता दिखाई। इसके बाद आरआईएमसी में प्रवेश मिलने से उन्हें अपने सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला। वहां का अनुशासित वातावरण और सैन्य प्रशिक्षण उनके व्यक्तित्व को निखारने में सहायक रहा। ईश की सफलता के पीछे उनके माता-पिता प्रो. विजय फोगाट और प्रो. रेखा रानी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके पिता सेक्टर-20 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में प्रोफेसर हैं, जबकि उनकी माता भी प्रोफेसर हैं। परिवार में शिक्षा और अनुशासन का माहौल रहा, जिसने ईश को अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। माता-पिता ने उन्हें मेहनत, जिम्मेदारी और निरंतर सीखने का महत्व समझाया।

दोनों भाइयों का सैन्य क्षेत्र में करियर बनाने का सपना

ईश के परिवार में उनका छोटा भाई राम फोगाट भी सैन्य क्षेत्र में करियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वह भी देहरादून स्थित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (आरआईएमसी) में कैडेट है। दोनों भाइयों की इस उपलब्धि और लक्ष्य के प्रति समर्पण से परिवार में खुशी का माहौल है। ईश की सफलता यह संदेश देती है कि सही मार्गदर्शन, अनुशासन और निरंतर मेहनत के बल पर युवा अपने सपनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।

धार्मिक आस्था और कारोबार के अधिकार में संतुलन जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने धार्मिक आस्था और कारोबार के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखने पर दिया जोर

भारतेन्दु संवाददाता, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के आसपास मांसाहारी भोजन की बिक्री, तैयारी और भंडारण पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि धार्मिक आस्था और कारोबार करने के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। हालांकि, न्यायालय ने इस विवाद पर अंतिम फैसला देने से परहेज किया और गुजरात हाई कोर्ट को मामले का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया।



सोमनाथ मंदिर के 500 मीटर दायरे में नॉनवेज पर रोक बरकरार : सुप्रीम कोर्ट।

अदालत ने हाई कोर्ट से दो महीने के भीतर संबंधित अपील पर निर्णय लेने को कहा है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने रेस्टोरेंट संचालकों की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने गुजरात हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत सोमनाथ मंदिर के आसपास मांसाहारी भोजन पर लगाया गया प्रतिबंध फिर से लागू हो गया था।

रेस्टोरेंट संचालकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने अदालत में दलील दी कि देश की बड़ी आबादी मांसाहारी भोजन का सेवन करती है। ऐसे में इस तरह का प्रतिबंध लोगों की भोजन संबंधी पसंद को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि भोजन की पसंद व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है और प्रतिबंध के कारण रेस्टोरेंट संचालकों के कारोबार के साथ-साथ वहां काम करने वाले लोगों के रोजगार पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में धार्मिक आस्था और कारोबार के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। पीठ ने स्पष्ट किया कि फिलहाल वह विवाद के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं करना चाहती। अदालत ने अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए मामले को अंतिम निर्णय के लिए गुजरात हाई कोर्ट पर छोड़ दिया। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट से अपील की सुनवाई जल्द पूरी करने और दो महीने के भीतर फैसला सुनाने को कहा है। इससे प्रतिबंध को लेकर जारी कानूनी विवाद के जल्द सुलझने की उम्मीद है।

◆ रेस्टोरेंट संचालकों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

सोमनाथ मंदिर के 500 मीटर दायरे में नॉनवेज पर रोक बरकरार

गिर सोमनाथ जिला प्रशासन ने 10 अगस्त को अधिसूचना जारी कर सोमनाथ मंदिर के आसपास 500 मीटर के दायरे और निर्धारित तीर्थ मार्गों पर मांसाहारी भोजन की तैयारी, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया था। रेस्टोरेंट संचालकों ने इस फैसले को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 30 अक्टूबर को प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार की अपील पर खंडपीठ ने उसी दिन इस आदेश पर रोक लगा दी थी। फिलहाल प्रतिबंध जारी रहेगा। गुजरात हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित है।

अंतर-महाविद्यालय महिला हॉकी में भारती, श्यामा प्रसाद और इंदिरा गांधी संस्थान सुपर लीग में पहुंचे

भारतेन्दु संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय की अंतर-महाविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता में भारती कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज ने सुपर लीग में जगह बना ली है। श्याम लाल कॉलेज में खेली जा रही प्रतियोगिता के दौरान चारों संस्थानों ने अलग-अलग मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अगले चरण में प्रवेश किया। भारती कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ने अपने मुकाबले बड़े अंतर से जीते, जबकि जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज को कड़े संघर्ष के बाद टाईब्रेकर में सफलता मिली।

प्रतियोगिता के एक मुकाबले में भारती कॉलेज ने विवेकानंद कॉलेज को 4-1 से पराजित किया। भारती कॉलेज की ओर से चेतना और खुशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो-दो गोल किए। दोनों खिलाड़ियों के गोल की बदौलत टीम ने मुकाबले में मजबूत बढ़त बनाई। वहीं, विवेकानंद कॉलेज की ओर से शुभम ने एकमात्र गोल किया। इसके बावजूद टीम मुकाबले में वापसी नहीं कर सकी और भारती कॉलेज ने जीत अपने नाम कर ली। एक अन्य मुकाबले में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ने रामलाल आनंद कॉलेज को 4-0 से हराकर एकतरफा जीत दर्ज की। विजेता टीम की ओर से तन्नू ने दो गोल किए, जबकि पायल और चारनी ने एक-एक गोल कर टीम की जीत में योगदान दिया।



रामलाल आनंद कॉलेज की टीम पूरे मुकाबले में कोई गोल नहीं कर सकी।

दिन का तीसरा मुकाबला जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज और जीसस एंड मेरी कॉलेज के बीच खेला गया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 3-3 गोल की बराबरी पर रहीं। जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज की ओर से अंजलि ने दो और रितिका ने एक गोल किया। वहीं, जीसस एंड मेरी कॉलेज की मेरी जोशना ने तीनों गोल दागकर अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा। इसके बाद टाईब्रेकर में जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज ने 3-0 से जीत दर्ज की। दिन के चौथे मुकाबले में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज को वॉकओवर मिला। इस तरह भारती कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज और इंदिरा गांधी संस्थान ने सुपर लीग में अपनी जगह पक्की कर ली।

पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने घायल कर्मियों के लिए सहायता राशि को दी मंजूरी

भारतेन्दु संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान घायल हुए 250 से अधिक पुलिसकर्मियों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसके तहत जवानों को चोट की गंभीरता के आधार पर 15 हजार से 25 हजार रुपये तक की राशि दी जाएगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने इस संबंध में वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है।



◆ गंभीर घायल जवानों को 25 हजार, अन्य कर्मियों को मिलेंगे 15 हजार रुपए

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए पुलिसकर्मियों को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे, जबकि अन्य रूप से चोटिल हुए कर्मियों को 15 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाते समय घायल हुए पुलिसकर्मियों को राहत पहुंचाना और उनके योगदान का सम्मान करना है। अपर पुलिस आयुक्त (जनसंपर्क) राजीव रंजन ने बताया कि यह राशि दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी फंड से प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान पुलिसकर्मी कई बार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हैं और इस दौरान घायल भी हो जाते हैं।

ऐसे जवानों को आर्थिक सहायता देना उनके समर्पण और बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने का प्रयास है। राजीव रंजन के अनुसार, पुलिसकर्मियों का कल्याण और उनकी देखभाल दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विभाग का मानना है कि ड्यूटी के दौरान घायल होने वाले जवानों को सहयोग देना जरूरी है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी के इलाज और देखभाल के लिए सात दिन की कस्टडी पैरोल दी

भारतेन्दु संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को सात दिन की कस्टडी पैरोल देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह राहत उनकी बीमार पत्नी की देखभाल और इलाज कराने के लिए दी है। सिद्दीकी को निर्धारित अवधि के लिए कस्टडी पैरोल पर रहने की अनुमति मिली है। जानकारी के अनुसार, जवाद अहमद सिद्दीकी अल फलाह यूनिवर्सिटी ग्रुप के चेयरमैन हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दो मामले चल रहे हैं। इन मामलों के चलते वह कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए अदालत से राहत की मांग की थी। सिद्दीकी की ओर से अदालत में पत्नी की बीमारी और उनकी देखभाल की आवश्यकता को आधार बनाया गया। याचिका में बताया गया कि पत्नी की स्थिति को देखते हुए उनका इलाज कराना और उनकी देखभाल करना जरूरी है। इस पर विचार करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें सात दिन की कस्टडी पैरोल देने की अनुमति प्रदान की। अदालत के इस फैसले से सिद्दीकी को सीमित अवधि के लिए राहत मिली है। कस्टडी पैरोल के दौरान वह अपनी बीमार पत्नी की देखभाल और इलाज से संबंधित जरूरी व्यवस्थाएं कर सकेंगे।

◆ फैक्ट्री की पहली मंजिल पर चल रहा था जुआ 30 लाख रुपए बरामद

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पीएलए का इनामी अपराधी दबोचा

आरोपी के खिलाफ मणिपुर के थौबल थाने में यूएपीए के तहत मामला दर्ज था

भारतेन्दु संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) से जुड़े एक लाख रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मणिपुर पुलिस को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के एक मामले में वांछित था। उसके खिलाफ मणिपुर के थौबल थाने में मामला दर्ज है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी पीएलए जैसे प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा हुआ है। मणिपुर में उसके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज होने के बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। आरोपी की तलाश मणिपुर पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। इसी बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को उसके संबंध में अहम जानकारी मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई की योजना तैयार की गई।



दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पीएलए के एक लाख के इनामी आरोपी को पकड़ा।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पकड़ने के लिए पूरी योजना बनाई। टीम ने उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और उचित अवसर मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले और उसकी भूमिका को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आरोपी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था और वह मणिपुर में दर्ज गंभीर मामले में वांछित था। प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होने के कारण उसकी गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी अहम है। मणिपुर के थौबल थाने में यूएपीए के तहत दर्ज मामले के चलते आरोपी की तलाश की जा रही थी। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में जांच एजेंसियां प्रतिबंधित संगठनों की गतिविधियों और उनसे जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल करती हैं। ऐसे में दिल्ली में आरोपी की गिरफ्तारी से मणिपुर पुलिस को मामले की जांच आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में आरोपी की पहचान, गिरफ्तारी के सटीक स्थान, पीएलए में उसकी कथित भूमिका और मामले से जुड़े अन्य विवरण सामने नहीं आए हैं। पुलिस की ओर से इन पहलुओं पर विस्तृत जानकारी मिलने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मणिपुर पुलिस के एक लाख रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क और संगठन से जुड़े अन्य संपर्कों की जानकारी जुटाई जा सकती है। साथ ही मणिपुर पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी से संबंधित आवश्यक सूचनाएं देकर आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई में सहयोग किया जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हुई हवा, कई इलाकों में एक्यूआई 700 के पार पहुंचा

भारतेन्दु संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे नोएडा-ग्रेटर नोएडा में धनतेरस के दिन वायु प्रदूषण ने गंभीर रूप धारण कर लिया। शुक्रवार सुबह से ही कई इलाकों में धुंध और स्मॉग की घनी चादर छाई रही। इसके चलते दृश्यता काफी कम हो गई और लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। कई क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 700 के पार पहुंच गया, जबकि ग्रेटर नोएडा में यह 773 तक दर्ज किया गया।



दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। सुबह के समय वातावरण में छाई धुंध के कारण लोगों को आसपास की चीजें देखने में भी परेशानी हुई। प्रदूषण का असर लोगों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है। गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत जैसी शिकायतें बढ़ रही हैं। खासकर पहले से सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

इस दौरान बाहर निकलते समय सतर्क रहने और प्रदूषित हवा के सीधे संपर्क से बचने की जरूरत है। दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण की गंभीर स्थिति ने एक बार फिर वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ग्रेटर नोएडा में एक्यूआई का 773 तक पहुंचना हालात की गंभीरता को दर्शाता है। धनतेरस जैसे त्योहार के दिन भी लोगों को जहरीली हवा और स्मॉग के बीच रहना पड़ रहा है।

दीपावली पर जलने के मामलों से निपटने को दिल्ली के अस्पताल तैयार

भारतेन्दु संवाददाता, नई दिल्ली। दीपावली पर पटाखों और दीयों से जलने-झुलसने की घटनाओं की आशंका को देखते हुए दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों ने आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था मजबूत कर दी है। सफदरजंग अस्पताल, एम्स, लोकनायक अस्पताल, जीटीबी और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ऐसे मरीजों को तत्काल उपचार देने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। अस्पतालों के आपातकालीन विभागों में अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ दवाओं और ड्रेसिंग सामग्री का पर्याप्त भंडार रखा जा रहा है। गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सात और आठ नवंबर को सुबह छह से सात बजे और रात आठ से दस बजे तक प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। अस्पतालों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने की छूट नहीं होगी।

चांदनी चौक में अतिक्रमण पर हाई कोर्ट सख्त

अवैध वेंडिंग और कब्जों से बाजार की स्थिति अव्यवस्थित और खतरनाक हुई

भारतेन्दु संवाददाता, दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने चांदनी चौक और आसपास के प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने क्षेत्र की तस्वीरों को देखने के बाद कहा कि अवैध वेंडिंग और अतिक्रमण के कारण वहां की स्थिति अव्यवस्थित और खतरनाक हो गई है। कोर्ट ने इस मामले में विशेष कार्यबल (एसटीएफ) की भूमिका और उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए।

चांदनी चौक दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक और भीड़भाड़ वाले इलाकों में शामिल है। यहां बड़ी संख्या में लोग खरीदारी और अन्य कामों के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जे तथा रेहड़ी-पटरी लगने से आवागमन प्रभावित होने की स्थिति बनती है। अतिक्रमण के कारण रास्ते संकरे होने और भीड़ बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अदालत ने इसी स्थिति को गंभीर मानते हुए प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर चिंता जताई।



अतिक्रमण से चांदनी चौक में अव्यवस्था बढ़ी।

सुनवाई के दौरान अदालत के सामने चांदनी चौक की तस्वीरें रखी गईं। इन्हें देखने के बाद पीठ ने कहा कि अवैध वेंडिंग और अतिक्रमण के चलते हालात अव्यवस्थित हो गए हैं। कोर्ट ने स्थिति को खतरनाक बताते हुए संबंधित व्यवस्था पर सवाल उठाए। अदालत की नाराजगी का मुख्य कारण यह रहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद समस्या का प्रभावी समाधान नजर नहीं आ रहा है।

हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए गठित एसटीएफ की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए। अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि चांदनी चौक जैसे महत्वपूर्ण इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अपेक्षित प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखने की जिम्मेदारी से जुड़ी व्यवस्था पर कोर्ट की टिप्पणी अहम मानी जा रही है।

जलवायु परिवर्तन से चक्रवात अर्नब का आर्थिक नुकसान 33 प्रतिशत तक बढ़ा

भारतेन्दु संवाददाता, नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन ने आंध्र प्रदेश के तट से टकराए चक्रवात अर्नब की तबाही को और गंभीर बना दिया। इंपीरियल कॉलेज लंदन के एक नए अध्ययन के अनुसार, मानवजनित ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस चक्रवात से होने वाला प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान औद्योगिक युग से पहले की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक रहा। अध्ययन में सामने आया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण तूफान की हवा की रफ्तार में लगभग पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन इससे होने वाला आर्थिक नुकसान कहीं अधिक बढ़ गया।

◆ ग्लोबल वार्मिंग के कारण आंध्र प्रदेश में चक्रवात का कहर और बढ़ा

अध्ययन के मुताबिक, चक्रवात अर्नब 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था। अंतरराष्ट्रीय ट्रैकिंग डेटा के आधार पर इसकी तीव्रता सैफिर-सिम्पसन पैमाने पर श्रेणी तीन के तूफान के बराबर आंकी गई। इस दौरान एक मिनट की अवधि में औसतन अधिकतम 202 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। तेज हवाओं के साथ हुई भीषण बारिश ने तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। अध्ययन में बताया गया कि इंसानी गतिविधियों से बढ़े वैश्विक तापमान ने चक्रवात की हवाओं को लगभग पांच प्रतिशत अधिक तेज कर दिया।

हवा की रफ्तार में यह वृद्धि देखने में कम लग सकती है, लेकिन तूफान की विनाशकारी क्षमता पर इसका बड़ा असर पड़ा। इसके चलते संपत्तियों और बुनियादी ढांचे को होने वाला प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान 33 प्रतिशत तक बढ़ गया। शोधकर्ताओं के अनुसार, यदि औद्योगिक युग से पहले के तापमान की स्थिति बनी रहती, तो चक्रवात से होने वाला नुकसान तुलनात्मक रूप से कम होता।

हादसा हादसे के बाद घटनास्थल पर जुटे परिजन अपनों की सलामती की दुआ करते रहे

चावड़ी बाजार में मकान ढहने से मची चीख-पुकार

भारतेन्दु संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के चावड़ी बाजार की गली शीश महल में तीन मंजिला मकान ढहने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इमारत गिरते ही चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया और घटनास्थल पर चीख-पुकार सुनाई देने लगी। हादसे के बाद लोग अपने परिजनों की तलाश में जुट गए। कोई मलबे में दबे भाई को खोज रहा था, तो कोई अपने बेटे को लगातार फोन कर उसकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था।

अपनों के सुरक्षित मिलने की उम्मीद में परिजन घटनास्थल और अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे। हादसे की सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंच गए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और दमकल विभाग की टीमों ने राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सावधानी से तलाश की गई। घटनास्थल पर मौजूद लोग बचावकर्मियों से अपने परिजनों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते रहे। हर किसी की नजर मलबे पर टिकी थी और लोगों को अपनों के बाहर निकलने का इंतजार था। हादसे के बाद एक श्रमिक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि, मलबे में अन्य लोगों के दबे होने की आशंका के चलते तलाश अभियान जारी रखा गया। बचाव दल मलबे को हटाकर अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। घटनास्थल पर राहत कार्य के दौरान सुरक्षा और सावधानी का विशेष ध्यान रखा गया। इमारत गिरने की खबर फैलते ही आसपास के लोग भी घटनास्थल पर पहुंचने लगे।

जिनके परिजन वहां मौजूद थे, वे उनकी सलामती की खबर मिलने की आस लगाए रहे। किसी के हाथ में फोन था तो कोई बचाव दल से जानकारी लेने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। हादसे के बाद का मंजर बेहद पीड़ादायक था। मलबे से उठती आवाजों और अपनों की तलाश में भटकते परिजनों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीमें लोगों को निकालने के लिए अभियान में जुटी रहीं।

चीखों के बीच अपनों का इंतजार करते परिजन



घटनास्थल पर लोगों की भीड़ बढ़ने के साथ ही पुलिस ने भी व्यवस्था संभाली। बचाव अभियान में जुटी टीमों को मलबे के अलग-अलग हिस्सों की जांच करने और फंसे लोगों तक पहुंचने में सावधानी बरतनी पड़ रही थी। परिजन लगातार अपने लापता सदस्यों के मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। किसी को फोन की घंटी सुनाई देने की उम्मीद थी, तो कोई अस्पतालों में पहुंचकर घायलों की सूची में अपनों का नाम तलाश रहा था।

आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने नमो भारत कॉरिडोर का किया दौरा

एनसीआरटीसी ने छात्रों को बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट का व्यावहारिक अनुभव दिया

भारतेन्दु संवाददाता, नई दिल्ली

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों ने बृहस्पतिवार को दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का शैक्षणिक दौरा किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के निर्माण में इस्तेमाल की गई आधुनिक तकनीकों, इंजीनियरिंग की चुनौतियों और संचालन प्रक्रियाओं को करीब से समझा।



आईआईटी छात्रों ने नमो भारत की तकनीकें करीब से समझीं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की ओर से आयोजित इस दौरे का उद्देश्य विद्यार्थियों को बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव का व्यावहारिक अनुभव देना था। दौरे की शुरुआत सराय काले खां स्टेशन से हुई। यहां विद्यार्थियों को स्टेशन पर उपलब्ध मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन सुविधाओं की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि किस तरह यह स्टेशन मेट्रो, वीर हकीकत राय अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी), रिंग रोड और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यात्रियों को परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराना है। विद्यार्थियों ने स्टेशन पर बने फुट ओवरब्रिज और उस पर लगाई गई ट्रैवलेटर सुविधा को भी देखा। उन्हें बताया गया कि ऐसी सुविधाएं यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने और अलग-अलग परिवहन साधनों के बीच संपर्क बेहतर करने में मदद करती हैं।

इस शैक्षणिक दौरे के दौरान विद्यार्थियों को नमो भारत कॉरिडोर के निर्माण से जुड़ी तकनीकी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने समझा कि बड़े परिवहन कॉरिडोर के निर्माण में किस तरह की इंजीनियरिंग चुनौतियां सामने आती हैं और उन्हें दूर करने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए यह दौरा कक्षा में पढ़े गए तकनीकी विषयों को वास्तविक परियोजना से जोड़ने का अवसर रहा।

इस दौरान उन्हें निर्माण कार्य के साथ-साथ संचालन और रखरखाव से जुड़े पहलुओं को समझने का मौका मिला। विद्यार्थियों ने कॉरिडोर के दुहाई स्टेशन का भी दौरा किया। यहां उन्हें आरआरटीएस से जुड़ी व्यवस्थाओं और संचालन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई।

न्यूज ब्रीफ

बीबीएमबी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिमाचल के अधिकारों की ऐतिहासिक जीत : विक्रमजीत शर्मा

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से जुड़े बिजली बकाया एवं हिस्सेदारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का जिला बाल कल्याण समिति कांगड़ा के चेयरमैन विक्रमजीत शर्मा ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा कानूनी स्तर पर की गई मजबूत पैरवी का यह सकारात्मक परिणाम है। लगभग छह दशक पुराने बिजली हिस्सेदारी विवाद के समाधान से प्रदेश को उसका लंबित अधिकार मिलने का रास्ता साफ हुआ है। शर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हिमाचल को आगामी 20 वर्षों में लगभग 11,973 मिलियन यूनिट बिजली प्राप्त होगी। इससे प्रदेश को प्रतिवर्ष 500 से 1,000 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है। उन्होंने प्रदेश सरकार, अधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञों के प्रयासों की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि शानन जलविद्युत परियोजना, वाटर सेस और चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी जैसे लंबित मामलों में भी प्रदेश को न्याय मिलेगा।

महिला की संदिग्ध मौत के बाद दो शिशु बच्चियों के संरक्षण को बाल कल्याण समिति ने लिया संज्ञान

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के आधार पर जिला बाल कल्याण समिति कांगड़ा ने महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। महिला की दो बच्चियां हैं, जिनमें एक की आयु लगभग एक वर्ष और दूसरी की तीन माह बताई जा रही है। समिति के अध्यक्ष विक्रमजीत शर्मा ने बताया कि दोनों बच्चियों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, पुलिस जिला देहरा तथा थाना प्रभारी ज्वालामुखी से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी गई है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजा गया है। उन्होंने बताया कि जिला बाल संरक्षण अधिकारी और जिला बाल सहायता केंद्र को भी आवश्यक समन्वय के लिए शामिल किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चियों के संरक्षण और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। महिला की मृत्यु के कारणों की जांच पुलिस का विषय है।

विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए हिमाचल की अंडर-16 टीम घोषित, सांभव शर्मा होंगे कप्तान

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) ने बीसीसीआई की विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर-16 एलीट ग्रुप 2026-27 के लिए 18 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। एसोसिएशन के मानद सचिव मनुज शर्मा ने इसकी जानकारी दी। शिमला के सांभव शर्मा टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि मंडी के आदिश मिन्हास उप-कप्तान होंगे। टीम में शिमला से अथर्व आर्य, नीरव और सान्यम भालुनी, कांगड़ा से भावेश ठाकुर, रियांश ठाकुर और यश चौधरी तथा मंडी से अर्णव ठाकुर और येश वर्मा शामिल हैं। इसके अलावा सोलन, बिलासपुर, कुल्लू और ऊना के खिलाड़ियों को भी मौका मिला है। योगिंदर पुरी मुख्य कोच होंगे। टीम विजयवाड़ा में पांच तीन दिवसीय मुकाबले खेलेगी। पहला मैच 14 से 16 नवंबर तक असम के खिलाफ होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड और बड़ौदा से मुकाबले होंगे। टूर्नामेंट में हिमाचल के युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

नाहन में पटाखों की बिक्री शुरू, चौगान में लगे स्टॉल



भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। दीपावली को लेकर बाजार सजने आरंभ हो गए हैं और बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। दीवाली पर पटाखों की बिक्री आज धनतेरस से आरंभ हो गई। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के ऐतिहासिक चौगान में आज से पटाखों की बिक्री शुरू हो गई है। नगर परिषद द्वारा आतिशबाजी और पटाखे विक्रय के लिए ऐतिहासिक चौगान में व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि केवल निर्धारित पटाखा विक्रय स्थल से ही बिक्री की जाएगी और यदि कोई अन्यत्र पटाखे बेचता पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम नाहन राजीव संख्यान ने बताया कि पटाखों के विक्रय के लिए स्थल निर्धारित किए गए हैं और विक्रय स्टॉल केवल चौगान में रखे गए हैं जहाँ पर निर्धारित फीस के बाद स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पर 3 दिन पटाखों की बिक्री होगी। इसके अलावा अन्य स्थान पर पटाखे बेचने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कैंपस उद्योग में कामगारों की मांगें मानीं

भारतेन्दु संवाददाता, बद्दी। कैंपस उद्योग में कामगारों और प्रबंधन के बीच चल रहा विवाद आखिरकार समाप्त हो गया। हिमाचल प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स के सलाहकार देव वरत यादव के प्रयासों से दोनों पक्षों में सहमति बन गई और कामगारों ने हड़ताल समाप्त करने पर सहमति जताई। समझौते के तहत प्रत्येक 15 दिन में टी-ब्रेक, 30 मिनट का लंच ब्रेक, मासिक वेतन पर्ची, पदों के अनुसार ग्रेडेशन और नियमानुसार ओवरटाइम भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। महिला कर्मचारियों की शिकायतों के लिए समिति गठित होगी। अक्टूबर का वेतन 17 नवंबर को दिया जाएगा तथा हड़ताल में शामिल किसी कामगार पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इंटक अध्यक्ष विक्रम ठाकुर ने भी कामगारों से सहयोग की अपील की। एएसपी संजीव भाटिया और डीएसपी योगराज चंदेल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। गौरतलब है कि विवाद के दौरान हुई पत्थरबाजी में कामगारों और स्टाफ के कुछ लोग घायल हुए थे। श्रम अधिकारी सुरिंदर बिष्ट ने हड़ताल समाप्त होने की पुष्टि की।

धनतेरस पर नाहन के बाजारों में उमड़ी भीड़, सोना-चांदी और बर्तनों की जमकर खरीदारी

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। देश भर में इस समय त्योहारी सीजन चला हुआ है और बाजारों में रौनक बढ़ी हुई है। शुक्रवार को धनतेरस पर सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। लोग बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, चांदी का कछुआ, मछली इत्यादि की खरीद कर रहे हैं। शहर के सर्राफा बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी बर्तनों की भी खरीद की जा रही है और लोग अपनी पसंद अनुसार बर्तन भी खरीद रहे हैं। इसके साथ ही नगर में पारंपरिक मिट्टी के उत्पाद दीपक इत्यादि भी लोग खरीद रहे हैं।कुल मिलाकर त्योहार सीजन में आज बाजार लोगों से भरे हुए हैं और बाजारों में रौनक बढ़ गई है।नाहन के 'वेलर श्याम खिंदड़ी ने बताया कि आज सुबह से ग्राहक पहुंच रहे हैं और अपनी पसंद के उत्पाद ले रहे हैं। लोग जरूरत के अनुसार खरीद कर रहे हैं।

नालागढ़ में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित, केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति

भारतेन्दु संवाददाता, नालागढ़। दीपावली पर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नालागढ़ उपमंडल प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थान तय किए हैं। एसडीएम नरेंद्र अहलूवालिया ने बताया कि नालागढ़ के वार्ड नंबर-1 स्थित पुराने राजकीय छात्र विद्यालय मैदान में 30 तथा डीएफओ कार्यालय के समीप 5 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके अलावा रामशहर, पंजेहरा और लोहारघाट में भी बिक्री स्थल निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। अस्थायी लाइसेंस खुली नीलामी के माध्यम से आवंटित किए गए हैं तथा वैध लाइसेंस के बिना बिक्री और भंडारण की अनुमति नहीं होगी। एसडीएम ने बताया कि दीपावली पर केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग किया जा सकेगा। पटाखे चलाने का समय रात 8 से 10 बजे तक निर्धारित है। उन्होंने लोगों से नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल दीपावली मनाने की अपील की। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।

दीपावली पर सीएम सुक्खू की श्रमिकों को बड़ी सौगात, 1,444 लाभार्थियों को मिले 6.11 करोड़

विवाह, शिक्षा, चिकित्सा, आवास और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत दी आर्थिक सहायता

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दिशा-निर्देश पर दीपावली के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने प्रदेश के श्रमिक परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की है।

बोर्ड की ओर से प्रदेश के 11 जिलों के 1,444 लाभार्थियों को लगभग 6 करोड़ 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर, शिमला में आयोजित कार्यक्रम में उद्योग व श्रम मंत्री हर्षवर्धन चौहान तथा मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी एवं देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर की उपस्थिति में लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर उद्योग व श्रम मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, आवास सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। सरकार का प्रयास है कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि बोर्ड पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं प्रभावी ढंग से संचालित कर रहा है। उन्होंने पात्र श्रमिकों से इन योजनाओं की जानकारी लेकर लाभ उठाने का आग्रह किया।

मंडी में सर्वाधिक 440 लाभार्थियों को मिला लाभ

जिला स्तर पर मंडी में सर्वाधिक 440 लाभार्थियों को 1 करोड़ 61 लाख 18 हजार 200 रुपये की सहायता प्रदान की गई। शिमला में 183 लाभार्थियों को 72 लाख 97 हजार 200 रुपये, बिलासपुर में 173 को 65 लाख 53 हजार 800 रुपये तथा हमीरपुर में 148 लाभार्थियों को 64 लाख 94 हजार 610 रुपये दिए गए। इसके अतिरिक्त किन्नौर में 168 लाभार्थियों को 64 लाख 92 हजार 200 रुपये, ऊना में 142 को 1 करोड़ 5 लाख 9 हजार 700 रुपये तथा कांगड़ा में 63 लाभार्थियों को 31 लाख 200 रुपये की सहायता प्रदान की गई। चंबा में 50 लाभार्थियों को 14 लाख 12 हजार 600 रुपये, कुल्लू में 38 को 9 लाख 45 हजार 600 रुपये, सिरमौर में 29 को 15 लाख 38 हजार 200 रुपये तथा सोलन में 10 लाभार्थियों को 5 लाख 95 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। सरकार की इस पहल से हजारों श्रमिक परिवारों को शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य और आवास जैसी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों की सहायता

बोर्ड की ओर से विवाह सहायता योजना के तहत 1 करोड़ 70 लाख 87 हजार रुपए, शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 14 लाख 67 हजार 700 रुपये तथा चिकित्सा सहायता योजना के तहत 54,610 रुपये प्रदान किए गए। इसी प्रकार मृत्यु एवं अंतिम संस्कार सहायता योजना के तहत 32 लाख 80 हजार रुपये और अन्य योजनाओं के अंतर्गत 5 लाख 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। स्वीकृत राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी गई। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गृह निर्माण के लिए 67 पात्र श्रमिकों को कुल 86 लाख 58 हजार रुपये की सहायता के चेक भी वितरित किए गए। इससे जरूरतमंद श्रमिक परिवारों को अपना घर बनाने में आर्थिक मदद मिलेगी।

स्कीइंग व स्नोबोर्डिंग खिलाड़ियों को राज्य खेल पुरस्कारों से बाहर रखना दुर्भाग्यपूर्ण : गोविंद

◆ पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री से 21 खिलाड़ियों को सम्मानित करने की उठाई मांग

◆ कहा- ओलंपिक चार्टर के सभी खेलों को मिले सम्मान

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित राज्य खेल पुरस्कार समारोह में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के खिलाड़ियों को सम्मानित नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है।

उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से इन खिलाड़ियों को भी राज्य खेल पुरस्कार प्रदान करने की मांग की है। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया, लेकिन विंटर गेम्स में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक चार्टर के अंतर्गत आने वाले सभी खेलों को समान मान्यता और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में ऐसे 21 खिलाड़ियों के नाम आए हैं, जिन्हें उपलब्धियों के बावजूद राज्य खेल पुरस्कारों से सम्मानित नहीं किया गया। इनमें हिमांशु ठाकुर, वर्षा देवी, प्रोमिला ठाकुर, कमलजीत, मनीष, प्रकृति, दीपिका, योगेश, तनुजा, सुहानी, संध्या, प्रीति, प्रणव, साक्षी, नताशा, शिवानिका, तमन्ना, सेजल, तेनजिन डोलमा, दिया और दीक्षा शामिल हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने कठिन परिस्थितियों में मेहनत कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।



इसके बावजूद उन्हें पुरस्कार समारोह में आमंत्रित तक नहीं करना निराशाजनक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मामले का संज्ञान लेकर सभी पात्र खिलाड़ियों की उपलब्धियों की समीक्षा करवाई जाए और उन्हें निर्धारित पुरस्कार राशि एवं सम्मान प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को समान अवसर, प्रोत्साहन और सम्मान मिलना चाहिए।

सिरमौर में धनतेरस के दिन दर्दनाक हादसा, एक व्यक्ति की मौत, 9 घायल

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर में धनतेरस के दिन बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 9 लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों को तुरंत उपचार के लिए सिविल अस्पताल सराहां ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कालेज नाहन रेफर किया गया है।

उधर, पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। हादसा नाहन-कुमारहट्टी नेशनल हाईवे पर डुंगा घाट के समीप एक तीखे मोड़ पर पेश आया, जहां बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में लुढ़कते हुए कयाणा की ओर जा रहे लिंक रोड पर जाकर रुकी। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किया। साथ ही पुलिस और 108 एंबुलेंस को सूचना



दी। एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सिविल अस्पताल सराहां पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं गंभीर घायलों को मेडिकल कालेज नाहन रेफर किया जा रहा है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है।

जानकारी मिली है कि जिला सिरमौर के गिरिपार इलाके के लोग शिमला की ओर से दिवाली पर्व पर अपने घर आ रहे थे। इस बीच वाहन रास्ते में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। उधर, प्रशासन ने मेडिकल कालेज प्रबंधन नाहन को अलर्ट कर दिया है। पुलिस घटनास्थल पर हादसे की जांच में जुट गई है।

पुराने सदस्यों को वोटिंग और चुनाव के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती ट्रक सोसायटी : हाईकोर्ट

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिलासपुर की एक ट्रक परिवहन सहकारी सोसायटी के चार पुराने सदस्यों को मतदान करने, बैठकों में हिस्सा लेने और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार देने के सरकारी आदेश को बरकरार रखा है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि सोसायटी में पहले से सदस्य के रूप में दर्ज लोगों को बिना नोटिस और उचित कारण के नाममात्र का सदस्य घोषित कर उनके अधिकार नहीं छीने जा सकते। हाईकोर्ट ने सोसायटी की याचिका खारिज करते हुए उसे चारों सदस्यों को उनके अधिकार देने के सरकारी आदेश को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने सुनाए आदेश



◆ किरतपुर में कारोबार करने पर छीने सदस्यता के अधिकार

◆ 1983 में 62 सदस्यों के साथ बनी थी सोसायटी

में कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि चारों निजी प्रतिवादी सोसायटी के पुराने सदस्य हैं और बिलासपुर जिले के स्थायी निवासी हैं। सोसायटी ने उनके किरातपुर (पंजाब) में कारोबार करने के आधार पर उन्हें नाममात्र का सदस्य घोषित कर दिया था। इसके बाद उनके ट्रकों को भी गट्टा नंबर-1 से हटाकर गट्टा नंबर-2 में डाल दिया गया। इससे उनके मतदान, बैठकों में भागीदारी और चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के अधिकार प्रभावित हुए। अदालत ने पाया कि सोसायटी ने इस कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया और न ही इसके लिए उचित कारण साबित किए। मामले के अनुसार संबंधित सहकारी सोसायटी का पंजीकरण 14 फरवरी 1983 को 62 सदस्यों के साथ हुआ था।

इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी और निजी संस्थानों के साथ समझौता कर परिवहन वाहनों के जरिए सामान की ढुलाई करना था। सोसायटी ने एसीसी सीमेंट के बरमाणा कारखाने से हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के विभिन्न स्थानों तक सीमेंट पहुंचाने के लिए समझौता किया था। शुरुआत में सोसायटी की सदस्यता के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु, स्वस्थ मानसिक स्थिति, बिलासपुर जिले का सामान्य निवासी होना, अच्छा चरित्र और ट्रक का मालिक होना जैसी शर्तें थीं। एक फरवरी 1993 को सोसायटी ने अपने उपनियमों में बदलाव कर सदस्यता के लिए नई शर्त जोड़ी। इसके अनुसार नया सदस्य बिलासपुर जिले में पीढ़ियों से रहने वाला और वर्ष 1970 से पहले से जिले में जमीन का मालिक होना चाहिए था। वर्ष 1970 के बाद जमीन खरीदने वालों को नाममात्र का सदस्य मानने का प्रावधान किया गया। 20 मार्च 2001 को उपनियमों में एक और बदलाव किया गया, जिसके तहत एक सदस्य के पास दो से अधिक ट्रक नहीं हो सकते थे।

वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में शुरू हुई थी बीबीएमबी में हिमाचल के हक की लड़ाई : विक्रमादित्य सिंह

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने की कानूनी लड़ाई वर्ष 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुरू की थी।

करीब तीन दशक बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से प्रदेश को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस निर्णय से हिमाचल को अगले 20 वर्षों तक हर साल करीब 60 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी। इससे प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक लाभ होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के कार्यकाल में इस मामले में निर्णायक सफलता मिली है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत बीबीएमबी की परियोजनाओं में हिमाचल की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिकार बनता है। वर्ष 1996 में वीरभद्र सिंह सरकार ने इसके लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी के सहयोग से प्रदेश ने अपना पक्ष मजबूती से रखा था। वर्ष 2011 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल की हिस्सेदारी के अधिकार को स्वीकार करते हुए इसके क्रियान्वयन के निर्देश दिए थे, लेकिन बकाया ऊर्जा लाभों का निर्धारण लंबित रहा। ताजा निर्णय से इस विवाद के समाधान का रास्ता साफ हुआ है। उन्होंने कहा कि भाखड़ा-नंगल और पोंग बांध सहित ब्यास नदी पर बनी परियोजनाओं के कारण बिलासपुर समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों के लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा। अनेक परिवार राजस्थान और हरियाणा में बसाए गए, लेकिन उनके कई अधिकार अब भी लंबित हैं। सरकार इन परिवारों के हितों की पैरवी करेगी। चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी और दूसरे अंतरराज्यीय मामलों को भी मजबूती से उठाया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 800 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 50 से 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।



सड़क निर्माण के लिए बिटुमेन की आपूर्ति का मामला केंद्र के समक्ष उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर पर्याप्त आपूर्ति का आग्रह किया है। रामपुर, आनी, कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और भरमौर में सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है।

बल्ह की दीक्षा शर्मा को मिला इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। मंडी जिला के बल्ह ब्लॉक की ग्राम पंचायत राजगढ़ की दीक्षा शर्मा को इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान लाडली फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। इस सम्मान के मिलने पर दीक्षा शर्मा ने कहा कि मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष, सौभाग्य और गौरव का क्षण है कि लाडली फाउंडेशन द्वारा बिलासपुर में आयोजित भव्य समारोह में मुझे इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। गवर्नर कविंद्र गुप्ता और कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी की गरिमामयी उपस्थिति और उनके कर-कमलों द्वारा यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। इस सम्मान के लिए मैं उनके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में मुझे यह सुनहरा अवसर प्रदान करने और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मैं लाडली फाउंडेशन, गोविंद सागर वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर और रेनबो स्टार क्लब का आभार व्यक्त करती हूं। यह सम्मान मुझे सामाजिक कल्याण और सेवा के मार्ग पर और अधिक समर्पण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। दीक्षा शर्मा मूल रूप से मंडी जिला के बल्ह क्षेत्र की ग्राम पंचायत राजगढ़, की निवासी हैं।



अनियोजित पर्यटन व बेतरतीब निर्माण हिमाचल के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा : विपिन परमार

◆ पर्यटन स्थलों की वहन क्षमता का वैज्ञानिक अध्ययन करवाने की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, पालमपुर। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने हिमाचल प्रदेश में अनियोजित पर्यटन विस्तार, अवैज्ञानिक निर्माण और कमजोर पर्यावरणीय निगरानी को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल की प्राकृतिक संपदा, नदियां, जंगल और पहाड़ प्रदेश की जीवनरेखा हैं, लेकिन इनके संरक्षण को लेकर सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। परमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट में प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की वहन क्षमता का वैज्ञानिक अध्ययन न होने पर चिंता जताई गई है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में प्रदेश में पंजीकृत होटलों की संख्या 2,784 थी, जो 2026 में बढ़कर 5,311 हो गई। वहीं, होमस्टे की संख्या 876 से बढ़कर 6,743 पहुंच गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के साथ क्या जलापूर्ति, सीवरेज, कचरा प्रबंधन और यातायात व्यवस्था भी मजबूत हुई है? समिति ने सड़क निर्माण के दौरान पहाड़ों की कटाई, मलबे के अनुचित निस्तारण और भूस्खलन के खतरे पर भी चिंता जताई है। परमार ने सरकार से शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी और कसोल सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों का वैज्ञानिक कैरिंग कैपेसिटी अध्ययन करवाने तथा अनियोजित निर्माण पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास की विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसा विकास स्वीकार्य नहीं हो सकता जो हिमाचल की प्राकृतिक संपदा और भविष्य को संकट में डाल दे। सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करनी चाहिए।



बिलासपुर आयुर्वेद चिकित्सालय में सात लाख से स्थापित हुई आधुनिक जांच मशीनें

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बिलासपुर में स्वास्थ्य जांच सुविधाओं का विस्तार किया गया है। उपायुक्त किरण भड़ाना ने शुक्रवार को अस्पताल में फुली ऑटोमेटिक 5-पार्ट सीबीसी/हेमेटोलॉजी एनालाइजर तथा 4-चैनल फ्लोरोसेंस इम्युनोएस्से एनालाइजर मशीनों का उद्घाटन किया। इन मशीनों की स्थापना के लिए जिला प्रशासन ने 7 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई है।

इन आधुनिक मशीनों के शुरू होने से मरीजों को सीबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, डायबिटीज, थायराइड, विटामिन बी-12 और विटामिन-डी सहित कई महत्वपूर्ण जांचों की सुविधा अस्पताल में ही मिलेगी। इससे मरीजों को जांच के लिए अन्य अस्पतालों और निजी प्रयोगशालाओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सीबीसी मशीन से रक्त संबंधी विभिन्न विकारों, एनीमिया और संक्रमण की पहचान में सहायता मिलेगी। वहीं,



फ्लोरोसेंस इम्युनोएस्से एनालाइजर से एचबीए1सी, थायराइड, विटामिन और महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न जांचें की जा सकेंगी। इससे चिकित्सकों को समय पर रिपोर्ट मिलने के साथ उपचार संबंधी निर्णय लेने में भी सुविधा होगी। इस अवसर पर जिला आयुष कार्यालय में भगवान धन्वंतरि की मूर्ति भी स्थापित की गई। विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान जिला आयुष अधिकारी डॉ. सुखविंदर कौर, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. रोहित कपिल, चिकित्सालय प्रभारी, चिकित्सा अधिकारी, फार्मेसी अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारी और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थी उपस्थित रहे।

निखिल ठाकुर को लगातार दूसरी बार मिला 'हरफनमौला खिलाड़ी, मंडी कॉलेज बना कबड्डी चैंपियन

भारतेन्दु संवाददाता, पंडोह। मंडी जनपद के पंडोह के युवा होनहार जइंटर कॉलेज कबड्डी प्रतियोगिता में मंडी कॉलेज ने लगातार दूसरी बार शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता बनने का गौरव हासिल किया है। वहीं, पंडोह क्षेत्र के होनहार कबड्डी खिलाड़ी निखिल ठाकुर को लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट का हरफनमौला खिलाड़ी के खिताब से नवाजा गया है। इस बार बल्दवाड़ा में आयोजित इंटर कॉलेज कबड्डी प्रतियोगिता में निखिल ठाकुर ने अपने शानदार खेल, बेहतरीन रेडिंग और दमदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मंडी में आयोजित इंटर कॉलेज कबड्डी प्रतियोगिता में भी निखिल ठाकुर को हरफनमौला खिलाड़ी के खिताब से सम्मानित किया गया था। इस वर्ष भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए उन्होंने लगातार दूसरी बार यह उपलब्धि हासिल की है। जिला कबड्डी एसोसिएशन अध्यक्ष श्याम लाल ठाकुर और सचिव नेत्र सिंह ठाकुर में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी है उन्होंने बताया कि लगातार निखिल ठाकुर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है निखिल ठाकुर खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा में कोच संजीव ठाकुर की देखरेख में प्रशिक्षण लेता है आपको बता दें कि लगातार 2 सालों से मंडी कॉलेज से पंडोह क्षेत्र के पांच खिलाड़ी लगातार खेल रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और मंडी कॉलेज को गोल्ड मेडल जीता रहे हैं।



बीबीएमबी मामले में सुप्रीम क

न्यूज ब्रीफ

श्रीराम के आदर्शों से विद्यार्थियों को कराया परिचित

भारतेन्दु संवाददाता, मजारी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मजारी में दीपावली के उपलक्ष्य में अवकाश से पूर्व रामायण पाठ, अंतर-सदनीय प्रश्नोत्तरी व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कंप्यूटर शिक्षिका शैली अग्निहोत्री द्वारा महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के सस्वर पाठ से हुआ। इसके बाद रामायण पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने शिक्षकों के मार्गदर्शन में आकर्षक रंगोलियां भी बनाईं। स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष गुरमेल सिंह ने रंगोलियों का निरीक्षण कर प्रतिभागियों की सराहना की। प्रतियोगिताओं में बाबा फतेह सिंह सदन ने प्रथम तथा बाबा जोरावर सिंह सदन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य सुरजीत ठाकुर ने विद्यार्थियों को भगवान श्रीराम के आदर्शों, नैतिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति का महत्व समझाया। कार्यक्रम के समापन पर मिठाई वितरित कर दीपावली की शुभकामनाएं दी गईं तथा सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल त्योहार मनाने का संदेश दिया गया।

राइजिंग स्टार युवक मंडल जोल के 45 सदस्यों ने थामा कांग्रेस का दामन



भारतेन्दु संवाददाता, जोगिंद्रनगर। उपमंडल की बल्ह जोली पंचायत के राइजिंग स्टार युवक मंडल जोल के सभी 45 सदस्यों ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। लोक निर्माण विभाग जोगिंद्रनगर के विश्राम गृह में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जीवन ठाकुर की मौजूदगी में युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जीवन ठाकुर ने सभी युवाओं का कांग्रेस परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के जुड़ने से पार्टी संगठन को मजबूती मिलेगी। युवक मंडल के प्रधान विजय ठाकुर सहित सदस्यों ने कहा कि वे मुख्यमंत्री की कार्यशैली और जनहितैषी नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर नगर परिषद उपाध्यक्ष प्यार चंद वालिया सहित पंचायत प्रतिनिधि, ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नेक्सराइज स्किल्स कांगड़ा में विद्यार्थियों ने धूमधाम से मनाई दिवाली पार्टी



भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। नेक्सराइज स्किल्स कांगड़ा में दीपावली के उपलक्ष्य में भव्य दिवाली पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें संस्थान के विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संस्थान को आकर्षक ढंग से सजाया गया तथा विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से त्योहार की खुशियां साझा की गईं। संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिमेष शर्मा ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व सकारात्मकता, नई उम्मीदों और आपसी प्रेम का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि संस्थान तकनीकी शिक्षा के साथ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास और अच्छे संस्कारों पर भी ध्यान देता है। को-फाउंडर एवं डायरेक्टर वरुण गुलेरिया ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में टीम भावना, सहयोग और आपसी जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने सुरक्षित एवं प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर ट्रेनर अक्षिता, अनिकेत सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों और स्टाफ ने मिठाइयां बांटकर दीपावली की खुशियां मनाईं।

प्रख्यात साहित्यकार एवं शिक्षक रमेश मस्ताना के निधन पर जताया गहरा शोक

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। प्रख्यात साहित्यकार एवं शिक्षक रमेश मस्ताना की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु पर भाषा एवं संस्कृति विभाग ने गहरा शोक प्रकट किया है। विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि रमेश मस्ताना के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है। उनके निधन से साहित्य एवं शिक्षा जगत को अपूरणीय क्षति पहुंची है। रमेश मस्ताना का पहाड़ी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के प्रति विशेष लगाव और योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। एक शिक्षक एवं साहित्यकार के रूप में उन्होंने समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं परिवारजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। रमेश मस्ताना का बीते दिन सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।

डीसी किरण बुजुर्गों संग मनाई दीपावली

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। दीपावली के अवसर पर उपायुक्त किरण भड़ाना ने मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित 'अपना घर' वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों के साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं। उन्होंने बुजुर्गों को मिठाई, फल और उपहार वितरित किए तथा उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान उपायुक्त ने बुजुर्गों से बातचीत कर उनके अनुभव सुने। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनका सम्मान और देखभाल करना हम सभी का नैतिक दायित्व है। उन्होंने समाज से अपील की कि कोई भी बुजुर्ग उपेक्षा और अकेलेपन का शिकार न हो। मानव सेवा ट्रस्ट के संस्थापक एवं अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकाश चंद बंसल ने बताया कि वर्ष 2020 से संचालित वृद्धाश्रम में अब तक 106 बुजुर्गों को आश्रय दिया गया है। वर्तमान में यहां 25 बुजुर्ग रह रहे हैं। इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल, जिला कार्यक्रम अधिकारी नरेंद्र सिंह, रेडक्रॉस सचिव अमित कुमार सहित ट्रस्ट के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

19 प्रशिक्षणार्थियों को वितरित की सिलाई मशीनें किसानों को सरकारी योजनाओं की दी जानकारी



भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना प्रबंधन इकाई मंडी द्वारा उठाऊ सिंचाई योजना कसारला में एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें लगभग 60 किसानों ने भाग लिया। खंड परियोजना प्रबंधक डॉ. राजेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने किसानों को कृषि, पशुपालन और बैंकिंग से संबंधित जानकारी दी। शिविर में किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, उनकी पात्रता और मिलने वाले लाभों से अवगत करवाया गया। अधिकारियों ने किसानों से कृषि उत्पादकता बढ़ाने और आजीविका के अवसर बेहतर बनाने के लिए इन योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। इस अवसर पर परियोजना के सेवा क्षेत्र घटक के तहत 2025-26 में साढ़े चार महीने का सिलाई प्रशिक्षण पूरा करने वाले 19 प्रशिक्षणार्थियों को सिलाई मशीनें वितरित की गईं। इसका उद्देश्य स्वरोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में पशु चिकित्सक डॉ. नेहा, कृषि विभाग के विशेषज्ञ डॉ. विजय कुमार, सहकारी बैंक के अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि तथा विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

आयुष अस्पताल में मनाया भगवान धनवंतरी दिवस

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। धनतेरस के पावन अवसर पर आयुर्वेद के जनक भगवान धनवंतरी का दिवस श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन स्थित आयुष अस्पताल में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया। इसमें आयुष विभाग के चिकित्सकों सहित अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया और भगवान धनवंतरी से सभी के उत्तम स्वास्थ्य एवं सुख-समृद्धि की कामना की। जिला आयुष अधिकारी सिरमौर डॉ. जसप्रीत कौर ने बताया कि भगवान धनवंतरी को प्राचीन काल से ही आयुर्वेद और आरोग्य का देवता माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि पहले इस दिन को आयुष दिवस के रूप में भी मनाया जाता था, लेकिन अब आयुष दिवस सितंबर माह में मनाया जाता है उन्होंने कहा कि धनवंतरी दिवस के अवसर पर आयुष अस्पताल में विधिवत पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान भगवान धनवंतरी से समाज के प्रत्येक व्यक्ति के स्वस्थ एवं निरोगी जीवन की कामना की गई। उन्होंने कामना की कि भगवान धनवंतरी सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें तथा पूरा समाज स्वस्थ और खुशहाल रहे।

हमीरपुर में त्योहारों पर मिलावटखोरों पर शिकंजा

फूड सेफ्टी विभाग की 15-20 दुकानों पर छापेमारी, 6 सैंपल लैब भेजे, लोगों को मिलेगा शुद्ध और सुरक्षित भोजन

भारतेन्दु संवाददाता, हमारीपुर। धनतेरस और दिवाली के त्योहारी सीजन में बाजार में मिठाइयों और फास्ट फूड की मांग अचानक बढ़ जाती है। इसी का फायदा उठाकर कुछ दुकानदार मिलावटी, घटिया और अस्वच्छ खाद्य पदार्थ बेचने लगते हैं। इसको रोकने के लिए फूड सेफ्टी विभाग हमीरपुर ने शहर में बड़ा निरीक्षण अभियान चलाया।



विभाग की टीम ने हमीरपुर शहर की मिठाई और फास्ट फूड की करीब 15 से 20 दुकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान दुकानों में साफ-सफाई, मिठाइयों की गुणवत्ता, कच्चा माल रखने का तरीका, एक्सपायरी सामान और कर्मचारियों की हाइजीन की बारीकी से जांच की गई। निरीक्षण के दौरान टीम को कई जगहों पर संदेह हुआ, जिसके बाद कुल 6 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। इनमें मोमोज, बर्फी, अलसी लड्डू, मलाई बर्फी, कलाकंद और लड्डू शामिल हैं। सभी सैंपलों को सील करके जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। लैब से रिपोर्ट आने के बाद अगर किसी सैंपल में मिलावट या मानकों से छेड़छाड़ पाई गई तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मौजूद फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉ. अभिषेक ठाकुर ने सभी मिठाई विक्रेताओं को साफ निर्देश दिए कि मिठाइयों में केवल फूड ग्रेड परमिटेड कलर का ही इस्तेमाल करें, वो भी बहुत ही कम मात्रा में। उन्होंने कहा कि कई दुकानदार मिठाइयों को आकर्षक दिखाने के लिए ज्यादा कलर डाल देते हैं, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। फास्ट फूड की दुकानों पर विशेष ध्यान दिया गया। डॉ. ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि तैयार खाने में किसी भी तरह का फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मोमोज, चाउमीन, मंचूरियन जैसे आइटमों में कलर डालना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खाने में इस्तेमाल होने वाला मोनो सोडियम ग्लूटामेट (अजीनोमोटो) भी सिर्फ फूड ग्रेड वाला हो और बहुत कम मात्रा में डाला जाए। ज्यादा अजीनोमोटो से सिरदर्द, उल्टी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

ग्लव्ज, मास्क और हेडगियर अनिवार्य

निरीक्षण के दौरान कई दुकानों पर काम करने वाले लोग बिना ग्लव्ज और मास्क के खाना परोसते पाए गए। इस पर विभाग ने नाराजगी जताई। सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों को निर्देश दिया गया कि खाना बनाते और परोसते समय ग्लव्ज, मास्क और हेडगियर पहनना अनिवार्य है। बिना इसके खाना परोसते पाए जाने पर चालान किया जाएगा।

दिवाली तक जारी रहेगा अभियान

असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी मनजीत सिंह ने बताया कि यह अभियान सिर्फ एक दिन का नहीं है। त्योहारी सीजन के अंत तक इस तरह के निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि विभाग का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि लोगों को अच्छा, सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध करवाना है। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर उन्हें किसी दुकान पर मिलावटी या घटिया खाना बिकता दिखे तो तुरंत विभाग को सूचित करें। शिकायत करने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

लोगों ने की सराहना

विभाग की इस कार्रवाई से शहर के लोगों में खुशी है। लोगों का कहना है कि त्योहारों के समय ऐसी जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी समय मिलावट सबसे ज्यादा होती है। दुकानदारों ने भी विभाग को सहयोग करने का आश्वासन दिया है।

मनाली के अलेऊ गांव में दो लोगों के शव मिलने से सनसनी

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। मनाली थाना क्षेत्र के अलेऊ गांव में एक महिला और पुरुष के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान 44 वर्षीय महिला और 46 वर्षीय पुरुष के रूप में हुई है। महिला का शव घर के पीछे चेरी के पेड़ के नीचे, जबकि पुरुष का शव कमरे में गद्दे पर पड़ा मिला। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत चचोगा के उपप्रधान ने पुलिस को महिला द्वारा फांसी लगाने की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को महिला के पास पेड़ से बंधी रस्सी मिली। जांच के दौरान घर के कमरे में एक अन्य व्यक्ति का शव भी बरामद हुआ। परिजनों ने पुलिस को बताया कि परिवार के सभी सदस्य सगाई समारोह में शामिल होने कटराईं गए थे। शाम करीब 7:45 बजे घर लौटने पर दोनों मृत मिले। परिजनों ने किसी तरह का संदेह जाहिर नहीं किया है। पुलिस ने घटनास्थल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर साक्ष्य जुटाए तथा दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मनाली भेज दिए। शनिवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस के अनुसार मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। मामले की जांच जारी है।

झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई सुक्खू सरकार में विकास कार्य ठप : पूर्ण चंद ठाकुर



भारतेन्दु संवाददाता, जोगिंद्रनगर। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूर्ण चंद ठाकुर ने चौहार घाटी की विभिन्न पंचायतों का दो दिवसीय दौरा कर जनसभाओं को संबोधित किया तथा लोगों की समस्याएं सुनीं। पांच नवंबर को उन्होंने खलैहल, बरोट और लपास पंचायतों में लोगों से मुलाकात की, जबकि छह नवंबर को बरधाण, लटराण और धमच्याण पंचायतों में जनसभाएं कीं। इस दौरान विधायक ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई सुक्खू सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य ठप पड़े हैं।

महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी पूरी नहीं हुई और कई महत्वपूर्ण संस्थान बंद कर दिए गए। उन्होंने हिमकेयर योजना बंद करने, बेरोजगारी और विधायक निधि में कटौती को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की मांग पर क्षेत्र के जरूरी विकास कार्यों के लिए चरणबद्ध तरीके से धनराशि उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा बड़े बहुमत से सत्ता में लौटेगी। दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने विधायक का टोपी और मफलर पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर पधर मंडल भाजपा अध्यक्ष इंद्र सिंह ठाकुर, पंचायत समिति अध्यक्ष सुनीता ठाकुर, जिला परिषद सदस्य रोशन लाल ठाकुर सहित विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि एवं भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

दीपावली पर 24 घंटे अलर्ट रहेगा अग्निशमन नियंत्रण कक्ष

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। दीपावली के दौरान आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन विभाग और होमगार्ड्स ने विशेष प्रबंध किए हैं। होमगार्ड्स की दसवीं वाहिनी हमीरपुर के कमांडेंट विनय कुमार ने बताया कि जिला मुख्यालय में 24 घंटे सक्रिय रहने वाला अग्निशमन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसके अलावा उपमंडल स्तर पर भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि दीपावली पर दीये व मोमबत्तियां ज्वलनशील वस्तुओं से दूर सुरक्षित स्थान पर जलाएं। पटाखे खुले स्थान पर ही चलाएं और आसपास पानी की बाल्टी जरूर रखें। बच्चों को पटाखों से दूर रखें तथा आतिशबाजी के दौरान सूती कपड़े पहनें। उन्होंने बिजली की सजावटी लाइटों के लिए नंगी तारों का प्रयोग न करने और कनेक्शन प्रशिक्षित इलेक्ट्रिशियन से करवाने की सलाह दी। उन्होंने सभी जिलावासियों से सावधानी बरतते हुए सुरक्षित दीपावली मनाने का आग्रह किया।

कुल्लू में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन मामलों में पांच आरोपी काबू

धनेश गौतम, भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। जिला कुल्लू में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 24.39 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) और 56 ग्राम अफीम बरामद की है।



पुलिस ने सभी मामलों में मादक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) के तहत केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पहले मामले में 2 नवंबर 2026 को पुलिस थाना मनाली की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सियाल स्थित एक निजी होटल में दबिश दी। इस दौरान तलाशी लेने पर पंजाब के जिला लुधियाना निवासी 36, 25 और 20 वर्षीय तीन युवकों के कब्जे से 24.100 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुआ। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ पुलिस थाना मनाली में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया है।

दूसरे मामले में 4 नवंबर को जिला डिटेक्शन सेल कुल्लू की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जिया पुल फ्लाईओवर के नीचे आरके शॉल इंडस्ट्री के समीप पार्वती नदी किनारे बैठे एक युवक की तलाशी ली। इस दौरान हाथीथान, भुंतर निवासी 35 वर्षीय युवक के कब्जे से 5.29 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई। पुलिस थाना भुंतर में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं, तीसरे मामले में 4 नवंबर को पुलिस थाना बंजार की टीम ने पुराने बस अड्डे के समीप यातायात जांच के दौरान एक वाहन को रोका।

वाहन की तलाशी लेने पर चालक के कब्जे से 56 ग्राम अफीम बरामद हुई। आरोपी की पहचान 36 वर्षीय निवासी गांव जल्ली, डाकघर नित्थर, जिला कुल्लू के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत मामला दर्ज किया है। जिला पुलिस की इन कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान जारी है। पुलिस सभी मामलों में आगे की जांच कर रही है।

लंबे अंतराल के बाद फिर दौड़ी सांफिया की 'थैरेपी ऑन व्हील्स', गांव-गांव में बच्चों को मिलेंगी सेवाएं

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। दिव्यांग व विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनके घर-द्वार पर पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में सांफिया फाउंडेशन की महत्वपूर्ण पहल 'थैरेपी ऑन व्हील्स' एक बार फिर शुरू हो गई है। कुछ आधिकारिक कारणों से लंबे समय से बंद पड़ी इस सेवा के दोबारा शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और उनके अभिभावकों ने राहत की सांस ली है।



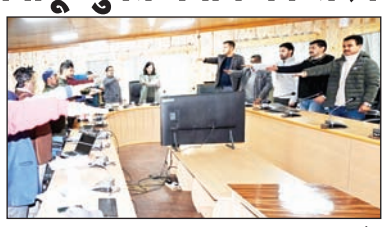
सेवा में लंबे समय तक व्यवधान रहने के कारण कई अभिभावक अपने बच्चों की नियमित थैरेपी को लेकर चिंतित थे। दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए बच्चों को थैरेपी केंद्रों तक ले जाना भी चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में इस परियोजना की पुनः शुरुआत से जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। यह परियोजना इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के सहयोग से संचालित की जा रही है। इसके तहत सांफिया फाउंडेशन की विशेषज्ञ टीम गांव-गांव पहुंचकर बच्चों को निशुल्क फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और विशेष शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। इसका उद्देश्य भौगोलिक दूरी और आर्थिक कठिनाइयों के कारण थैरेपी से वंचित रहने वाले बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पहुंचाना है। सांफिया फाउंडेशन के संचालन प्रमुख बीजू हिमदल ने कहा कि 'थैरेपी ऑन व्हील्स' केवल एक वाहन या सेवा नहीं, बल्कि जरूरतमंद बच्चों और उनके परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है। उन्होंने कहा कि संस्था का प्रयास है कि कोई भी बच्चा दूरी या आर्थिक परिस्थितियों के कारण आवश्यक थैरेपी से वंचित न रहे। टीम गांव-गांव पहुंचकर नियमित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस परियोजना को दोबारा शुरू करने में सहयोग के लिए सांफिया फाउंडेशन की टीम और अभिभावकों ने आईआरईडीए, नई दिल्ली का आभार जताया। फाउंडेशन दिव्यांगजनों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुलभ एवं समावेशी पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। 'थैरेपी ऑन व्हील्स' की पुनः शुरुआत इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

यूपीएससी-एचपीपीएससी की मुफ्त कोचिंग के लिए 20 नवंबर तक करें आवेदन

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला स्थित डॉ. अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में यूपीएससी और एचपीपीएससी की ग्रुप-ए एवं ग्रुप-बी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक वर्षीय निशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए 100 निःशुल्क और 25 सशुल्क सीटें उपलब्ध हैं। पात्रता के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक, आयु 21 से 37 वर्ष तथा शैक्षणिक अंकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत होना जरूरी है। चयनित विद्यार्थियों को 4,000 रुपए मासिक छात्रवृत्ति तथा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर साक्षात्कार की तैयारी के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2026 है। इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cuhimachal.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

लाहौल-स्पीति जिले में सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने का लक्ष्य

भारतेन्दु संवादाता, केलांग। जिला लाहौल-स्पीति में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक उपायुक्त निवेदिता नेगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई।



बैठक का संचालन मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमन सिंह ठाकुर ने किया। बैठक में बताया गया कि 20 अक्तूबर से 26 दिसंबर 2026 तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य बच्चों एवं युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाना और जिले में तंबाकू मुक्त वातावरण तैयार करना है। इसके तहत जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को शत-प्रतिशत तंबाकू मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपायुक्त नेगी ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सभी विभागों और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने और निर्धारित समय में अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। अभियान के तहत कोटपा अधिनियम का सख्ती से पालन करवाने के लिए जिला एवं खंड स्तर पर उड़नदस्तों द्वारा नियमित निरीक्षण और कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पंचायतों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी से गांवों को तंबाकू मुक्त बनाने के प्रयास होंगे। स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। डीसी ने बच्चों व किशोरों को कम उम्र में तंबाकू की लत से बचाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि समय रहते रोकथाम करना स्वस्थ भविष्य के लिए जरूरी है।

मंडी में तंबाकूमुक्त युवा अभियान 4.0 का शुभारंभ, 60 दिन चलेगा जागरूकता अभियान



भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। डीसी अपूर्व देवगन ने शुक्रवार को सेरी मंच मंडी से 60 दिवसीय तंबाकूमुक्त युवा अभियान 4.0 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान 26 दिसंबर, 2026 तक जिलेभर में चलाया जाएगा।

डीसी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य युवाओं को तंबाकू एवं निकोटीन की लत से बचाना तथा शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों को तंबाकूमुक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थानों की बाहरी सीमा से 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा एवं खाद्य सुरक्षा विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष मंडी जिले के 1,049 शिक्षण संस्थानों और 68 गांवों को तंबाकूमुक्त घोषित किया गया था। इस वर्ष सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकूमुक्त बनाने तथा तंबाकूमुक्त गांवों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के दौरान रैलियों, नुक्कड़ नाटकों, प्रभात फेरियों, मैराथन और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उपायुक्त ने समाज, अभिभावकों और शिक्षकों से अभियान में सहयोग की अपील की। इस अवसर पर सीएमओ डॉ. अशोक चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और आईटीआई के विद्यार्थी उपस्थित रहे।

पशुपालकों को रोगों की रोकथाम और उचित पोषण की दी जानकारी

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। अभिलाषी विश्वविद्यालय चैल चौक के स्कूल ऑफ वेटरनरी साइंसेज द्वारा ग्राम पंचायत चच्योट में पशु चिकित्सा एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कुल 59 पशुओं का उपचार किया गया तथा पशुपालकों को पशुओं के स्वास्थ्य, रोगों की रोकथाम और उचित प्रबंधन की जानकारी दी गई। शिविर में पशु चिकित्सक डॉ. रईस, डॉ. फरहान, डॉ. शगुन और डॉ. प्रिया ने सेवाएं प्रदान कीं। डॉ. रईस एवं डॉ. फरहान ने मैस्टाइटिस, मस्से और अन्य रोगों का उपचार किया। वहीं, डॉ. शगुन ने प्रजनन संबंधी समस्याओं का उपचार कर पशुपालकों को जागरूक किया। डॉ. प्रिया ने संतुलित आहार, पशु पोषण और चारा प्रबंधन की जानकारी दी। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. आरके अभिलाषी, प्रति-कुलाधिपति डॉ. एलके अभिलाषी, कुलपति प्रो. एचके चौधरी और डीन डॉ. आरके असरानी ने टीम को बधाई देते हुए भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

30 साल बाद भी बैंक पेंशनरों को नहीं मिला पेंशन रिविजन का लाभ, महंगाई भत्ते में भेदभाव का आरोप

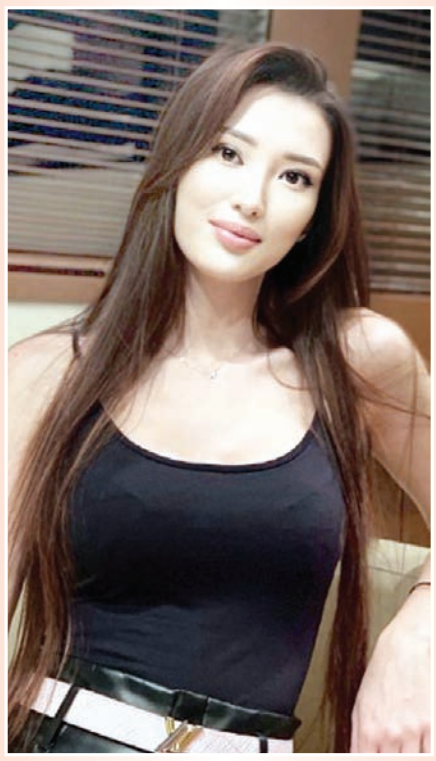
भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज एसोसिएशन रजिस्टर्ड के मंडी सर्कल की आम सभा शुक्रवार को भुंतर स्थित होटल रॉयल मेंशन में आयोजित हुई।



हिमाचल चेयरमैन व राष्ट्रीय वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव प्रेजिडेंट जेपी शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से 150 से अधिक बैंक पेंशनरों ने भाग लिया। इस दौरान पेंशन संशोधन, महंगाई भत्ता, स्पेशल एलाउंस और मेडिकल सुविधाओं सहित विभिन्न लंबित मांगों पर चर्चा की गई। बैठक में पेंशनरों ने रोष जताते हुए कहा कि 30 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद बैंक कर्मचारियों की पेंशन का रिविजन और अपडेशन नहीं हुआ है। उनका आरोप था कि एक नवंबर 2022 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अन्य वर्गों की तुलना में कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। उन्होंने मांग की कि बैंक पेंशन और भत्तों का संशोधन रिजर्व बैंक के पैटर्न पर किया जाए। पेंशनरों ने स्पेशल एलाउंस को पेंशन में शामिल न किए जाने पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि एक नवंबर 2012 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा, जिससे मासिक पेंशन

सबीना ऑल्तिनबिकोवा की खूबसूरत अदा

सबीना ऑल्तिनबिकोवा कजाकिस्तान की एक प्रसिद्ध पेशेवर वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, 2014 में अपनी असाधारण सुंदरता के कारण वह सोशल मीडिया पर रातों-रात वायरल हो गई थीं और चर्चा में आ गई थीं, जिसे लेकर कोच ने उनके खेल पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही थी।



तन्वी ने यूथ ओलंपिक में रचा इतिहास

बैडमिंटन में पहली भारतीय महिला रजत विजेता बनीं, चमकाया देश का नाम

एजेंसी, डकार (सेनेगल)

भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी तान्वी पत्री ने यूथ ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया है। महिला एकल वर्ग के फाइनल में उन्हें चीन की खिलाड़ी झांग यी शिन के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस उपलब्धि के साथ उन्होंने भारतीय बैडमिंटन के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। 15 वर्षीय तान्वी इस प्रतियोगिता में महिला एकल का रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। फाइनल मुकाबला सेनेगल के डकार में खेला गया, जहां दोनों खिलाड़ियों के बीच करीब एक घंटे 22 मिनट तक कड़ा संघर्ष देखने को मिला। झांग ने तान्वी को 15-21, 21-13, 24-26 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।

मुकाबले की शुरुआत में तान्वी को लय हासिल करने में थोड़ा समय लगा। वह एक समय 3-5 से पीछे चल रही थीं, लेकिन इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी करते हुए लगातार अंक जुटाए और 10-5 की बढ़त बना ली। तान्वी ने अपने बेहतरीन खेल, सटीक शॉट और नेट पर नियंत्रण के दम पर पहला गेम 21-15 से जीत लिया। इस गेम को अपने नाम करने में उन्हें 25 मिनट लगे। पहले गेम में जीत के बाद उनसे खिताबी मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद बढ़ गई थी।



फाइनल में कड़े संघर्ष के बाद तान्वी को रजत

दूसरे गेम में भी तान्वी ने अच्छी शुरुआत की और एक समय 4-0 की बढ़त हासिल कर ली। हालांकि कोर्ट पर हवा के बहाव के कारण उनके शॉट्स का नियंत्रण प्रभावित हुआ। इसका फायदा उठाते हुए झांग ने धीरे-धीरे मुकाबले में वापसी की।

निर्णायक गेम में आखिरी तक चला संघर्ष

तीसरे और निर्णायक गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला। झांग ने क्रॉस-कोर्ट ड्रॉप शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए शुरुआत में बढ़त बना ली। एक समय वह 19-10 से आगे थीं। इसके बाद तान्वी ने हार नहीं मानी और लगातार अंक हासिल करते हुए अंतर कम किया। उन्होंने झांग के पांच मैच प्वाइंट बचाए और खुद भी तीन बार स्वर्ण पदक जीतने के करीब पहुंचीं। हालांकि दबाव के क्षणों में झांग ने बेहतर खेल दिखाया और 26-24 से निर्णायक गेम जीतकर स्वर्ण पदक हासिल कर लिया।

यूथ ओलंपिक में भारत की तीसरी बैडमिंटन पदक विजेता

मध्यांतर के बाद चीनी खिलाड़ी ने अपने खेल में तेजी दिखाई और लगातार अंक हासिल किए। उन्होंने 21-13 से दूसरा गेम जीतकर मुकाबले को एक-एक से बराबर कर दिया। तान्वी से पहले यूथ ओलंपिक के व्यक्तिगत बैडमिंटन मुकाबलों में दो भारतीय खिलाड़ी रजत पदक जीत चुके हैं। एचएस प्रणय ने 2010 में और लक्ष्य सेन ने 2018 में पुरुष एकल वर्ग में रजत पदक हासिल किया था। लक्ष्य सेन ने 2018 में मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीता था। आदित्य जोशी 2014 में सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। अब तान्वी ने महिला एकल वर्ग में रजत पदक जीतकर भारत की उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ दी है। तान्वी इससे पहले अंडर-17 और अंडर-15 एशियाई चैंपियनशिप के दोनों खिताब जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दे चुकी हैं। कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली यह सफलता उनकी मेहनत और तैयारी का परिणाम है। फाइनल में हार के बावजूद उनका प्रदर्शन भारतीय बैडमिंटन के लिए उत्साहजनक है।

माइकल हसी बने ऑस्ट्रेलियाई टीम के कोचिंग कंसल्टेंट

एजेंसी, मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज माइकल हसी को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कोचिंग सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह वर्ष 2027 में होने वाली एशेज सीरीज और वनडे विश्व कप की तैयारियों में टीम की मदद करेंगे। इसके अलावा 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक और ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए टीम की रणनीति तैयार करने में भी उनकी अहम भूमिका रहेगी। हसी का अनुभव टीम को बड़े टूर्नामेंटों के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद करेगा। हसी की नई जिम्मेदारी इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टी-20 सीरीज से शुरू होगी। इसके बाद वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पर्थ में होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारियों में मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड के साथ काम करेंगे। टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि उनके अनुभव और बल्लेबाजी की समझ से खिलाड़ियों को महत्वपूर्ण मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। हसी इससे पहले भी ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ कुछ समय के लिए बल्लेबाजी सलाहकार की भूमिका निभा चुके हैं। हालांकि, कमेंट्री और अन्य क्रिकेट संबंधी जिम्मेदारियों के कारण वह लंबे समय तक टीम से नहीं जुड़ पाए थे। इस वर्ष न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने उन्हें इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कोचिंग स्टाफ में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन हसी ने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ काम करने को प्राथमिकता दी।



स्पोर्ट्स विंडो

कॉन्वे भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर, ट्रेनिंग के दौरान सिर में लगी चोट

एजेंसी, वेलिंगटन। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के बीच न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है। टीम के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे सिर में चोट (कन्कशन) के कारण बाकी बचे चार मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। मंगलवार को पहले वनडे से पहले अभ्यास सत्र के दौरान उनके सिर में चोट लगी थी। इसके बाद उन्हें ऑकलैंड के मेडिकल सेंटर के आपातकालीन विभाग में ले जाया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने गुरुवार को कॉनवे के सीरीज से बाहर होने की पुष्टि की। उनकी जगह बाएं हाथ के बल्लेबाज निक केली को टीम में शामिल किया गया है। केली को पहले ही सीरीज के चौथे और पांचवें वनडे के लिए चुना गया था। अब वह बाकी मुकाबलों के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। इस बीच तेज गेंदबाज मैट हेनरी की कन्कशन जांच सामान्य रही और उन्हें खेलने की मंजूरी मिल गई है।



निक केली को टीम में जगह

क्रिस लिन की सजा खत्म, कोकीन इस्तेमाल के कारण लगा था बैन

एजेंसी, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर क्रिस लिन को कोकीन सेवन मामले में बड़ी राहत मिली है। इंग्लैंड क्रिकेट नियामक ने उनकी तीन महीने की सजा घटाकर एक महीना कर दी है। 36 वर्षीय लिन 18 जुलाई को इंग्लैंड में टी-20 ब्लास्ट फाइनल्स डे के दौरान हुए डोपिंग परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए थे। जांच में उनके नमूने में कोकीन का मेटाबोलाइट मिला था। लिन ने नियमों के उल्लंघन की बात स्वीकार कर ली थी। जांच में यह भी माना गया कि उन्होंने प्रतियोगिता से बाहर कोकीन का इस्तेमाल किया था और इसका उनके खेल प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं था। रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम पूरा करने के बाद उनकी सजा घटाई गई। एक महीने का निलंबन पूरा होने के बाद अब वह खेलने के लिए स्वतंत्र हैं।

राजस्थान और लखनऊ के बीच तीन से चार खिलाड़ियों की ट्रेड की तैयारी

एजेंसी, नई दिल्ली। आईपीएल नीलामी से पहले राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच बड़ी ट्रेड डील होने की संभावना है। दोनों फ्रेंचाइज़ी तीन से चार खिलाड़ियों की अदला-बदली को लेकर बातचीत कर रही हैं। राजस्थान की नजर लखनऊ के एक तेज गेंदबाज पर है, जबकि लखनऊ बदले में राजस्थान के एक या दो बल्लेबाजों और ऑलराउंडर को टीम में शामिल करना चाहता है। इस ट्रेड में लखनऊ का एक स्पिनर भी शामिल हो सकता है। हालांकि, दोनों टीमों ने अभी खिलाड़ियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। सूत्रों के मुताबिक, ट्रेड को लेकर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है और डील को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है।

राजस्थान को पेसर की जरूरत, लखनऊ ऑलराउंडर की तलाश में

सहवाग के बेटे आर्यवीर ने अंडर-19 एशिया कप में जड़ा अर्धशतक

एजेंसी, अल अमेरात। अंडर-19 एशिया कप में भारत ने नेपाल को 10 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल की टीम 42.3 ओवर में 128 रन पर सिमट गई। दर्शन सोनार ने 43 और विकेटकीपर आशीष लुहार ने 29 रन बनाए। भारत की ओर से ईशान सूद ने 18 रन देकर तीन विकेट झटके, जबकि अर्जुन राजपूत ने भी तीन विकेट हासिल किए। यशवीर गौर को दो सफलताएं मिलीं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने बिना विकेट गंवाए 19.1 ओवर में जीत हासिल कर ली। वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने 52 गेंदों में सात चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 70 रन बनाए। कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने 63 गेंदों में नाबाद 53 रन का योगदान दिया। दोनों के बीच 129 रन की अटूट साझेदारी हुई। ईशान सूद को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।



भारत-न्यूजीलैंड दूसरे वनडे पर बारिश का खतरा, मैच धुलने की आशंका

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे आज वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। हालांकि मुकाबले पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को यहां 60 प्रतिशत तक बारिश की संभावना है। बारिश के कारण भारतीय टीम ने शुक्रवार का अभ्यास सत्र रद्द कर दिया, जबकि न्यूजीलैंड ने इंडोर अभ्यास किया। पांच मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है।

पीएम मोदी से मिले पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव

प्रधानमंत्री को दिखाया टी-20 विश्व कप का स्वर्ण पदक

एजेंसी, नई दिल्ली

पूर्व भारतीय टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान वह अपने परिवार के साथ नई दिल्ली पहुंचे। उनकी पत्नी देविशा शेट्टी और बेटी रिद्धिमा भी उनके साथ मौजूद थीं। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने सूर्यकुमार के परिवार के साथ समय बिताया और बच्चों से भी बातचीत की। इस अवसर पर सूर्यकुमार ने 2026 टी-20 विश्व कप में भारत की खिताबी जीत का स्वर्ण पदक भी प्रधानमंत्री को दिखाया। सूर्यकुमार ने यह पदक अपने गले में पहना हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे हाथ में लेकर देखा। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा कीं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में लिखा कि दिवाली के माहौल में राम और सरयू का आगमन होने से इस वर्ष का त्योहार और भी पवित्र एवं दिव्य हो गया है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2026 टी-20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था।



टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शानदार रिकॉर्ड

सूर्यकुमार यादव ने अब तक 113 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 3272 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 36.35 और स्ट्राइक रेट 162.94 रहा है। उनके नाम चार शतक और 25 अर्धशतक दर्ज हैं। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 297 चौके और 179 छक्के लगाए हैं, जबकि 58 कैच भी पकड़े हैं।

विश्व कप जीतने के बाद टीम से हुए बाहर

2026 टी-20 विश्व कप जीतने के बाद उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। इसके बाद आयरलैंड और इंग्लैंड दौरों के लिए भी उन्हें भारतीय टी-20 टीम में जगह नहीं मिली। दी गई जानकारी के अनुसार, श्रेयस अय्यर को टीम का नया कप्तान बनाया गया। कप्तानी और टीम में जगह को लेकर हुए बदलावों के बीच विश्व कप विजेता सूर्यकुमार की प्रधानमंत्री से यह मुलाकात चर्चा में रही।

बांग्लादेश के ओपनर शदमान इस्लाम का टखना मुड़ा, मैच से बाहर होने का खतरा

बाकी मुकाबले में दस खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ सकता है

एजेंसी, ढाका। बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज शदमान इस्लाम वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन फील्डिंग करते समय चोटिल हो गए। उनका टखना मुड़ने के बाद उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। शदमान की चोट से बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यदि वह इस मुकाबले के बाकी हिस्से में नहीं खेल पाते हैं, तो टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरना पड़ सकता है। शदमान ने पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया था। ऐसे में उनकी अनुपस्थिति बांग्लादेश के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है।

शदमान दूसरे दिन के खेल के 78वें ओवर में चोटिल हुए। मेहदी हसन मिराज की गेंद पर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज अमीर जंगू ने फाइन लेग की दिशा में शॉट खेला। स्लिप में फील्डिंग कर रहे शदमान गेंद को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़े। गेंद तक पहुंचकर उसे उठाने की कोशिश के दौरान उनका पैर फिसल गया और गिरते समय टखना मुड़ गया। चोट लगने के बाद वह मैदान पर ही गिर पड़े। उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें स्ट्रेचर की मदद से मैदान से बाहर ले जाया गया। घटना के रीप्ले में आउटफील्ड पर ओस भी दिखाई दी, जिससे मैदान पर फिसलन होने की आशंका जताई गई।

इससे पहले वेस्टइंडीज ने दूसरे दिन अपनी पहली पारी चार विकेट पर 235 रन से आगे बढ़ाई। टीम ने बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान की बदौलत पहली पारी में 356 रन बनाए। केविन विकहम और अमीर जंगू ने चौथे विकेट के लिए 131 रन की अहम साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। विकहम ने 61 रन बनाए, जबकि जंगू ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 212 गेंदों पर 133 रन की पारी खेली। उनकी पारी में 13 चौके और दो छक्के शामिल रहे। जस्टिन ग्रीव्स ने भी 51 रन बनाकर टीम के स्कोर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जोशुआ बिशप ने 23 रन बनाए, जबकि जोमेल वॉरिकन 27 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 356 रन बनाने में सफल रही। बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 90 रन देकर छह विकेट हासिल किए। तस्कीन अहमद और मेहदी हसन मिराज ने दो-दो विकेट लिए।



शदमान की चोट से बांग्लादेश की बढ़ी मुश्किलें

ब्लिंकिट ने एंबुलेंस सेवा के लिए लागू किए नए शुल्क संबंधी नियम

सेवा के गैर-आपातकालीन उपयोग पर लगेगा 2500 रुपए शुल्क

एजेंसी, नई दिल्ली

क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट की एम्बुलेंस सेवा के नियमों में बदलाव किया गया है। कंपनी की मूल इकाई इटरनल के वाइस चेयरमैन और संस्थापक दीपिंदर गोयल ने नई शुल्क व्यवस्था की जानकारी दी है। इसके तहत गंभीर और आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की एम्बुलेंस सेवा पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेगी। हालांकि, गैर-आपातकालीन जरूरतों के लिए इस सेवा का इस्तेमाल करने पर अब 2500 रुपये का शुल्क देना होगा। कंपनी ने यह कदम एम्बुलेंस सेवा के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने और वास्तविक जरूरतमंद मरीजों तक समय पर सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया है।

दीपिंदर गोयल ने स्पष्ट किया कि ब्लिंकिट की एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आपात स्थिति में लोगों को तेजी से चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है। कई बार गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के दौरान अस्पताल पहुंचने में होने वाली देरी मरीज के लिए परेशानी बढ़ा सकती है।

ब्लिंकिट एम्बुलेंस सेवा के दुरुपयोग पर सख्ती

आपात स्थिति में मुफ्त रहेगी ब्लिंकिट एंबुलेंस सेवा

नई व्यवस्था के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बिना किसी वास्तविक आपातकालीन स्थिति के एम्बुलेंस सेवा का उपयोग करता है तो उससे 2500 रुपये शुल्क लिया जाएगा। कंपनी का मानना है कि इस व्यवस्था से गैर-जरूरी बुकिंग को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, एम्बुलेंस और चिकित्सा सहायता से जुड़े संसाधनों का इस्तेमाल उन लोगों के लिए सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिन्हें वास्तव में तत्काल मदद की आवश्यकता है। आपातकालीन सेवा को मुफ्त रखने से आर्थिक कारणों से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सहायता लेने में परेशानी नहीं होगी।



वीडियोकॉन के पूर्व प्रमोटर वेणुगोपाल धूत दिवालिया घोषित

एजेंसी, नई दिल्ली। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रमोटर और निदेशक वेणुगोपाल नंदलाल धूत को दिवालिया घोषित कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने पांच नवंबर को यह आदेश पारित किया। यह कार्रवाई 12,668 करोड़ रुपये के ऋण डिफॉल्ट और व्यक्तिगत ऋण चुकौती योजना विफल होने के बाद की गई है। एसबीआई ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को दी गई ऋण सुविधाओं के लिए धूत की व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की थी। बैंक ने फरवरी 2018 में इन गारंटियों को लागू किया था। धूत ने बकाया चुकाने के लिए सिलीगुड़ी में प्रस्तावित विकास परियोजना के माध्यम से 36 महीनों में 600 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, लेनदारों ने इसे स्वीकार नहीं किया।



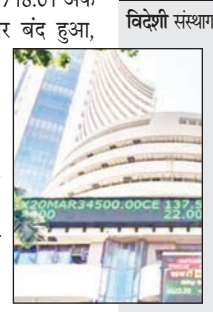
12,668 करोड़ के लोन डिफॉल्ट पर एनसीएलटी का फैसला

सेंसेक्स में 1718 अंकों की छलांग, निफ्टी भी 494 अंक चढ़ा

एजेंसी, मुंबई

भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार सातवें दिन तेजी दर्ज की गई। धनतेरस के दिन सेंसेक्स 1718.01 अंक उछलकर 81,028.02 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 493.75 अंक बढ़कर 25,030.35 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स करीब आठ महीने बाद 80 हजार के पार बंद हुआ है। इससे पहले पांच मार्च 2026 को इसने यह स्तर छुआ था। पिछले सात कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स 7,781.99 अंक और निफ्टी 2,331.5 अंक चढ़ चुका है। वैश्विक बाजारों में गिरावट के बावजूद विदेशी निवेश और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से घरेलू बाजार को समर्थन मिला। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में सर्वाधिक 6.15 फीसदी की बढ़त रही।

विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले सात दिनों में भारतीय शेयर बाजार में 32,210 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसके अलावा सितंबर तिमाही के अच्छे नतीजों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। रिलायंस, इंफोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी ने भी बाजार को सहारा दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक, बेहतर कारोबारी नतीजों, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में संभावित बदलाव की उम्मीद से विदेशी निवेशकों का रुख भारतीय बाजार के प्रति सकारात्मक हुआ है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के डॉ. वीके विजयकुमार का मानना है कि बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के शेयरों में आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है।



विदेशी निवेशकों ने बाजार में लगाए 32 हजार करोड़

एनबीसीसी का मुनाफा 34 प्रतिशत बढ़कर 210 करोड़ रुपए पहुंचा

एजेंसी, नई दिल्ली

सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी एनबीसीसी लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शानदार वित्तीय प्रदर्शन करते हुए अपने शुद्ध लाभ में 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी को इस अवधि में समेकित आधार पर 210 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह आंकड़ा इससे कम था। कंपनी के बेहतर प्रदर्शन में परिचालन आय में हुई बढ़ोतरी और विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं से प्राप्त कार्यादेशों की अहम भूमिका रही है।

एनबीसीसी के निदेशक मंडल ने चालू वित्त वर्ष के लिए 25 पैसे प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। इसके लिए 11 नवंबर को शेयरधारिता रखने वाले निवेशकों को पात्र माना जाएगा। कंपनी ने बताया कि तिमाही के दौरान उसकी समेकित परिचालन आय में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 17 प्रतिशत बढ़कर 3,396 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। इससे कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों में विस्तार और परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का संकेत मिलता है।

एनबीसीसी को 1000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट

कंपनी ने तिमाही के दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए बड़े कार्यादेश भी हासिल किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से उसे आंध्र प्रदेश के अमरावती में कार्यालय और आवासीय परिसरों के निर्माण के लिए करीब 780 करोड़ रुपये का परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य मिला है। इसके अतिरिक्त भारत-तिब्बत सीमा पुलिस से लद्दाख में सीमा पर स्थित 28 चौकियों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 235 करोड़ रुपये का ठेका प्राप्त हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कंपनी ने अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। एनबीसीसी ने सेशेल्स सरकार के साथ 1,008 आवासीय इकाइयों वाली इल ऑरोर आवासीय परियोजना के लिए समझौता किया है।

विस्तार इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से मिले टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन

इवेको अधिग्रहण से टाटा मोटर्स को मिली नई ताकत

एजेंसी, नई दिल्ली

भारतीय उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने रोम स्थित पलाज्जो चिगी में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। इस उच्चस्तरीय बैठक में टाटा मोटर्स द्वारा इतालवी वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी इवेको समूह के अधिग्रहण और भारत तथा इटली के बीच बढ़ते रणनीतिक, औद्योगिक एवं आर्थिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा हुई। टाटा मोटर्स ने हाल ही में 3.43 अरब यूरो का भुगतान कर इवेको में 89.42 प्रतिशत नियंत्रक हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। इस सौदे के बाद इवेको टाटा मोटर्स की अप्रत्यक्ष अनुषंगी कंपनी बन गई है। इसे टाटा मोटर्स के वैश्विक विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इससे पहले एन. चंद्रशेखरन ने इटली के टोरीनो स्थित इवेको मुख्यालय में आयोजित वैश्विक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अधिग्रहण प्रक्रिया में सहयोग और समर्थन देने के लिए इतालवी सरकार तथा प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इवेको समूह की जड़ें इटली में बेहद मजबूत हैं और यह यूरोप से लेकर लातिन अमेरिका तक एक प्रतिष्ठित ब्रांड तथा विश्वस्तरीय तकनीक के साथ अपनी पहचान बनाए हुए है।



21 अरब यूरो के संयुक्त राजस्व के साथ उतरेगा टाटा-इवेको समूह

टाटा और टोरीनो का पुराना नाता फिर चर्चा में

उन्होंने टोरीनो के साथ टाटा समूह के पुराने संबंधों का भी उल्लेख किया। चंद्रशेखरन ने बताया कि 1990 के दशक के अंत में टाटा की पहली स्वदेशी यात्री कार के डिजाइन के लिए भी टोरीनो के साथ संबंध स्थापित हुए थे। ऐसे में इवेको का अधिग्रहण दोनों पक्षों के बीच औद्योगिक सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत है।

130 से अधिक देशों में बढ़ेगा कारोबार

दोनों कंपनियों के संयुक्त बयान के अनुसार, उनके व्यापक बाजार पहुंच के कारण यूरोप, भारत, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका सहित 130 से अधिक देशों में कारोबार का विस्तार होगा।